

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

# आक्स

वर्ष : 22 | अंक : 22

16 से 31 अगस्त 2024

पृष्ठ : 48

मूल्य : 25 रु.



## आजादी के सही मायने की अब भी तलाश!

77 साल बाद भी जाति, धर्म, भाषा की  
बेड़ियां नहीं तोड़ पाया भारत

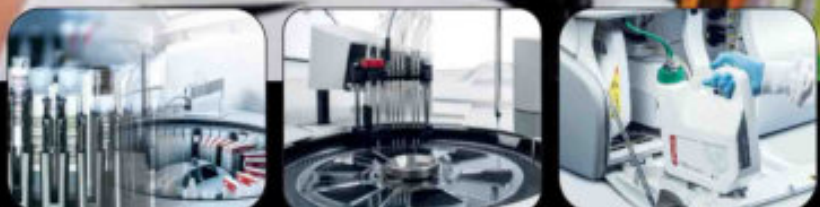
एक दिन के उल्लास पर भारी बेरोजगारी,  
महंगाई, अपराधों की बीमारी

# ANU SALES CORPORATION

HAPPY INDEPENDENCE DAY



## We Deal in Pathology & Medical Equipment



Address : M-179, Gautam Nagar,  
Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

☎ 9329556524, 9329556530 ✉ Email : [ascbhopal@gmail.com](mailto:ascbhopal@gmail.com)

## ● इस अंक में

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

पहल

8

सरकारी संपत्तियों  
का प्रबंधन...

मद्र में अनुपयोगी सरकारी संपत्तियों को बेचकर सरकारी खजाना भरने की जो परिपटी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की थी, मोहन सरकार उस पर अमल नहीं करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली...

डायरी

10-11

पानी पिलाने  
वाले...

मद्र में एक तरफ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं और सुशासन पर जोर दे रहे हैं। इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है।

लालफीताशाही

13

3 हजार करोड़  
की जमीन...

2 साल पहले चलाए गए ऑपरेशन भूमाफिया में जहां कई गृह निर्माण संस्थाओं की जमीनों पर पीड़ितों को भूखंडों के कब्जे दिलवाए गए, तो भूमाफिया के चंगुल में फंसी जमीनें भी छुड़वाई और कई रजिस्ट्रियों को शून्य करवाने के लिए कोर्ट में प्रकरण दायर...

भरशाही

16

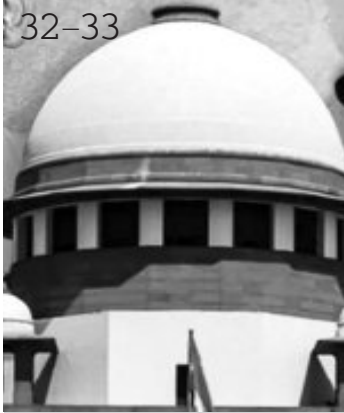
सीखो कमाओ  
योजना फेल

बेरोजगारी मद्र की सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए करीब 1 साल पहले मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की गई थी। योजना को लेकर बड़े-बड़े दावे भी किए गए थे, लेकिन एक साल के दौरान योजना को उतनी सफलता नहीं मिली, जितने दावे किए जा रहे थे।



विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत की आजादी की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई। हर तरफ उल्लास, जोश, जुनून और खुशी का माहौल था, लेकिन एक दिन के उल्लास पर बेरोजगारी, महंगाई और अपराधों की बीमारी सालभर भारी पड़ती है। विडंबना यह है कि आज भारत विकास की नई-नई ऊंचाईयां छू रहा है। शहर उन्नत और हाईटेक बन रहे हैं। लेकिन आज भी देश जाति, धर्म, भाषा और भेदभाव की बेड़ियों को तोड़ नहीं पाया है।

32-33



36



44



45



राजनीति

30-31

कांग्रेस की  
स्पेशल...

कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों की चुनावी तैयारी शुरू हो गई है। अगले चार महीने में चार राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ज्यादा संभावना है कि इस बार तीन राज्यों के चुनाव एक साथ हों। पहले महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव अलग-अलग होते थे। लेकिन...

महाराष्ट्र

35

साथ-साथ  
चुनाव...

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन भाजपा राज्य में चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। हालांकि पार्टी को चिंता राज्य में कार्यकर्ताओं के एक तबके की नाराजगी की सता रही है। साथ ही चुनाव से पहले पार्टी अपने लोगों को जोड़े रखने, और जोश...

बिहार

38

नीतीश के  
कारण...

लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा ने सम्राट चौधरी को बिहार प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया है। सम्राट चौधरी के हटाए जाने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख कारण हैं, वो उनका नीतीश कुमार से बेहतर तालमेल का न होना है। बिहार की...

6-7 अंदर की बात

41 महिला जगत

42 अध्यात्म

43 कहानी

44 खेल

45 फिल्म

46 व्यंग्य



# कर्ज का भार...बंगलों पर लाखों न्योछावर

कि सी कवि ने लिखा है...

लोकतंत्र के लोकशाही का, ऐसा न तुम दुरुपयोग करो  
कमा न सके चारू पैसे तो, फिजूलखर्ची से दूर रहो

लेकिन इसके विपरीत मप्र में यह देखने को मिल रहा है कि सरकार एक तरफ जहां कर्ज के बोझ तले दबी हुई है, तो वहीं मंत्रियों के बंगलों को चमकाने पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि मंत्रियों के बंगलों पर साल दर साल लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। आखिर मुफ्त का चंदन, घिस मेरे नंदन की तर्ज पर मंत्री अपने बंगलों पर लाखों रुपए खर्चा क्यों करवा रहे हैं। आलम यह है कि करीब सालभर पहले जिन बंगलों पर लाखों रुपए खर्च कर उन्हें सजाया और खंवाड़ा गया था, उन्हीं बंगलों को सजाने-खंवारने के लिए मंत्री 2-2 करोड़ रुपए तक खर्च कर रहे हैं। मंत्री अपने विभागों से बंगलों को सजवा रहे हैं। गौरतलब है कि करीब 8 महीने पहले जब नई सरकार का गठन हुआ था, तो पहले मंत्रियों ने मनचाहे बंगले के लिए जमकर मशक्कत की। जैसे-तैसे उन्हें बंगले आवंटित हुए तो उन्होंने सरकार से बंगले का रिनोवेशन कराने की मांग कर डाली। चिंताजनक बात यह है कि प्रदेश सरकार पर लगातार कर्ज का भार बढ़ रहा है। इस बात को मंत्री भलीभांति जानते हैं। उसके बाद भी मंत्रियों को अपने बंगले की सजा-सज्जा की चिंता बनी हुई है। इसलिए बिना सोचे-समझे मंत्री अपने बंगले पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि मंत्रियों के बंगलों के रिनोवेशन में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार का खेल भी खेला जाता है। विभागीय अधिकारियों के साथ ही इंजीनियर और ठेकेदार मिल-जुलकर रिनोवेशन का लंबा-चौड़ा मसौदा तैयार करते हैं, उसके बाद शुरू होता है मालामाल होने का खेल। बंगलों के रिनोवेशन में किस तरह की घपलेबाजी होती है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक-दो साल बाद ही बंगलों को फिर से मरम्मत की जरूरत आ पड़ती है। राज्य विधानसभा में बजट भाषण के बाद उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने स्वीकार किया है कि राज्य पर 3.75 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। प्रदेश के कई मंत्री और शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों के सरकारी बंगले करोड़ों रुपए के रिनोवेशन के लिए चर्चा में रहते हैं। जून में सरकार ने मंत्रियों के बंगलों में 18 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया था, क्योंकि कई मंत्री अपने बंगलों से नाब्रुश थे। उन्होंने अपने बंगलों के रिनोवेशन की मांग की थी। करीब एक महीने पहले मंत्रियों के बंगलों ने राष्ट्रीय सुब्रिग्यां भी बटोरी थीं। अब खवाल उठ रहा है कि अभी खर्चा हो रहा है या कि पहले की सरकारों में भी ऐसा खर्चा हुआ है। आपको बता दें जब कमलनाथ सरकार आई थी और जो मंत्री बने थे, तब भी खर्चा हुआ था। प्रदेश में जिसकी सरकार आती है, मंत्रियों की अगर मांग होती है कि बंगले की हालत जर्जर है और बंगले को बुधारा जाए, तो उन बंगलों की मरम्मत कराई जाती है। 3.75 लाख करोड़ के कर्ज में डूबी मप्र सरकार ने बजट में भी सरकारी बंगलों और आवाशों के रखरखाव के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सरकारी निधि से बंगलों के रिनोवेशन पर होने वाले खर्च के अतिरिक्त मंत्री अपने विभागों से भी अपने बंगलों को सजवाते-खंवारते हैं, जिस पर लाखों रुपए व्यय होते हैं। यह राशिया तो किसी मद्द से या फिर किसी योजना में कटौती कर जुटाई जाती है। बंगलों की सजा-सज्जा का यह खेल पिछले कुछ सालों से इस कदर बढ़ गया है कि इसमें भ्रष्टाचार की बू आने लगी है।

- राजेन्द्र आगाल

**अक्षर**

वर्ष 22, अंक 22, पृष्ठ-48, 16 से 31 अगस्त, 2024

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल  
सम्पादकीय कार्यालय :

प्लॉट नम्बर 150, जॉन-1 मनोरमा कॉम्प्लेक्स,

एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर

भोपाल- 462011 ( म.प्र. ),

फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788

email : akshmagazine@gmail.com

Website : www.akshnews.com

RNI NO. HIN/2002/8718 MPEPL/642/2021-23

**व्यो**

कोलकाता:- इंद्रकुमार, छत्तीसगढ़:- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी,

जयपुर:- आर.के. बिन्नानी, लखनऊ :- मधु आलोक निगम।

**प्रमुख संपादक**

भावना सक्सेना-भोपाल, जय मतानी-भोपाल, देवीराम-इंदौर,

हर्ष सक्सेना-भोपाल, दश दवे-इंदौर, संदीप वर्मा-इंदौर,

विपिन कंधारी-इंदौर, गौरव तिवारी-विदिशा,

ज्योत्सना यादव-गंजबासोदा, राजेश तिवारी-उज्जैन,

टोनी छाबड़ा-धार, आशीष नेमा-नरसिंहगढ़,

अनिल सोडानी-नई दिल्ली, हसमुख जैन-मुंबई,

इंद्र कुमार बिन्नानी-पुणे।

**प्रदेश संपादक**

पारस सरावगी ( इंदौर )

09329586555

नवीन रघुवंशी ( इंदौर )

09827227000 ( इंदौर )

धर्मद कथुरिया ( जबलपुर )

098276 18400

श्यामसिंह सिकरवार ( उज्जैन )

094259 85070

सुभाष सोमानी ( रतलाम )

089823 27267

मोहित बंसल ( विदिशा )

075666 71111

**देशीय कार्यालय**

नई दिल्ली : ई.सी. 294 माया इन्कॉर्पोरेट मायपुरी,

फोन : 9811017939

जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर

(राजस्थान) मोबाइल-09829 010331

रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर,

फोन : 0771 2282517

भिलाई : नेहरु भवन के सामने, सुपेला,

रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015

इंदौर : नवीन रघुवंशी, रघुवंशी कॉलोनी,

इंदौर, मो.-9827227000

देवास : जय सिंह, देवास

मो.-7000526104, 9907353976

स्वावाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटेर्स, प्लॉट नं. 150, जॉन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा कॉम्प्लेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 ( म.प्र. ), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। सम्पत्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।



## विकसित हो रहा मप्र

मप्र आज विकास के पथ पर तेजी से बढ़ रहा है। इस पर विधानसभा में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में भी मुहर लगी है। राज्य सकल घरेलू उत्पाद 9.37 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं प्रतिव्यक्ति आय में चार गुना वृद्धि हुई है। यह प्रदेश के विकसित स्थिति को दर्शाता है।

● राधेश्याम दांगी, राजगढ़ (म.प्र.)

## ध्यान दे सरकार...

मप्र में महिला अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पीड़ित महिलाओं को न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण है कि राज्य महिला आयोग की बेंच सात साल से लगी ही नहीं है। दरअसल, आयोग में ना तो अध्यक्ष हैं और ना ही सदस्य। सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है।

● प्रमोद तिवारी, ग्वालियर (म.प्र.)

## सिंहस्थ की तैयारी

2028 में होने वाले सिंहस्थ को लेकर मप्र सरकार तैयारियों में जुट गई है। सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन के साथ-साथ संपूर्ण मालवा और निमाड़ के जिलों में भी विकास कार्य किए जाएंगे। देशभर में मप्र के सिंहस्थ की चर्चा पहले से बनी हुई है।

● पंकज मिश्रा, उज्जैन (म.प्र.)



## एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की जरूरत

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हो या मप्र की राजधानी भोपाल या व्यावसायिक राजधानी इंदौर, हर जगह कोचिंग इंडस्ट्री ऐसी ही अव्यवस्थाओं के बीच चल रही है। ब्रासकर यूपीएससी की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर तो बड़े-बड़े दावों के साथ युवाओं को अपने दिव्यताएं उनका शोषण कर रहे हैं। वर्तमान में यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री एक ऐसी मशीन में तब्दील हो गई है, कि हर शहर के रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर कोचिंग संस्थान की मार्केटिंग टीम के लोग देखे जा सकते हैं। भारत के तकरीबन 3,000 करोड़ रूपए की यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री है। जिसे आज कॉर्पोरेट की तरह चलाया जाता है। सरकार को एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करने की जरूरत है।

● प्रीति मलजोनिया, भोपाल (म.प्र.)

## कांग्रेस को मजबूत होना होगा...

मप्र में कांग्रेस पहले विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारी है। कांग्रेस को इसकी चिंता करनी चाहिए और इस साल होने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। कांग्रेस आलाकमान को सीनियर लीडर्स के साथ युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए। इससे वे हर वर्ग के मतदाताओं को जोड़ सकते हैं। कुछ राज्यों में कांग्रेस के रीजनल लीडर ताकतवर हो गए थे। वे अपने हिसाब से राज्य चलाते थे। उनकी लीडरशिप में पार्टी लगातार हारी है, इसलिए इन राज्यों में लीडरशिप बदल रही है।

● ऋषभ गुप्ता, शिवपुरी (म.प्र.)

## मंडियों के हाल बेहाल

मप्र सरकार को प्रदेश की मंडियों पर ध्यान देने की जरूरत है। आए दिन सैकड़ों किसानों की शिकायतें सुनने को मिलती हैं। आवाज जानवर किसानों की अनाज से भरी बोखियां काटकर अनाज खाने लगते हैं। यदि किसान किसी कार्य से दायं-बाएं हो जाता है तो उसके अनाज पर आवाज जानवर टूट पड़ते हैं। मंडी में पानी की भी विकराल समस्या बनी है इसलिए किसान और व्यापारी बेहद परेशान हैं। कई जगहों पर तो लाइट की समुचित व्यवस्था भी नहीं है।

● मोहन वर्मा, सीहोर (म.प्र.)

## पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

## अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,  
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल



## बिहार भाजपा में बड़ा फेरबदल

लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद चर्चा थी कि भाजपा बड़े स्तर पर बदलाव कर सकती है। अब पार्टी ने बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की जगह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। भाजपा के इस कदम को राज्य के एक बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश के लिहाज से देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले यह बड़ा फेरबदल है। राज्य में पिछड़ा वर्ग सबसे अधिक है, ऐसे में यह फैसला एक्स फैक्टर हो सकता है। दिलीप जायसवाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने से किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सुपौल और सहरसा में भाजपा को मजबूती मिलेगी। हालांकि जब सम्राट चौधरी को बिहार का उपमुख्यमंत्री बनाया गया था तभी से यह कयास लगाए जा रहे थे कि सम्राट चौधरी की जगह नया प्रदेश अध्यक्ष चुना जा सकता है। दिलीप जायसवाल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। कुछ दिन पहले ही दिलीप ने पार्टी आलाकमान से मुलाकात की थी तभी से इस बात की संभावना थी कि उन्हें पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि दिलीप को पार्टी की जिम्मेदारी देने के बाद भाजपा ने अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने की कोशिश की है।

## सरयू सहारे नीतीश

कुछ ही महीनों बाद होने जा रहे झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी कमियों को दुरुस्त करने में जुट गई हैं, वहीं झारखंड की सियासत की समझ रखने वाले कद्दावर नेता सरयू राय आखिरकार जेडीयू में शामिल हो गए हैं। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सरयू राय को पार्टी की सदस्यता दिलाई। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले सरयू राय को अपनी पार्टी में शामिल कराकर मुख्यमंत्री नीतीश ने बड़ा दांव खेला है। असल में जेडीयू राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए लंबे समय से कोशिश कर रही है। हालांकि उसे इसमें सफलता नहीं मिल पा रही थी। ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद नीतीश ने पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली थी और अब मुख्यमंत्री पद के साथ-साथ वे पार्टी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की कवायद में जुटे हैं। लोकसभा चुनाव में बिहार में जेडीयू के बड़े भाई की भूमिका में उभरकर सामने आने के बाद नीतीश कुमार ने आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला लिया है। इसको लेकर पिछले दिनों नीतीश ने झारखंड के जेडीयू अध्यक्ष खीरू महतो अथवा पार्टी के अन्य नेताओं के साथ बैठक की थी। इससे पहले झारखंड में बड़ी सियासी समझ रखने वाले दिग्गज नेता सरयू राय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी।



## इंडिया अलायंस का हिस्सा बनेंगे जगन!

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी प्रमुख वाईएस जगन रेड्डी ने बीते दिनों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि हाल ही में राज्य की सत्ता में आसिन होने वाली तेलुगु देशम पार्टी की सरकार ने उनकी पार्टी के खिलाफ हिंसक रुख अपना लिया है। जगन मोहन रेड्डी के इस प्रदर्शन को इंडिया गठबंधन के कई दिग्गजों का साथ मिला। जिसमें समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हुए और उन्होंने अपना समर्थन वाईएसआर कांग्रेस के इस प्रदर्शन को दिया। जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में कयासबाजी शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि वाईएसआर कांग्रेस भी इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ सकती है। अगर ये चर्चा हकीकत में बदल जाती है तो इंडिया गठबंधन का कुनबा भी मजबूत हो जाएगा। गौरतलब है कि वाईएसआर कांग्रेस के लोकसभा में चार सांसद हैं, वहीं राज्यसभा में 11 सांसद हैं जो बहुत बड़ा नंबर है। राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं, लेकिन 19 सीटें खाली होने के चलते उच्च सदन की कुल स्ट्रेंथ फिलहाल 226 है। ऐसे में अगर वाईएसआर कांग्रेस भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए तो मोदी सरकार के लिए राज्यसभा में कोई भी बिल पास करना बेहद मुश्किल हो सकता है।

## सेनापति बनेंगे फडणवीस!

देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी इन दिनों अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की खोज में है। वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 2022 में ही खत्म हो गया था लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उसे बढ़ाकर 30 जून 2024 तक कर दिया गया था। मगर अभी तक पार्टी नए अध्यक्ष का चयन नहीं कर पाई है। ऐसे में सियासी गलियारों में उन नामों पर चर्चा होने लगी है जो पार्टी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम की हो रही है। कहा जा रहा है कि फडणवीस ही भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। इसके पीछे कई सारे तर्क दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि फडणवीस के अध्यक्ष बनने से भाजपा और आरएसएस के बीच चल रही तनातनी खत्म हो सकती है जिसकी मौजूदा समय में पार्टी को सबसे ज्यादा जरूरत है। गौरतलब है कि फडणवीस नागपुर से आते हैं। नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय भी है। उन्हें संघ का करीबी माना जाता है। आरएसएस के शीर्ष नेताओं से उनके संबंध भी अच्छे हैं।

## कांग्रेस छोड़ सकते हैं चौधरी

आम चुनाव 2024 में कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी के बहरामपुर लोकसभा सीट से हार और अब पार्टी के बंगाल इकाई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर लगातार कयासबाजी जोरों पर है। इस बीच राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बयानों से चौधरी के राजनीतिक भविष्य पर सस्पेंस और भी गहरा हो गया है। असल में भाजपा नेता शमिक भट्टाचार्य ने अधीर रंजन चौधरी को लेकर बयान दिया कि सही खिलाड़ी गलत पार्टी में खेल रहा है। इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उनका इशारा चौधरी के भाजपा में शामिल होने की तरफ है। पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन और ममता बनर्जी के बीच राजनीतिक मतभेद जगजाहिर हैं। अधीर लगातार ममता बनर्जी का विरोध करते रहे हैं। ऐसे में वे कांग्रेस में रहते ममता के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं इसलिए वे कांग्रेस का हाथ छोड़ भाजपा का दामन थाम सकते हैं।

## आर-पार के मूड में आ गए साहब

प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों दो आईएएस अधिकारियों की तकरार इस कदर बढ़ गई है कि उनमें से एक साहब आर-पार के मूड में आ गए हैं। दरअसल, सूत्रों का कहना है कि सरकार के करीबी एक आईएएस साहब प्रदेश के विभिन्न जिलों में अफसरों को फोन लगाकर शिष्टाचार की घूटी पिलाते हैं और सहयोगी की अपेक्षा करते हैं। बताया जाता है कि गत दिनों राजधानी के एक पड़ोसी जिले में पदस्थ महिला आईएएस अधिकारी के यहां सरकार के करीबी साहब का फोन पहुंचा। उन्होंने मैडम के सामने अन्य जिलों के अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव को रखा। साहब ने जिस नाम के सहारे प्रस्ताव रखा तो मैडम को अजब सा लगा। उन्होंने कुछ देर बाद एक प्रमुख सचिव को फोन करके साहब के फोन वाली बात बयां की। बताया जाता है कि इस पर प्रमुख सचिव ने कहा कि ऐसी कोई व्यवस्था बनी होगी, इसीलिए आपके सामने प्रस्ताव रखा गया है। सूत्र बताते हैं कि यह बात सरकार के करीबी आईएएस को पता लग गई। फिर क्या था, साहब इस तरह उबल पड़े कि वे आर-पार के मूड में आ गए हैं। उन्होंने मैडम को फोन करके खूब खरी-खोटी सुनाई। यही नहीं उन्हें धमकी भी दे डाली कि जल्द ही मैं तुम्हारा बोरिया-बिस्तर बंधवाता हूँ। यहां बता दें कि मैडम के पिता भी दक्षिण के एक राज्य में आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और संघ ज्वाइन कर लिया है। ऐसे में मैडम हित आनंद के कारण बची हुई हैं।

## हाथ मलते रह गए साहब

राजधानी भोपाल में विकास करवाने वाले एक संस्थान में एक बड़ी संपत्ति के नामांतरण में ऐसा खेल हुआ है कि एक माननीय की झोली भर गई, वहीं संस्थान के सीईओ हाथ मलते रह गए। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश में अवैध गतिविधियों और फर्जीवाड़ा कर तेजी से लक्ष्मीपुत्र बन रहे एक कंसल्टेंट्स कंपनी के मालिक ने गत दिनों राजधानी के एक व्यवसायिक क्षेत्र में बड़े भूखंड को खरीदा। उन्होंने जिस भूखंड को खरीदा उस पर पूर्व में एक सिनेमा हॉल चलता था। बताया जाता है कि उक्त व्यवसायी ने उक्त भूखंड को खरीदने के बाद उसके नामांतरण के लिए साठगांठ शुरू की और एक नेताजी के माध्यम से अपनी फाइल को आगे बढ़ाया। उक्त नेताजी भोपाल के विकास करने वाले संस्थान में राजनीतिक कुर्सी पर बैठे थे। नेताजी ने अधिकारियों को विश्वास में लेकर उक्त भूखंड के नामांतरण की प्रक्रिया शुरू करवाई और सबको आश्वासन दिया कि इस पूरे मामले में बड़ी रकम मिलने वाली है, जिसको आपस में बांट लेंगे। बताया जाता है कि संस्थान की बड़ी कुर्सी पर बैठे साहब को भी बड़ी रकम मिलने की संभावना थी। लेकिन नेताजी ने ऐसा खेल खेला कि नामांतरण भी हो गया और सारी राशि खुद हजम कर ली। इसके बाद संस्थान में बैठे बड़े साहब के साथ ही अन्य लोग हाथ मलते रह गए।



## छोटे साहब की रक्षा करेंगे पंडित जी

प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों एक छोटे साहब यानि 2016 बैच के एक आईएएस अधिकारी चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल, साहब करीब 6 माह पहले राजधानी भोपाल के एक बड़े प्रोजेक्ट में सीईओ बने हैं। बताया जाता है कि साहब ने यहां पदस्थ होते ही अपने रसूख में चार चांद लगाने के लिए एक निजी सुरक्षा गार्ड रख लिया है। जिनको सुरक्षा गार्ड रखा है, वे रिटायर्ड आर्मी मैन हैं। छोटे साहब ने जैसे ही निजी सुरक्षा गार्ड रखा हर तरफ चर्चा होने लगी कि आखिर उन्हें किस बात का डर सता रहा है। जबकि साहब का संस्थान जिस विभाग में आता है, उसके प्रमुख सचिव या अन्य अधिकारी के पास कोई निजी सुरक्षा गार्ड नहीं है। जब इसकी पड़ताल की गई तो यह तथ्य सामने आया कि साहब ने जिस सुरक्षा गार्ड को अपने पास रखा है, उन्हें सब पंडित जी कहकर पुकारते हैं। बताया जाता है कि पंडित जी मोटी तनख्वाह ले रहे हैं, वह भी साहब जिस संस्थान में पदस्थ हैं, वहीं से। यही नहीं जब इसकी गहराई से जांच-पड़ताल की गई तो यह बात भी सामने आई कि वे दो लोगों की तनख्वाह ले रहे हैं, एक तो पंडित जी खुद और दूसरी किसी और के नाम की। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि साहब को निजी सुरक्षा गार्ड रखना पड़ रहा है वह भी सरकारी खर्च पर। साहब की इस हरकत की शिकायत ऊपर तक पहुंच गई है।

## करोड़ों में पाई कुर्सी

प्रदेश में कमाऊ कुर्सी को पाने के लिए अफसरों में हमेशा प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। ऐसी ही एक प्रतिस्पर्धा प्रदेश के पानी पिलाने वाले विभाग में बनी हुई है। इस विभाग में इंजीनियरों की सबसे बड़ी कुर्सी पर काबिज होने के लिए तरह-तरह के दांव लगाए जाते हैं। सूत्रों का कहना है कि इस कुर्सी का मजा ले चुके एक साहब ने करोड़ों देकर संविदा नियुक्ति पाई है। साहब संविदा पर नियुक्त तो हो गए हैं, लेकिन उनकी जड़ें उखाड़ने में उनके समकक्ष बैठे एक अधिकारी जुट गए हैं। गौरतलब है कि इस विभाग की भर्शाही, लापरवाही और भ्रष्टाचार हमेशा चर्चा का केंद्र बने रहते हैं। विभाग भले ही पानी पिलाने का काम करता है, लेकिन इसके अफसर पत्थर पर दूब उगाने की तर्ज पर जमकर कमाई करते हैं। इसलिए इस विभाग में पदस्थ होने के लिए अफसर तरह-तरह के दांवपेंच चलते रहते हैं। वर्तमान में विभागीय इंजीनियरों की की सबसे बड़ी कुर्सी पर जो साहब बैठे हैं, उन्होंने अब तक की सबसे बड़ी रकम देकर कुर्सी तो हासिल कर ली है, लेकिन उनकी राह में बाधा पहुंचाने वाले कई लोग सक्रिय हो गए हैं।

## चमड़ी जाए, दमड़ी न जाए

उपरोक्त कहावत को राजधानी के एक बहुचर्चित ट्रेवल्स कंपनी के संचालक साकार करते हैं। इस ट्रेवल्स कंपनी की टोपीबाजी के किस्से एक नहीं अनेकों हैं। एक बार तो इन्हें ब्लैकलिस्ट भी किया जा चुका है, लेकिन आलम यह है कि कंपनी के संचालक की आदत छूटती नहीं है। सूत्र बताते हैं कि इनके कारोबार का तरीका है कि पहले चरणवंदना करो, फिर टांग खींचकर गिरा दो। ऐसा वे हर किसी के साथ करते हैं, चाहे वह अफसर हो या फिर नेता। यही नहीं उक्त ट्रेवल्स कंपनी के संचालक की फितरत ऐसी रही है कि चाहे संगठन हो, संघ हो या और कोई नेता, जरूरत पड़ने पर किसी को भी साधने में कोई कोरकसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन वे उनसे पूरा पैसा वसूल लेते हैं। सूत्रों का कहना है कि उक्त ट्रेवल्स कंपनी के संचालक इस कदर शातिर हैं कि लोगों को विश्वास में लेकर एक ही गाड़ी तीन-तीन नामों से चलवा देते हैं और पैसा वसूल लेते हैं। लेकिन बताया जाता है कि उक्त ट्रेवल्स कंपनी के संचालक की सारी चालाकी की पोल खुलने लगी है और लोग उनकी हकीकत से वाकिफ हो गए हैं।

**म**प्र में अनुपयोगी सरकारी संपत्तियों को बेचकर सरकारी खजाना भरने की जो परिपार्टी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की थी, मोहन सरकार उस पर अमल नहीं करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली मप्र सरकार अनुपयोगी सरकारी संपत्तियों को बेचने के पक्ष में नहीं है। सूत्रों का कहना है कि मोहन सरकार अनुपयोगी सरकारी संपत्तियों का बेहतर उपयोग और प्रबंधन करने के पक्ष में है। इससे जहां सरकारी संपत्ति वैसी की वैसी तो रहेगी ही उससे आय भी होगी। यानी शिव 'राज' के नक्शेकदम पर मोहन 'राज' नहीं चलेगा।

दरअसल, मप्र की पूर्ववर्ती सरकार और उसके मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश सरकार पर बढ़ते कर्ज के दबाव को कम करने के लिए प्रदेशभर में फैली अनुपयोगी सरकारी संपत्तियों को बेचने का सिलसिला शुरू किया था। लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सरकारी संपत्तियों को बेचने के कतई पक्ष में नहीं है। यही वजह है कि डॉ. मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद से लोक परिसंपत्ति विभाग ने एक भी संपत्ति को नहीं बेचा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पहली ही बैठक में सरकारी संपत्ति बेचने पर रोक लगा दी थी। हालांकि संपत्ति बेचने पर लिखित रोक नहीं लगी है। जबकि विभाग संपत्तियां बेचने की लंबी सूची बनाकर तैयार कर चुका था। मुख्यमंत्री के इस फैसले को प्रदेश के हित में बताया जा रहा है।

गौरतलब है कि प्रदेशभर में फैली अनुपयोगी सरकारी संपत्तियों का बेहतर उपयोग और प्रबंधन करने की बजाय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें बेचने का सिलसिला शुरू किया था। पिछली सरकार सितंबर 2020 में लोक परिसंपत्ति विभाग के गठन से लेकर नवंबर 2023 तक करीब 99 संपत्तियों को खुली नीलामी के जरिए बेच चुकी थी। संपत्ति बेचकर सरकार के खजाने में करीब एक हजार करोड़ रुपए आए। लेकिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सरकारी संपत्ति बेचने की बजाय उनका बेहतर उपयोग और प्रबंधन करने के पक्ष में हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर दूसरे प्रदेशों में भी राज्य की संपत्ति को चिन्हित कर सहेजा गया है। पिछली सरकार ने मप्र के भीतर एवं दूसरे प्रदेशों में राज्य की अचल संपत्तियों को बेचने के लिए 26 सितंबर 2020 को सरकार के 69वें विभाग के रूप में लोक परिसंपत्ति विभाग का गठन किया था। इसी विभाग में मप्र राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी बनाकर संपत्तियां बेची गईं। जिनमें राजस्व, परिवहन, ऊर्जा समेत अन्य विभागों की संपत्तियां शामिल हैं। पिछली सरकार ने वर्ष 2020-21 में 4 संपत्तियों से 26.96 करोड़, 2021-22 में 19 संपत्तियों से 284.5 करोड़, 2022-23 में 52 संपत्तियों से 564.45 करोड़ और चालू वित्तीय वर्ष 2023-24

## सरकारी संपत्तियों का प्रबंधन करेगी सरकार



### मुख्यमंत्री ने करवाया सर्वे...कांग्रेस को नजर आया झोल

गौरतलब है कि सरकारी संपत्तियों का बेहतर उपयोग और प्रबंधन करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सर्वे कराने का निर्देश दिया तो कांग्रेस को उसमें झोल नजर आने लगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद वित्त विभाग ने सभी विभागों को लिखे पत्र में कहा है कि मुख्य सचिव दूसरे राज्यों में स्थित सरकार की संपत्ति को लेकर जल्द समीक्षा करेगी। इस पत्र के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा और मुख्यमंत्री मोहन यादव पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने मांग की है कि भाजपा सरकार प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर श्वेतपत्र जारी करे। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि कर्ज में डूबी मप्र सरकार देश के दूसरे राज्यों में मौजूद मप्र के अलग-अलग विभागों की संपत्ति बेचने और उसे किराए पर देने की तैयारी कर रही है। वित्त विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखकर जानकारी भी मांग ली है। पूछा जा रहा है कि किस राज्य में कितनी संपत्ति किस रूप में है, उसका मूल्य क्या है? अगर किसी प्रॉपर्टी का कोर्ट में केस चल रहा है, किसी तरह का विवाद है तो इसकी भी जानकारी दी जाए। इस कवायद का मकसद मप्र के बाहर मौजूद विभिन्न विभागों की संपत्ति का डाटा जुटाना है। ताकि, उसे बेचकर या किराए पर देकर राशि जुटाई जा सके। संपत्ति के मौजूदा स्वरूप की जानकारी देने के साथ, उसके मौजूदा मूल्य की जानकारी भी चाही गई है।

में 24 संपत्तियों से 258.44 करोड़ रुपए जुटाए। हालांकि अभी तक 1134 करोड़ में से करीब 1 हजार करोड़ आ चुके हैं। जबकि मोहन सरकार ने एक भी संपत्ति अभी तक नहीं बेची है।

जानकारी के अनुसार, पिछली सरकार 99 संपत्तियों का 661 करोड़ के आरक्षित मूल्य के विरुद्ध खुली नीलामी में 1134 करोड़ में सौदा कर चुकी थी। जिनमें से करीब 1 हजार करोड़ रुपए खजाने में आ चुके हैं। विभाग ने 561 संपत्तियों को चिन्हित कर रखा है, जो बेचने के लिए हैं। डॉ. मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद विभाग ने एक भी संपत्ति को नहीं बेचा है। बल्कि उन्हें सार्वजनिक उपयोग के लिए व्यवस्थित किया जा रहा है। ताकि भविष्य में सरकार उनका उपयोग कर सके। पिछली सरकार के कार्यकाल में ही विनोद मिल उज्जैन की 18.18 हेक्टेयर, इंदौर और लवकुशनगर छतरपुर की संपत्ति बेचने की निविदा प्रक्रिया शुरू की गई थी, जो पूरी नहीं हुई। सरकार अब ये संपत्तियां भी बेचने के पक्ष में नहीं है।

हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मप्र परिसंपत्ति प्रबंधन राज्य कंपनी लिमिटेड के

संचालक मंडल की बैठक में कहा कि मप्र और मप्र के बाहर अन्य राज्यों में प्रदेश सरकार की परिसंपत्तियों का उपयोग और बेहतर प्रबंधन का कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही कहा कि परिसंपत्तियों एवं उनकी वर्तमान स्थिति का अध्ययन और सर्वेक्षण कर ऐसी परिसंपत्तियों का जनहित में उपयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सरकारी संपत्ति बचाने को लेकर कितने संवेदशील हैं, इसका अंदाजा हाल ही में राजधानी भोपाल के सबसे बड़े प्राकृतिक खूबसूरत स्थल वाल्मी की पहाड़ी को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कराने के फैसले से लगाया जा सकता है। वाल्मी पर भोपाल के बिल्डर से लेकर कॉर्पोरेट जगत की निगाहें थीं। बिल्डरों की कॉलोनियों को वाल्मी से रास्ता देने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि एकजुट हो चुके थे। पिछली सरकार में पंचायत मंत्री ने बिल्डरों की कॉलोनियों को रास्ता देने के लिए वाल्मी में खुदाई को मंजूरी दे दी थी। इस बीच तत्कालीन मुख्य सचिव ने अपने वीटो का उपयोग कर काम रुकवाया था।

● प्रवीण सक्सेना



**जि** न अधिकारियों के कंधों पर लोगों को ठगी से बचाने की जिम्मेदारी है, वे खुद साइबर ठगों के निशाने पर हैं। जालसाज आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के कभी सोशल मीडिया अकाउंट हैक करके, तो कभी वॉट्सऐप पर उनके नाम से ग्रुप बनाकर लोगों को फंसाने व ठगने का षड्यंत्र रच रहे हैं। अभी हाल ही में ठगों ने वॉट्सऐप की डीपी में जबलपुर कलेक्टर की फोटो लगाई और उनके रिश्तेदार से 25 हजार रुपए ठग लिए। इसी तरह शहडोल, धार और शिवपुरी कलेक्टरों के नाम से भी ठगने के प्रयास जालसाजों ने किए हैं। इसी प्रकार का एक मामला मुरैना जिले के एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान का भी है। बीते सप्ताह फेसबुक पर उनका फर्जी अकाउंट बनाया गया, जो कुछ दिनों पहले डिलीट कर दिया गया।

दरअसल, आईएएस और आईपीएस जैसे अधिकारियों के नाम से आसानी से ठगी हो जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कुछ समय पहले इंदौर से लेकर भोपाल क्षेत्र में सामने आया, जब पूर्व आईपीएस एमएस वर्मा के नाम से साइबर ठगों ने फर्जी फेसबुक अकाउंट बना लिया और फर्जी फेसबुक पर लिखा कि मेरा स्वास्थ्य खराब है अभी किसी से बात नहीं कर पाऊंगा, मुझे आर्थिक सहयोग की जरूरत है। इसके साथ एक बैंक खाता नंबर भी पोस्ट कर दिया, जो ठगों का था। इस खाते में कई थाना प्रभारियों से लेकर अन्य पुलिसकर्मियों ने बिना सोचे-समझे व सत्यापन के पैसे डाल दिए। वहीं, सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा ने कहा कि मेरा फेसबुक पर केवल एक अकाउंट है, जिसे मैं खुद ऑपरेट करता हूँ। बाकी के दो या तीन अकाउंट हैं, वह सभी फर्जी हैं। इन्हें बंद करवाकर फर्जी अकाउंट खोलने वालों का पता लगवाकर कार्रवाई की जाएगी। ठगों ने शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी के नाम पर श्रीलंका के नंबर से वॉट्सऐप अकाउंट बनाया। कलेक्टर ने लिखा, अज्ञात हैकर ने मेरे नाम और फोटो के साथ फर्जी अकाउंट बना लिया है। इसमें मेरे नाम के साथ फोटो का भी इस्तेमाल किया है। बिजनेस अकाउंट पर +94785909474 नंबर से फर्जीवाड़े का प्रयास किया गया है। कलेक्टर ने लिखा है, कृपया मेरे नाम से बनाए गए फर्जी अकाउंट से सावधान रहें। यदि कोई संदेश मिलता है, तो रिपोर्ट करें और उसे ब्लॉक करें।

जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना के नाम से उनके रिश्तेदार से 25 हजार रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। साइबर ठग ने कलेक्टर की फोटो की डीपी लगाई और फिर कई रिश्तेदारों को मैसेज किए। उनके एक रिश्तेदार झांसे में आ गए और 25 हजार रुपए वॉट्सऐप पर ट्रांसफर कर दिए। बाद में फोन कर बताया तो कलेक्टर सक्सेना हैरान रह गए। उन्होंने

## ठगों के निशाने पर ब्यूरोक्रेट्स



### इन अधिकारियों के भी बने फर्जी अकाउंट

मुरैना व इंदौर के पूर्व एसपी और वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सीबीआई में सेवाएं दे रहे आईपीएस अधिकारी आशुतोष बागरी का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर कई लोगों को ठगने का प्रयास किया गया। ऐसी शिकायतें मिलने के बाद खुद बागरी ने अपने मूल फेसबुक अकाउंट से इस फर्जी अकाउंट की जानकारी दी थी और कहा कि इससे किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट आए तो मत जुड़िए और ना ही कोई जानकारी दें। मुरैना के पूर्व एसपी व वर्तमान में छतरपुर में डीआईजी ललित शाक्यवार के नाम से भी एक महीने पहले फर्जी फेसबुक अकाउंट बना और उनके करीबियों को मैसेज कर फोन नंबर से लेकर अन्य जानकारी मांगी गई। मुरैना व श्योपुर के पूर्व और खंडवा के वर्तमान एसपी अनुराग सुजानिया के नाम से भी पिछले महीने फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया गया और उनके करीबियों को मैसेज करके ठगने का प्रयास किया, पर आईपीएस सुजानिया ने जानकारी लगते ही अकाउंट बंद करा दिया। मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर के पूर्व एसपी और वर्तमान में पीएचक्यू में पदस्थ एडीजीपी सुनील कुमार पांडेय के नाम से भी 15 दिन पहले ठगों ने फर्जी फेसबुक अकाउंट बना लिया था।

शिकायत साइबर सेल को भेजी है। साथ ही अलर्ट भी जारी किया है। इससे पहले भी कलेक्टर सक्सेना के नाम से फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर साइबर फ्रॉड की कोशिश की गई थी। उनके कुछ परिचितों को मैसेंजर पर मैसेज भेजकर रुपए मांगने की चैट सामने आ गई थी तो सक्सेना ने शिकायत साइबर सेल से कर आईडी ब्लॉक कराने को कहा था। उन्होंने लोगों को सतर्क भी किया था, लेकिन इस बार साइबर ठगों ने वॉट्सऐप पर कलेक्टर की फोटो लगाकर ठगी कर डाली। वहीं धार कलेक्टर प्रियंका मिश्रा के नाम पर भी ठगी करने का किया गया। जानकारी के बाद प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। साथ ही साइबर सेल को भी शिकायत की गई है। ऑनलाइन ठगों ने कलेक्टर मिश्रा के नाम से वॉट्सऐप अकाउंट नंबर 94785265198 पर फर्जी अकाउंट बनाया था। साथ ही एक व्यक्ति को मैसेज भेजकर ठगने का प्रयास किया। गनीमत रही कि संबंधित व्यक्ति की सतर्कता के कारण ठग सफल नहीं हो सके। कलेक्टर ने लोगों को सावधानी बरतने को कहा है।

शहडोल कलेक्टर तरुण भटनागर के नाम से

फर्जी नंबर से सोशल मीडिया में पैसे मांगने की बात सामने आई है। ऑनलाइन ठगों ने कलेक्टर के नाम से फर्जी नंबर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पैसे की मांग की। इसे लेकर जिला प्रशासन ने आमजन को सतर्क रहने कहा है। साथ ही यह भी कहा गया है कि कोई भी अपने बैंक खाते एवं पहचान से संबंधित जानकारी साझा न करें। इसी प्रकार सिवनी कलेक्टर संस्कृति जैन का 94785265198 के माध्यम से फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों से गिफ्ट और पैसे की मांग की गई थी। उमरिया कलेक्टर के नाम से भी फर्जी नंबर से सोशल मीडिया में पैसे की मांग की बात सामने आई है। सोशल मीडिया मनोरंजन से लेकर सूचना के लिए एक बड़ा माध्यम है। लेकिन इसके खतरे भी बढ़ रहे हैं। लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय सतर्क रहें। हाल के दिनों में यह चौथा मामला है, जब हाइप्रोफाइल लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। इससे पहले लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के नाम से फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर ठगी की कोशिश की गई थी।

● सुनील सिंह

म प्र में एक तरफ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं और सुशासन पर जोर दे रहे हैं। इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है।

लेकिन कुछ विभागों में इस गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। इन्हीं में से एक है पानी पिलाने वाला विभाग। इस विभाग में लूट मची है। विभागीय मंत्री

## पानी पिलाने वाले विभाग में लूट की घूट

की शह पर उनके सिपाहसालार विभाग में मनमानी और भ्रष्टाचार की नदी बहा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि मंत्री ने भी अफसरों को अपनी कमाई का टारगेट बता दिया है, जिसके आधार पर अफसर काम कर रहे हैं। वैसे तो सब मंत्रियों का हाल बेहाल है, लेकिन इनका जवाब नहीं है। इन्होंने अपने चारों तरफ ऐसे अधिकारियों का कॉकस बना लिया है, जिसके कारण विभाग का भले ही बंटोधार हो जाए, लेकिन उनकी तथा उनके चहेतों की झोली में लक्ष्मीजी की कृपा बरसती रहे।

## अभी तो चुनाव खर्च भी नहीं निकला

पानी पिलाने वाले विभाग में मची लूट के संदर्भ में कहा जा रहा है कि जैसा राजा वैसी प्रजा वाली स्थिति इस विभाग में बनी हुई है। वैसे तो मंत्रियों के बंगले विभाग चलाते हैं और हर माह खर्च होने वाले 4-5 लाख रुपए की जुगाड़ करते हैं। इस बीच मंत्री ने अपने सिपाहसालारों से स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अभी तो चुनाव खर्च भी नहीं निकला है। यानि, उसकी भरपाई भी हर हाल में करनी है। बताया जाता है कि इसको देखते हुए प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में बदनामनुमा एक आदमी ने कमाई का मोर्चा संभाल लिया है। बताया जाता है कि ये जनाब जहां-जहां मंत्री पदस्थापना में पदस्थ रहे हैं, वहां-वहां बंटोधार किया है। अभी हाल ही में वे एक युवा मंत्री के यहां पदस्थ थे। जहां उन्होंने उक्त मंत्री के कैरियर को चौपट करने में कोई कोरकसर नहीं छोड़ी।

## पाड़े से भी दूध निकालने में माहिर

जिस महाशय की यहां बात हो रही है, उनके बारे में कहा जाता है कि गाय-भैंस से तो हर कोई दूध निकाल लेता है, ये तो पाड़े से भी दूध निकालने में माहिर हैं। सूत्र बताते हैं कि मंत्री को कह दिया गया है कि ट्रांसफर की कमाई करोड़ों में करा देंगे। उसके लिए बकायदा रेंट लिस्ट भी बना ली गई है। महाशय एक तो



## अफसरों को तनिक भी डर नहीं

प्रदेश में सरकार की सख्ती के बाद भी अफसरों को भ्रष्टाचार करने में तनिक भी डर नहीं है। इस पर गत दिनों तब और मुहर लग गई, जब लोकायुक्त पुलिस ने भोपाल नगर निगम के सेवानिवृत्त अधीक्षण यंत्री और संविदा पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में कार्यरत प्रदीप कुमार जैन (अब हटा दिए गए) के आवास और कार्यालय पर छापेमारी की। जैन के खिलाफ लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया है। लोकायुक्त पुलिस ने प्रदीप कुमार जैन के आवास पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही की। लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक को आय से अधिक संपत्ति को लेकर शिकायत मिली थी। इसका सत्यापन कराया गया। इसमें प्रारंभिक जांच में आय से 300 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित करने के प्रमाण मिले हैं। इसके बाद प्रदीप कुमार जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त कर उनके आवास और कार्यालय पर लोकायुक्त की दो टीमों ने तलाशी कार्यवाही की। लोकायुक्त टीम को तलाशी के दौरान 5 करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्ति, 86 लाख से ज्यादा के जेवरात के बिल, लाखों के निवेश के दस्तावेज और विदेश यात्रा के दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। टीम को एक लॉकर और भोपाल में 5 प्रॉपर्टी की जानकारी भी मिली है। लोकायुक्त पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीके जैन के विदेशी निवेश की जानकारी भी मिली है। इसकी टीम जांच कर रही है। जैन कुछ दिन पहले ही कनाड़ा से लौटे हैं। जैन भोपाल नगर निगम से सेवानिवृत्त होने के बाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में संविदा पर अधीक्षण यंत्री के पद पर पदस्थ हुए थे। छापेमारी के बाद कागजों के आधार पर जांच चल रही है, वहीं उन्हें स्मार्ट सिटी से हटा दिया गया है।

करेला, ऊपर से नीम चढ़ा वाली स्थिति में हैं। वहीं उनको उन्हीं के जैसा एक साथी मिल गया है। ये जनाब एक ठाकुर साहब हैं, जो उनसे ताल से ताल मिला रहे हैं। इससे एक और एक ग्यारह वाली स्थिति बन गई है। ठाकुर साहब के रसूख का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सहायक यंत्री रहते हुए कार्यपालन यंत्री का काम संभाल रहे हैं। ये जनाब भोपाल में ही पढ़े-लिखे हैं और विकलांग कोटे से नौकरी कर रहे हैं, पर जानकार यह कहते हैं कि नौकरी के लिए विकलांग कोटा लिया था, विकलांग तो दिख नहीं रहे हैं कहीं से।

## मंत्री मुट्ठी में

सूत्रों का कहना है कि उपरोक्त दोनों अफसरों ने पानी पिलाने वाले विभाग की मंत्री को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। मंत्री के बंगले का खर्चा कार्यपालन यंत्री संभाल रहे हैं। यही नहीं विभाग के कई अफसरों के घर का खर्चा भी यही उठा रहे हैं। कहने को तो साहब राजधानी भोपाल की स्वच्छता के कामों को भी देखते हैं और उनके माध्यम से सालाना 4-5 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। इनकी ईमानदारी ऐसी है कि उक्त राशि में से 75 प्रतिशत अपने पास रखते हैं और 25 प्रतिशत औरों में बांट देते हैं। इन जनाब के बारे में कहा जाता है कि सेटिंगबाज ये अधिकारी पहले भी राजधानी में बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाले एक संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर रहकर गाड़ियों के संचालन का काम देखते थे और वहां भी उन्होंने जमकर चांदी काटी है। देखने में शांत और सौम्य स्वभाव के उक्त अधिकारी इस कदर शातिर हैं कि वे अच्छे-अच्छों को अपने जाल में फांस लेते हैं। बताया जाता है कि इनकी पोस्टिंग भी लाखों रुपए देकर हुई है। ऐसे में जब उक्त कार्यपालन यंत्री ने मोटी राशि देकर पदस्थापना पाई है, तो उन्होंने कमाई का बड़ा रास्ता देखा होगा। इसलिए वे विभाग में बेधड़क और बेझिझक कमाई कर रहे हैं।

म प्र की मुख्य सचिव वीरा राणा को एक और सेवावृद्धि मिल सकती है। उनका कार्यकाल सितंबर 2024 तक है। इसके संकेत गत दिनों वरिष्ठ अधिकारियों की जिस तरह से पदस्थापना की गई है, उससे मिलते हैं। मुख्य सचिव पद के दावेदारों में प्रमुख नामों में 1989 बैच के अधिकारी मोहम्मद सुलेमान और 1990 बैच के अधिकारी एसएन मिश्रा शामिल हैं। दोनों अधिकारियों के दायित्व में जिस तरह परिवर्तन किया है, उससे माना जा रहा है कि किसी अन्य अधिकारी के लिए रास्ता सुगम किया जा रहा है। दरअसल, वीरा राणा का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से अच्छा सामन्जस्य बन रहा है। वहीं वह पूर्व में किसी अन्य सीएम की खास नहीं रही हैं। इसलिए संभावना जताई जा रही है कि उन्हें एक और एक्सटेंशन मिल सकता है। मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा को अपने कार्यालय में पदस्थ कर बड़ा संकेत दिया है। उनसे वरिष्ठ अधिकारी 1989 बैच के विनोद कुमार और जेएन कंसोर्टिया को मंत्रालय के बाहर पदस्थ किया तो अब अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान को कृषि उत्पादन आयुक्त बनाया है, जो तुलनात्मक रूप से कम महत्व का दायित्व माना जाता है। इनकी मुख्य भूमिका कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी विभागों के बीच समन्वयक की होती है। वे जुलाई 2025 में सेवानिवृत्त होंगे। वहीं, एसएन मिश्रा को गृह और परिवहन जैसे महत्वपूर्ण विभाग देकर उनकी आगामी भूमिका की ओर भी इशारा कर दिया है। वह जनवरी 2025 में सेवानिवृत्त होंगे। इसी बैच के मलय श्रीवास्तव नवंबर 2025 और डॉ. राजेश राजौरा मई 2027 में सेवानिवृत्त होंगे। इसलिए लगता है कि राजेश राजौरा के सीएस बनने में अभी देरी है।

## एसीएस-पीएस लेवल के अफसर कम

सरकार भले ही बदल गई है लेकिन आईएएस अफसरों की पदस्थापना की परंपरा पुरानी ही है। पुरानी सरकारों की तरह वर्तमान सरकार भी एक-डेढ़ दर्जन अफसरों पर विश्वास जता रही है। ऐसा नहीं है कि बाकी अफसरों का काम बुरा है, लेकिन वे अफसर व्यवस्था से पटरी नहीं बैठ पाते हैं। जबकि एक-डेढ़ दर्जन अफसर ऐसे हैं, जिन्हें जिस सांचे में ढाला जाए, उसमें फिट बैठने की कोशिश करते हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि कई विभागों का काम अतिरिक्त प्रभार से चल रहा है। जिन अफसरों को दूसरे विभागों का प्रभार मिला है, वे वहां मन लगाकर काम भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर इस बात का है कि न जाने कब चलता कर दिए जाए। दरअसल, प्रदेश में एसीएस और पीएस लेवल के अफसरों की कमी है। इसका असर यह हो रहा है कि अफसरों को कई-कई विभागों के अतिरिक्त



## वीरा राणा को मिल सकता है एक और एक्सटेंशन

### आखिरकार मंत्रियों ने अपनी बात मनवा ली

मप्र में सत्ता और संगठन ने मंत्रियों को विवादित और पुराने स्टाफ से दूर रहने का जो फॉर्मूला बनाया था, वह मंत्रियों की जिद और मनमर्जी के आगे पस्त हो गया। यानी मंत्रियों की मर्जी सब पर भारी पड़ी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रियों को उनकी मर्जी से स्टाफ में विशेष सहायक, निज सहायक और स्टाफ के कर्मचारी नियुक्त करने की अनुमति दे दी है। 8 माह की मशकत के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने 14 मंत्रियों के स्टाफ की पदस्थापना के आदेश भी जारी कर दिए हैं। जो अफसर, कर्मचारी मंत्री स्टाफ में पोस्टिंग पाने में सफल रहे हैं उनमें से कई पिछले एक दशक से मंत्रियों के यहां काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि मंत्री स्टाफ में सालों से पदस्थ अधिकारी-कर्मचारियों की भाजपा के ही नेता-कार्यकर्ताओं ने शिकायतें की थी। उनका कहना था कि सालों से ये कर्मचारी कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते। इसके अलावा कई विशेष सहायक से लेकर निज सहायकों पर आरोप भी लगे थे। इसके चलते संगठन ने मंत्रियों के पुराने स्टाफ को फिर से उन्हें न देने का निर्णय लिया था, पर इसका पूर्णरूप से पालन नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई सरकार के गठन के बाद मंत्रियों के यहां पहले काम कर चुके अधिकारियों और कर्मचारियों की पोस्टिंग पर रोक लगा दी थी। इससे संबंधित नस्ती मंजूर नहीं किए जाने के बाद कई मंत्रियों के स्टाफ में ये अधिकारी-कर्मचारी काम कर रहे थे लेकिन अब मुख्यमंत्री ने इन अफसरों, कर्मचारियों की पदस्थापना पर सहमति दे दी है।

प्रभार दिए गए हैं। वहीं एक ही विभाग में कई आईएएस अफसरों को पदस्थ कर दिया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में मलय श्रीवास्तव एसीएस के पद पर पदस्थ हैं। ऐसे में इस विभाग में दीपाली रस्तोगी को प्रमुख सचिव के पद पर पदस्थ कर दिया गया है। ऐसे में विभाग में किस तरह काम होगा?

### माननीयों की नाराजगी पड़ी भारी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सत्ता संभालते ही अफसरों को ताकीद कर दिया था कि मंत्रियों-विधायकों को पूरा सम्मान देना होगा और जनता का हर काम करना होगा। बावजूद इसके जिलों में पदस्थ कई कलेक्टर-एसपी सहित अन्य मैदानी अफसरों ने नाफरमानी की। इससे मंत्री और विधायकों ने उनके खिलाफ मुख्यमंत्री से शिकायत की थी। सरकार ने जिन 47 आईएएस और आईपीएस अफसरों को बदला है, उनमें से 18 के खिलाफ कुछ न कुछ शिकायतें थीं, जबकि ज्यादातर लूपलाइन में थे। उन्हें बड़ी

जिम्मेदारी दी गई है तो बालाघाट कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा जैसे कुछ अफसरों को एक ही स्थान पर तीन साल से ज्यादा हो गए थे। इस कारण उन्हें हटाया गया। प्रमोटी आईएएस केदार सिंह, अजय गुप्ता, सोमेश मिश्रा जैसे अफसर लंबे समय से लूपलाइन में थे, जिन्हें मौका दिया गया। गुना बस हादसे के बाद से आईएएस तरुण राठी लूपलाइन में डाले गए थे, उन्हें अब अवसर मिला। मोहन सरकार के आते ही पंचायत से हटाकर लूपलाइन में भेजे गए आईएएस अफसर उमाकांत उमराव को श्रम विभाग का जिम्मा देकर अवसर दिया गया है। अंशुल गुप्ता उज्जैन निगमायुक्त रहते मुख्यमंत्री की नजर में आए, इसलिए जनसंपर्क का जिम्मा मिला। डिंडोरी कलेक्टर विकास मिश्रा को लूपलाइन में भेजा गया, वह पूर्व की सरकार में चर्चा में रहे थे। उज्जैन जिला पंचायत सीईओ मृणाल मीना समेत 2015 बैच के 5 आईएएस को जिलों में कलेक्टर बनाकर अवसर दिए हैं।

● राजेंद्र आगाल

ए नटीए द्वारा आयोजित नीट-यूजी परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े की चर्चा इस समय पूरे देश में हो रही है। अब नीट फर्जीवाड़े जैसा ही मामला मप्र में भी सामने आया है। यहां बीएड, डीएड, डीएलईएड कॉलेजों में बड़े पैमाने पर मप्र के छात्रों का हक मार दिया। यह बात कोई और नहीं बल्कि मप्र का राज्य शिक्षा केंद्र स्वयं बोल रहा है लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। राज्य शिक्षा केंद्र ने 98 डिफॉल्टर डीएलएड कॉलेजों की सूची जारी कर बताया था कि ये वे कॉलेज हैं जिन्होंने 2024-25 सत्र के लिए मप्र के एक भी छात्र को एडमिशन नहीं दिया है। पहले चरण की काउंसिलिंग के बाद 98 कॉलेजों में मप्र के छात्रों की संख्या जीरो है। नोटिस में राज्य शिक्षा केंद्र ने यह टिप्पणी भी की है कि मप्र के छात्रों को एडमिशन न देकर ये कॉलेज मप्र के मेधावी छात्रों के साथ घोर अन्याय कर रहे हैं।

दरअसल डीएलएड कॉलेज संचालक लंबे समय से इस फर्जीवाड़े को मप्र में चला रहे हैं, जिसके तहत वे मप्र के छात्रों को एडमिशन नहीं देते हैं और दलालों के माध्यम से कॉलेजों की सीटों पर राजस्थान, उप्र, बिहार, झारखंड सहित अन्य राज्यों के छात्रों को एडमिशन देते हैं। इसके पीछे कमाई का बड़ा गणित है। यदि मप्र के छात्रों को एडमिशन देंगे तो उनको सरकारी फीस जो 30 से 35 हजार रुपए प्रतिवर्ष है, उस पर एडमिशन देना होगा, जबकि दूसरे राज्यों के छात्रों को दलालों के माध्यम से एडमिशन देकर उनसे एक लाख रुपए से लेकर डेढ़ लाख रुपए प्रतिवर्ष तक की फीस वसूल की जाती है। यह कोर्स दो साल का होता है तो इस प्रकार दो साल के लिए प्रति छात्र 3 लाख रुपए तक की वसूली कॉलेजों द्वारा की जाती है। मोटी फीस के एवज में कॉलेजों द्वारा छात्रों को नियमित कॉलेज आने से छूट रहती है और सिर्फ परीक्षा के वक्त ही उन्हें बुलाया जाता है। इस पूरे फर्जीवाड़े को दलालों, नकल माफिया, डीएलएड कॉलेज संचालक, एमपी बोर्ड व राज्य शिक्षा केंद्र के अधिकारियों की मिलीभगत से अंजाम दिया जाता है। लेकिन इस बार एनएसयूआई द्वारा शिकायत करने के बाद राज्य शिक्षा केंद्र ने कॉलेजों को नोटिस तो दिया लेकिन उसके बाद कार्रवाई के नाम पर शांत बैठ गए। इस पूरे फर्जीवाड़े में दिलचस्प बात ये निकलकर सामने आई कि जब राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी 98 कॉलेजों को नोटिस दिया तो लगभग सभी कॉलेजों ने एक जैसा जवाब लिखकर राज्य शिक्षा

## मप्र में भी नीट-यूजी जैसा फर्जीवाड़ा



### एसटीएफ को जांच का जिम्मा

मामले की शिकायत के बाद सरकार ने जांच का जिम्मा स्पेशल टास्क फोर्स को सौंपा। शिकायतों की लंबे समय से चल रही जांच के दौरान खुलासा हुआ कि इन कॉलेज के प्रबंधन द्वारा एनसीटीई दिल्ली और जीवाजी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त करने के लिए जो दस्तावेज लगाए गए थे जब इनका सत्यापन किया गया तो वे सब जाली निकले। मामले की जांच शुरू हुई तो एसटीएफ की जांच में चिन्हित सभी बीएड और डीएड कॉलेजों के सारे दस्तावेज फर्जी पाए गए, जिससे एनसीटीई और जीवाजी विश्वविद्यालयों की टीम द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट पर सवालिया निशान लग गए हैं, जिनके आधार पर उन्हें मान्यता दी गई थी। एसटीएफ ने लगभग 5 साल तक जांच की। फर्जी कॉलेजों में आइडियल कॉलेज बरोआ, अंजुमन कॉलेज ऑफ एजुकेशन सेवदा, दतिया, प्राणी कॉलेज ऑफ एजुकेशन मुगावली, अशोकनगर, सिटी पब्लिक कॉलेज शादौरा, अशोकनगर, मां सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय वीरपुर, श्योपुर और प्रताप कॉलेज ऑफ एजुकेशन बड़ौदा, श्योपुर शामिल हैं।

केंद्र को भेजा है, जिसमें कहा गया है कि पहले चरण की काउंसिलिंग के बाद मप्र के जिन छात्रों को कॉलेज एलाउंट किए गए, वे एडमिशन लेने ही नहीं आए। सभी कॉलेजों ने यही जवाब राज्य शिक्षा केंद्र को भेजा लेकिन राज्य शिक्षा केंद्र इस

जवाब को देखने के बाद भी जाग नहीं पाया या जानबूझकर आंखे बंद करके बैठ गया।

डिप्लोमा इन एजुकेशन और बैचलर डिग्री इन एजुकेशन की डिमांड मप्र में जितनी है, उससे कहीं अधिक उप्र, राजस्थान, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में है। इन राज्यों में सरकारी नौकरी के नाम पर सबसे अधिक वैकेंसी शिक्षा विभाग में ही निकलती है और इन राज्यों में शिक्षा विभाग द्वारा अपने शिक्षकों को वेतन भी मप्र की तुलना में अधिक दिया जाता है। सरकारी नौकरी की चाह में दूसरे राज्यों के छात्र मप्र के डीएलएड कॉलेजों का रुख करते हैं और दलालों के माध्यम से पहले ही सीट बुक कर लेते हैं। काउंसिलिंग की सिर्फ औपचारिकता होती है और उसके बाद एक लाख से डेढ़ लाख रुपए सालाना फीस पर दूसरे राज्यों के छात्रों द्वारा मप्र के डीएलएड कॉलेजों में एडमिशन ले लिए जाते हैं। वहीं मप्र में शिक्षक बनने का सपना लिए छात्र दर-दर की ठोकर खा रहे हैं। अव्वल तो

उनको डीएलएड जैसा कोर्स करने के लिए अपने ही राज्य में कॉलेज मिलता नहीं, जैसे-तैसे वे एडमिशन ले भी लें तो मप्र सरकार का स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्त अवस्था में बैठा हुआ है, जबकि हजारों की संख्या में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हुए हैं लेकिन सरकार में मप्र के ही छात्रों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

मप्र में शिक्षा घोटाला रुकने का नाम नहीं ले रहा। नर्सिंग कॉलेज घोटाले के बाद अब बीएड और डीएड कॉलेजों का फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। स्पेशल टास्क फोर्स की जांच में खुलासा हुआ कि ग्वालियर-चंबल अंचल में बीएड और डीएड की शिक्षा दे रहे चार कॉलेज तो ऐसे हैं जिनके सारे डॉक्यूमेंट ही फर्जी हैं। ग्वालियर-चंबल में फर्जी दस्तावेज के आधार पर संचालित बीएड-डीएड कॉलेजों का पर्दाफाश हुआ है। स्पेशल टास्क फोर्स की जांच में यह बात सामने आई है। हालांकि शिकायत की जांच में 4 से 5 साल लग गए और अब जाकर फर्जी कॉलेज के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो पाया है। बताया गया कि 4-5 साल पहले 2019 और 2020 दीपक कुमार शाक्य और मनीष चोकोटिया द्वारा शिकायत की गई थी कि ग्वालियर-चंबल अंचल में बीएड और डीएड के कुछ ऐसे कॉलेज चल रहे हैं, जिनके सभी डॉक्यूमेंट फर्जी हैं। यह कॉलेज फर्जी एफआईआर, फर्जी भवन निर्माण और डायवर्जन पत्र आदि पर संचालित किए जा रहे हैं।

● कुमार विनोद

2 साल पहले चलाए गए ऑपरेशन भूमाफिया में जहां कई गृह निर्माण संस्थाओं की जमीनों पर पीड़ितों को भूखंडों के कब्जे दिलवाए गए, तो भूमाफिया के चंगुल में फंसी जमीनें भी छुड़वाई और कई रजिस्ट्रियों को शून्य करवाने के लिए कोर्ट में प्रकरण दायर किए गए। अभी पिछले दिनों 3 हजार करोड़ रुपए से अधिक कीमत की देवी अहिल्या गृह निर्माण संस्था की ढाई लाख स्क्वायर फीट से अधिक जमीनों की रजिस्ट्रियां भी कोर्ट ने शून्य घोषित कर दीं, जिसके चलते पीड़ितों को भूखंडों का आवंटन किया जा सकेगा। जिन जमीनों की रजिस्ट्रियां शून्य हुई हैं वे संस्था की कॉलोनी अयोध्यापुरी के साथ श्री महालक्ष्मी नगर की है। अभी अन्य जमीनों की रजिस्ट्रियों को शून्य करने के प्रकरण भी कोर्ट में विचाराधीन हैं, तो कुछ जमीनी जादूगर मुहिम ठंडी पड़ते ही अपने वायदे से मुकर भी गए।

इंदौर में गृह निर्माण संस्थाओं में पिछले 20 सालों में जमकर जमीनी घोटेले हुए और तीन बार शासन स्तर पर इनके खिलाफ बड़ी मुहिम भी शुरू हुई। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2008-09 में पहली मुहिम चलाई, जिसमें कई भूमाफिया जेल गए और पीड़ितों को भूखंड भी मिले। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इस तरह का ऑपरेशन भूमाफिया चलाया और उसके बाद तख्तापलट हुआ और फिर भाजपा की सरकार बनी, तब शिवराज सिंह चौहान ने ही 2021-22 में ऑपरेशन भूमाफिया फिर से शुरू करवाया। नतीजतन तत्कालीन इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने अब तक की सबसे प्रभावी कार्रवाई इस दौरान की, जिसके चलते जहां चर्चित भूमाफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई तो दीपक मद्दे सहित कई को जेल भी जाना पड़ा और उसी मुहिम का असर था कि ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इन भूमाफियाओं के खिलाफ प्रकरण बनाए और करोड़ों रुपए की संपत्तियां अटैच कर डालीं।

अभी भी हालांकि अयोध्यापुरी की केएस सिटी और सिम्प्लैक्स की लगभग साढ़े 5 एकड़ जमीन सरेंडर नहीं हो सकी है। केएस सिटी कंपनी ने तो प्रशासन को बकायदा जमीन सरेंडर करने का शपथ-पत्र भी दिया था मगर बाद में मुहिम ठंडी पड़ने पर वे अपने वायदे से पलट गए। कंपनी की ओर से आशीष गुप्ता ने देवी अहिल्या की अयोध्यापुरी की 1.47 एकड़ जमीन खरीदी और तत्कालीन अपर कलेक्टर डॉ. अभय बेडेकर के समक्ष शपथ-पत्र देकर इस जमीन को सरेंडर करने का वायदा किया, ताकि वह एफआईआर और गिरफ्तारी से बच सके। मगर मुहिम ठंडी पड़ने पर जमीन सरेंडर करने से पीछे



## 3 हजार करोड़ की जमीन माफियामुक्त

### कई रजिस्ट्रियां शून्य

देवी अहिल्या संस्था की ही सर्वे नं. 85 की 0.767 हेक्टेयर यानी लगभग 8 हजार स्क्वायर फीट से अधिक ये जमीन भी श्री महालक्ष्मी नगर में मौजूद है। इन तीनों रजिस्ट्रियों के शून्य होने से ढाई लाख स्क्वायर फीट से अधिक जमीन वापस संस्था के खाते में आ गई है, जो अब वरीयता सूची के आधार पर पीड़ितों को भूखंड के रूप में मिल सकेगी। उल्लेखनीय है कि बाजार दर के मुताबिक ये जमीनें आज 3 हजार करोड़ रुपए से अधिक कीमत की हैं, क्योंकि 10 से 15 हजार रुपए स्क्वायर फीट का बाजार भाव फिलहाल इन जमीनों का चल रहा है। यह भी महत्वपूर्ण है कि अयोध्यापुरी की ही अरुण डागरिया और अतुल सुराना के कब्जे की 70 हजार स्क्वायर फीट जमीन की रजिस्ट्री पूर्व में शून्य घोषित हो चुकी है। इसी तरह एक एकड़ जमीन शैलबाला जैन के कब्जे से भी संस्था को मिल चुकी है। अब अयोध्यापुरी संघर्ष समिति के गौरीशंकर लाखोटिया का कहना है कि सहकारिता विभाग जल्द ही वरीयता सूची जारी कर दे, ताकि जिन जमीनों की रजिस्ट्रियां शून्य होकर संस्था को वापस मिली है, कम से कम उनका कब्जा तो भूखंड पीड़ितों को दिया जा सके। इस मामले में संस्था के पीड़ितों ने कलेक्टर आशीष सिंह से भी गुहार लगाई है और साथ में प्राधिकरण से भी, ताकि योजना 171 को डीनोटीफाइड भी जल्द कर दिया जाए, जिससे कॉलोनी को वैध कराने के लिए एनओसी का रास्ता साफ हो सके।

हट गए और फिर सिर्फ 5 प्लॉट, जिसमें 6250 स्क्वायर फीट जमीन आती है, उसे ही सरेंडर करने की बात कह रहे हैं, जबकि कब्जे में 60

हजार स्क्वायर फीट जमीन है। अब प्रशासन ही इस मामले में नए सिरे से कार्रवाई करेगा। इसी तरह सिम्प्लैक्स इन्वेस्टमेंट की जमीन भी संघवी परिवार और मद्दे के पास है और ये 4 एकड़ जमीन अयोध्यापुरी कॉलोनी में शामिल है। ये जमीन भी अभी तक सरेंडर नहीं हो सकी है, जबकि इसी जमीन को लेकर संघवी परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थीं और फिर जमानत के चलते गिरफ्तारी से बचे और इस मामले में प्रतीक संघवी भी आरोपी हैं। दूसरी तरफ पिछले दिनों सहकारिता विभाग को लगभग ढाई लाख स्क्वायर फीट जमीनों की रजिस्ट्रियां कोर्ट के जरिए शून्य करवाने में सफलता मिली।

उपायुक्त सहकारिता मदन गजभिये के मुताबिक देवी अहिल्या गृह निर्माण की अयोध्यापुरी और श्री महालक्ष्मी नगर की इन जमीनों की रजिस्ट्रियां शून्य हो गई हैं, जिसमें मेसर्स मिरांडा इंटरप्राइजेस की खजराना के सर्वे नंबर 135/1, 135/3, 135/4, 136/4/1 और 137 की 2.405 हेक्टेयर यानी सवा 2 लाख स्क्वायर फीट जमीन की रजिस्ट्री कोर्ट से शून्य घोषित हो गई है और यह जमीन संस्था की कॉलोनी श्री महालक्ष्मी नगर में मौजूद है। चूंकि इतनी बड़ी जमीन संस्था को वापस मिल गई है, जिसके चलते पीड़ितों को भूखंड आवंटित करने में आसानी होगी। इसी तरह गजभिये के मुताबिक देवी अहिल्या संस्था की ही सर्वे नंबर 387/2 की लगभग 23 हजार स्क्वायर फीट जमीन, जिसकी रजिस्ट्री पूजा आशीष डोसी, छवि रोहित डोसी और अमरजीत सिंह चावला के नाम पर संस्था के कर्ताधर्ताओं ने कर दी थी, ये जमीन भी वापस संस्था को मिल गई है, जिसमें अयोध्यापुरी के पीड़ितों को भूखंड मिल सकेंगे।

● विकास दुबे

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मप्र के हर क्षेत्र में एक समान विकास का जो मॉडल बनाया है, उसकी केंद्र सरकार के साथ ही अन्य राज्य भी सराहना कर रहे हैं। इस कारण मप्र विकास का नया मॉडल बन गया है। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में मप्र की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी, वहीं रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

## विकास का मॉडल बना मध्यप्रदेश...



**दो** दशक पहले बीमारू राज्य में शामिल मप्र आज विकास का रोल मॉडल बनकर उभर रहा है। खासकर जबसे डॉ. मोहन यादव ने मप्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है, उन्होंने मप्र को विकास का नया मॉडल बनाने का अभियान शुरू कर दिया है। इसके लिए उनका प्रदेश के हर हिस्से में एक समान विकास पर फोकस है। इसके लिए उन्होंने मंत्रियों, विधायकों, सांसदों को जिम्मेदारी तो दी ही है, वहीं अफसरों को भी फ्री-हैंड देकर काम पर लगाया है। सरकार की ऐसी ही नीतियों और रणनीति का परिणाम है कि आज मप्र अब बीमारू राज्य नहीं रहा। देश के टॉप-10 धनी राज्यों में इसकी गिनती होने लगी है। मप्र 13.87 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी के साथ अर्थव्यवस्था के मामले में देश में 10वें नंबर पर आ चुका है।

मप्र की तरक्की का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मप्र 9वें नंबर पर काबिज तेलंगाना से बस 1 पायदान पीछे है। मप्र सरकार प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र को विकास का मॉडल बनाएगी। यानी हर विधानसभा क्षेत्र में आवश्यक सुविधाओं के साथ ही वह सारी सुविधाएँ मुहैया कराई जाएंगी, जो वहाँ के निवासियों में गर्व का भाव भर सके। इसके लिए सरकार विधानसभा क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से योजना बना रही है। इसके लिए हर विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए जाएंगे। जानकारी के अनुसार सरकार ने विधायकों से अपने विधानसभा क्षेत्र में कराए जाने वाले विकास कार्यों का प्रस्ताव मांगा है। विधायकों से प्रस्ताव मिलने के बाद सरकार

### इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर जोर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का इंफ्रास्ट्रक्चर विकास भी पर फोकस है। गौरतलब है कि अधोसंरचना विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में मप्र को 10,500 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। इसमें 9,750 करोड़ रुपए राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए मिलेंगे। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार ने अधोसंरचना विकास को प्राथमिकता में रखा है। इसके लिए 11.11 लाख करोड़ रुपए का प्रविधान किया है। राज्यों को अधोसंरचना निर्माण के लिए डेढ़ लाख करोड़ रुपए के दीर्घावधि ब्याज मुक्त ऋण का प्रविधान किया है। वर्ष 2029 में होने वाले सिंहस्थ के लिए मोहन सरकार ने तैयारी प्रारंभ कर दी है। श्रद्धालुओं के लिए आवागमन की सुविधा को देखते उज्जैन महाकाल रोपवे बनाया जा रहा है। इसके लिए बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रविधान किया गया है। इसी तरह पीथमपुर में विकसित किए जा रहे मल्टी मॉडल लाजिस्टिक पार्क के लिए 60 करोड़ रुपए रखे गए हैं। केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत सेतु बंधन योजना में पलाईओवर समेत अन्य परियोजनाओं की तीन हजार करोड़ रुपए की स्वीकृतियों के लिए 750 करोड़ रुपए इस वित्तीय वर्ष में दिए जाएंगे। इसी तरह भारतमाला, पर्वतमाला, एक्सप्रेस-वे समेत राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के लिए 9 हजार 750 करोड़ रुपए का अनुमानित प्रविधान किया है।

आगामी चार साल में विकास कार्यों को अमलीजामा पहुंचाने पर काम करेगी।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का पूरा फोकस प्रदेश में एक समान विकास पर है। इसके लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। दरअसल, सरकार की कोशिश है कि चार साल में विधानसभा क्षेत्रों को आदर्श बनाया जाए। स्कूल, बिजली, पानी, सड़क, नाली, सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी केंद्र समेत सभी सुविधाएँ होंगी। केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से पात्रों को लाभांशित किया जाएगा। रोजगार के लिए मेलों का आयोजन होगा तो खेलकूद की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के साथ गोवंश के संरक्षण और पर्यटन की गतिविधियों के विकास पर ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने विधायकों से विधानसभा क्षेत्र के विकास संबंधी दृष्टि पत्र मांगा है। इसे तैयार करने के लिए प्रारूप भी भेजा गया है। योजना में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे।

मप्र में सरकार चाहती है कि प्रदेश के विकास में सबकी भूमिका हो। इसके लिए सरकार ने तय किया है कि विधानसभा क्षेत्रों को आदर्श बनाया जाएगा। इसके लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दी जाने वाली राशि के साथ विधायक, सांसद निधि और कांफ़ेरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी का उपयोग किया जाएगा। जो राशि और लगानी होगी, वह सरकार अपने वित्तीय संसाधनों से लगाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सभी विधायकों को दृष्टि पत्र का प्रारूप भेजा है। इसमें बताया गया कि दृष्टि पत्र तैयार करते समय विधायक क्षेत्र की महत्वपूर्ण

समस्याओं का आकलन करें। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण, आंगनबाड़ी, कौशल विकास, पेयजल, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, यातायात, गोवंश संरक्षण, पर्यटन, रोजगार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कार्य प्रस्तावित करें। एक जिला-एक उत्पाद योजना के माध्यम से कैसे रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं, इस पर विचार अवश्य किया जाए। साक्षरता की दर बढ़ाने, शिशु एवं मातृ स्वास्थ्य में सुधार, कुपोषण में कमी लाने, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भी कार्ययोजना बनाई जाएगी। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने विधायकों से 15-15 करोड़ रुपए के क्षेत्र में विकास से संबंधित प्रस्ताव मांगे थे। अधिकतर सदस्यों ने सड़क, पुल-पुलिया, सामुदायिक भवन आदि के प्रस्ताव दिए थे, जिन्हें विभिन्न योजनाओं में सम्मिलित कर काम स्वीकृत कराए गए। विधानसभा क्षेत्र के लिए बनने वाली कार्ययोजना में केंद्र और राज्य सरकार की सभी हितग्राहीमूलक योजनाओं को शामिल किया जाएगा। सभी पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ अपात्रों को चिन्हित करने का काम भी होगा। दृष्टि पत्र के माध्यम से जो लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे वे दो और चार वर्ष की अवधि के लिए होंगे। दृष्टि पत्र के माध्यम से विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे, उनकी पूर्ति के लिए जिम्मेदारी भी तय होगी। प्रगति की नियमित जिला और राज्य स्तर पर समीक्षा की व्यवस्था रहेगी। योजना के लिए आवंटित धन का उपयोग पारदर्शी तरीके से किया जाएगा और लेखा-जोखा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध भी कराया जाएगा। सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए के काम कराने के लिए राशि की व्यवस्था अलग-अलग मदों से करेगी। इसमें 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था विधायक निधि, सांसद निधि, जनभागीदारी, कांपैरिट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी और पुनर्धनत्विकरण से की जाएगी। शेष 60 करोड़ रुपए सरकार अपने खजाने से देगी। प्रतिवर्ष 15-15 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।

प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर अपना एकाधिकार जमाने के बाद प्रदेश की भाजपा सरकार उत्साहित भी है और विकास की नई कहानी लिखने की तरफ अग्रसर हो रही है। ग्रामीण विकास को तर्जिह देने वाला एक फैसला अब प्रदेश की मोहन सरकार लेने वाली है। प्रदेश की सभी 230 विधानसभाओं में एक-एक मॉडल गांव तैयार करने के लिए अब सरकार विधायकों को उनकी विधानसभा का कोई एक गांव गोद लेने की बाध्यता करने वाली है। इसी के चलते प्रदेश की हर विधानसभा में एक-एक मॉडल गांव तैयार करने की योजना बनाई गई है। बताया जा रहा है कि इन चिन्हित



## नीतियों में हुए कई परिवर्तन

प्रदेश में विकास और रोजगार के लिए सरकार ने अपनी नीतियों में कई परिवर्तन किए हैं। उद्योगों के लिए आवश्यक सड़क, बिजली, पानी, और अधोसंरचना सहित सुशासन के हर पैमाने में मद्र निवेशकों के लिए पहली पसंद बन रहा है। किसी समय बीमारू के नाम से बंदनाम मद्र अब विकासशील राज्य की तरफ बढ़ गया है। यहां के उद्योग मित्र माहौल का ही परिणाम है कि पिछले 10 वर्षों में यहां 3 लाख करोड़ के उद्योग धंधे लगे और दो लाख युवाओं को रोजगार मिला। औद्योगिक घरानों का भरोसा जीतने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को लगातार सफलता मिल रही है। सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम, बिना अनुमति उद्योग की स्थापना सहित जो वादे उद्योग जगत से किए हैं, उन्हें धरातल पर उतारा जा रहा है। हालांकि, अब भी कुछ कमियां हैं, जैसे उद्योगों की स्थापना से जुड़े विभागों के अधिकारियों की कार्य संस्कृति में सुधार लाना पड़ेगा। ऐसा हुआ तो मद्र देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा, जहां सर्वाधिक निवेश होता है। कम लागत और बड़ा काम। यही वो तरीका है जो अर्थव्यवस्था को गति देकर मद्र की तरवीर बदल सकता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) का विस्तार सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने का माध्यम बन सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार इसे प्राथमिकता में ले और वो सभी सुविधाएं उपलब्ध कराए जो छोटे उद्योगों के लिए वातावरण बनाने का काम करें। सरकार भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है।

गांवों के समग्र विकास की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के विधायक पर होगी। इसके लिए सांसदों की तरह सभी विधायकों को भी उनकी विधानसभा क्षेत्र का एक गांव गोद लेना होगा। विधायकों द्वारा गोद लिए जाने वाले आदर्श ग्राम की प्राथमिकताओं में सड़क, पानी, सीवेज, स्वच्छता तो होगी ही। साथ ही इन गांवों में शिक्षा और स्वास्थ्य को खास महत्व दिया जाएगा। कोशिश यह भी की जाएगी कि इन गांवों में सरकारी योजनाओं के अलावा निजी सेक्टर से रोजगार के साधन मुहैया कराए जाएं। ताकि ग्रामीणों को अपनी धरती से पलायन का दंश न झेलना पड़े। मद्र को गांवों का प्रदेश कहा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक यहां 54 हजार से ज्यादा गांव मौजूद हैं। हालांकि केंद्र और प्रदेश की विभिन्न योजनाओं ने इन गांवों तक सड़क, पानी, बिजली की सुविधाएं पहुंचाई हैं। प्रदेश सरकार के नए कदम से हर विधानसभा में एक-एक गांव विकसित किया जाता है तो कुल 230 गांवों तक सुविधाएं पहुंचेंगी। इसके अलावा प्रदेश के सांसदों को भी उनकी संसदीय सीमा में एक गांव गोद लेने की व्यवस्था है। इस लिहाज से प्रदेश के ढाई सौ से ज्यादा गांव पहले से ज्यादा विकसित हो सकते हैं। पूर्व व्यवस्था के

मुताबिक प्रदेश के सांसद अपने क्षेत्र के गांव गोद तो ले लेते हैं। लेकिन इनमें से अधिकांश सांसद जिम्मेदारी लेने के बाद वे अपने कर्तव्य से विमुख ही दिखाई दिए हैं। गोद लेने के बाद कई गांवों का यह हथ्र भी हुआ है कि संबंधित सांसद पूरे कार्यकाल में उस गांव तक पहुंचे ही नहीं हैं। प्रदेश में नई व्यवस्था की शुरुआत के साथ इस बात पर ध्यान रखना भी जरूरी होगा कि संबंधित विधायक इसके प्रति गंभीरता दिखाएं।

राज्य सरकार अब सब्सिडी और सेवाओं के खर्च पर कटौती करने जा रही है, तो पूंजीगत व्यय (मशीनरी, भवन, स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधाओं) पर खर्च बढ़ाएगी। केंद्रीय बजट के बाद अधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस पर काम करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रियों और अफसरों से कहा है कि खर्चों में कटौती एवं आय बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी बजट की तुलना करते हुए भविष्य के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। सभी विभागों की बैठक कर योजनाओं के क्रियान्वयन एवं बजट के प्रावधान पर समीक्षा की जाएगी।

● डॉ. जय सिंह सेंधव

पूर्ववर्ती शिवराज सिंह चौहान की भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में काम तय रफतार के अनुसार नहीं मिल रहा है। मद्र में अगस्त 2023 से शुरू हुई योजना में अब तक 71 लाख युवाओं ने पंजीयन कराया था, लेकिन मात्र 25 हजार को ही रोजगार मिल सका। यानी रोजगार देने के सरकार के वादों पर मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना खरी नहीं उतर रही है। सरकार ने यह योजना इस दावे के साथ शुरू की थी कि एक साल में प्रदेश के एक लाख युवाओं को इससे रोजगार मिलेगा। एक साल बाद भी सिर्फ 25 हजार युवाओं को योजना से रोजगार का मौका मिल पाया है।

जब योजना की शुरुआत में अनुमान था कि कंपनियों को सीखने के साथ काम करने वाले मिलेंगे। स्टायपेंड में से मात्र 20 प्रतिशत ही उन्हें देना होता है। बाकी 80 प्रतिशत राज्य सरकार देती है। हालांकि कंपनियों ने योजना में जरा भी रूचि नहीं दिखाई। यही कारण है कि रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद भी कई कंपनियों ने न तो कोर्स मॉड्यूल बनाए और न ही वैकेंसी की घोषणा की। ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत कंपनियों को ऑनलाइन हाजिरी दर्ज करना पड़ती है, जिसके लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लगाया गया है। ऑनलाइन हाजिरी नहीं होने पर सरकार की तरफ से पैसा नहीं मिलता है। अगस्त 2023 में जहां 77 प्रतिशत आवेदकों की हाजिरी दर्ज हुई। वहीं, जून 2024 में भी यही स्थिति रही। सितंबर 2023 से मई 2024 तक जरूर 85 से 90 प्रतिशत आवेदक क्लास में पहुंचे।

आलम यह है कि इस योजना में युवा न तो सीख पा रहे हैं और न ही कमा पा रहे हैं, क्योंकि कंपनियों ने इस योजना में ठीक तरह से रिस्पॉन्स नहीं दिया। भोपाल जिले में ही योजना के तहत 6929 वैकेंसी निकली, जबकि आवेदन करने वालों की संख्या 11.56 लाख से अधिक थी। इसके बाद भी कंपनियों ने ज्यादातर आवेदन रिजेक्ट कर दिए। केवल 1163 आवेदक ट्रेनिंग प्रोग्राम जॉइन कर पाए। योजना में प्रदेशभर में 23 हजार 377 कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इनमें से 16 हजार 543 कंपनियों ने ही कोर्स शुरू किए और वैकेंसी निकालीं। इनके लिए पूरे प्रदेश में 71 लाख युवाओं के आवेदन आ गए। लाखों आवेदन पेंडिंग होने के बाद भी कंपनियों ने शॉर्ट लिस्ट करने में कंजूसी की और सिर्फ 32 हजार को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया। इनमें भी 25 हजार को रोजगार मिला है। वहीं, भोपाल जिले में 1900 से अधिक विभिन्न फर्म और कंपनियों ने योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन सभी ने इसमें रूचि नहीं ली। यही कारण है कि इनमें से 1270 कंपनियों ने ही ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए। इन्होंने 46 अलग-अलग सेक्टर के लिए 400 से अधिक कोर्स डिजाइन

बेरोजगारी मद्र की सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए करीब 1 साल पहले मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की गई थी। योजना को लेकर बड़े-बड़े दावे भी किए गए थे, लेकिन एक साल के दौरान योजना को उतनी सफलता नहीं मिली, जितने दावे किए जा रहे थे।



## सीखो कमाओ योजना फेल

### मंत्री बोले- कंपनियों के साथ करेंगे बैठक

कौशल विकास एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम टेटवाल का कहना है कि कंपनियों को क्या समस्याएं आ रही हैं, उनके साथ बैठकर समझेंगे योजना के तहत 25 हजार युवाओं को सीखने का मौका मिला। उन्हें स्टायपेंड भी दे दिया गया और अपने कौशल के अनुसार नौकरियां भी पा चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सीखने का मौका मिले, इसका प्रयास किया जा रहा है। कंपनियों में युवाओं के लगातार रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। आगे भी होते रहेंगे। इसे बंद नहीं किया जा सकता। कंपनियां जितनी वैकेंसी निकालती हैं, उसके अनुसार उन कोर्स या ट्रेड को जॉइन करने का मौका युवाओं को मिलता है। कंपनियों को क्या समस्याएं आ रही हैं, उनके साथ बैठकर समझेंगे। कंपनियों में कितने ट्रेड चल रहे हैं? कितने युवाओं को ले रही हैं? कितनों को नौकरी मिल रही है, इसकी वन-टू-वन मॉनीटरिंग की जाएगी। आने वाले सालों में युवाओं के लिए योजना में बेहतर अवसर उपलब्ध रहेंगे।

किए। इनके लिए 6929 वैकेंसी निकाली। यानी, ट्रेनिंग के लिए इतनी सीटें बताईं। स्टायपेंड मिलने के कारण करीब 166 गुना ज्यादा यानी 11.56 लाख लोगों ने आवेदन किया था। इनमें से 10.89 लाख आवेदन पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन

ट्रेनिंग देने वाली कंपनियों ने इंटरव्यू के लिए मात्र 2323 आवेदकों को ही बुलाया। इसमें से भी फाइनल लिस्ट में 1380 आवेदकों के ही नाम थे। इनमें से मात्र 1163 ही ट्रेनिंग के लिए संस्थानों में पहुंचे।

सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत मिलने वाले स्टायपेंड के लिए युवाओं ने बढ़-चढ़कर आवेदन किया। स्टायपेंड मिलने के लालच में आवेदन करने वालों में 12वीं पास या आईटीआई के अलावा इंजीनियर तक शामिल हैं। हालांकि सबसे ज्यादा आवेदन 12वीं पास की तरफ से 7.38 लाख आए, लेकिन 4.71 लाख ग्रेजुएट युवाओं ने और 41 हजार इंजीनियरों ने भी सीखने के साथ कमाई के लिए आवेदन किया। सबसे ज्यादा चार लाख से अधिक आवेदन आईटी सेक्टर के कोर्स के लिए आए। 2.56 लाख बैंकिंग सेक्टर के लिए और 1.88 लाख मैनेजमेंट के लिए आवेदन किए गए। बेरोजगारी दूर करने के दावे के साथ सीखो कमाओ योजना में निशुल्क ट्रेनिंग के साथ पात्र आवेदकों को हर महीने 8 से 10 हजार रुपए स्टायपेंड भी दिया जाता है। सरकार ने एक लाख युवाओं को हर साल रोजगार देने का दावा किया था। योजना में अलग-अलग क्षेत्रों की अलग-अलग कंपनियों ने नामांकन किया और कई ट्रेड में ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किए। ट्रेनिंग पूरी होने पर संबंधित कंपनी या किसी अन्य कंपनी में युवाओं को नौकरी मिल सकती है।

● अरविंद नारद



सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ग्वालियर-आगरा एक्सप्रेस वे (सिक्सलेन ग्रीनफील्ड हाईवे) की डीपीआर तैयार हो गई है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही आगरा से ग्वालियर के बीच सिक्स लेन ग्रीन फील्ड हाईवे बनेगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट में मुरैना के किसान बड़ी बाधा बन गए हैं। मुरैना के किसानों का एक समूह सिक्सलेन ग्रीनफील्ड हाईवे के लिए जमीन देने को तैयार नहीं है। इससे इस प्रोजेक्ट पर खतरा मंडराने लगा है। जबकि इस प्रोजेक्ट के बनने से किसानों को भी फायदा होगा। अभी तक आगरा से ग्वालियर आने में तीन घंटे लगते हैं। पर इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद सिर्फ डेढ़ घंटे में आ सकेंगे। इससे मप्र, राजस्थान व उप्र के लोगों को लाभ मिलेगा।

ग्वालियर-आगरा एक्सप्रेस-वे के लिए निविदाएं आमंत्रित कर दी गई हैं। इससे औद्योगिक क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन ग्रीनफील्ड सिक्सलेन एक्सप्रेस-वे मुरैना में जमीनों के अधिग्रहण के मुद्दे पर फंस गया है। एक्सप्रेस-वे के लिए प्रशासन की कार्रवाई जमीन अधिग्रहण के अंतिम चरण यानी मुआवजा वितरण तक पहुंच चुकी है, लेकिन अधिकांश किसान मुआवजा के लिए बैंक खाता, आधार कार्ड व अन्य जरूरी दस्तावेज नहीं दे रहे। किसानों का कहना है कि सरकार जमीन के बदले एक हेक्टेयर का कलेक्टेट रेट 10 लाख तक दे रही है जबकि गांवों में कीमत 50 लाख तक पहुंच गई है। मुरैना में किसानों की इसी तरह की असहमति व विरोध के कारण मप्र, उप्र और राजस्थान को जोड़ने के लिए प्रस्तावित अटल प्रगति पथ की प्रक्रिया भी लगभग एक साल से ठंडे बस्ते में चली गई है।

ग्वालियर-आगरा ग्रीनफील्ड सिक्सलेन एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए मप्र के ग्वालियर, मुरैना, राजस्थान के धौलपुर और उप्र के आगरा में जमीनों का अधिग्रहण होना है, इनमें सबसे अधिक मुरैना जिले में 42 गांवों में जमीन को अधिग्रहण के लिए चिन्हित किया गया है। मुरैना ब्लॉक के 22 गांवों के 6765 किसानों की 180.9205 हेक्टेयर जमीन और अंबाह ब्लॉक के तीन गांवों के 582 किसानों की 20.2470 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित कर मुआवजा देना है, लेकिन इन 7347 किसानों में से प्रशासन को 2645 किसानों के बैंक खाते व अन्य जानकारी ही उपलब्ध हो पाई हैं, इनमें से भी अधिकांश किसानों का आरोप है कि प्रशासन ने यह जानकारी पीएम किसान सम्मान निधि के उनके रिकार्ड से उठा ली है। जिसमें उनकी सहमति नहीं है। 17 गांवों में करीब 3000 किसान तो अधिग्रहण के लिए जमीन का सर्वे करने तक का विरोध कर रहे हैं। मुरैना एसडीएम भूपेंद्र सिंह का कहना है कि जल्द से जल्द भूमि अधिग्रहण की



## खर्च होंगे 2000 करोड़

वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए बड़ा प्रोजेक्ट प्लान किया गया है। मप्र से होकर गुजर रहे दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को उज्जैन से जोड़ा जाएगा। इसके लिए फोरलेन रोड बनाई जाएगी। प्रोजेक्ट पर 2 हजार करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसके निर्माण के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है। मप्र रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने यह योजना तैयार की है। शुरुआती योजना के मुताबिक जावरा से उज्जैन के बीच फोरलेन ग्रीनफील्ड मार्ग का निर्माण किया जाएगा। इसके दोनों ओर यात्रियों की सुविधा के लिए फूड प्लाजा समेत अन्य सुविधाएं जुटाई जाएंगी। इसकी लंबाई लगभग 85 किमी होगी। यह एक्सेस कंट्रोल रहेगा। यानि हर कहीं से वाहन इस रोड पर नहीं आ सकेंगे। इससे वाहन न केवल तेज रफतार से चल सकेंगे बल्कि दुर्घटना की आशंका भी कम हो जाएगी। यह रोड बनने से हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से उज्जैन की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी और सिंहस्थ में आने वाले श्रद्धालुओं की दिक्कत नहीं होगी।

प्रक्रिया पूरी करने के लिए किसानों को समझाइश देकर उनसे दस्तावेज लेने का प्रयास कर रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि रिकार्ड से किसानों के खाता नंबर ले रहे हैं। आधार कार्ड और पेन कार्ड की जानकारी किसान से लेनी है जो कई किसानों से नहीं मिल पा रही। देहात क्षेत्र होने के कारण जमीनों की सरकारी दर कम है, इसीलिए मुआवजा राशि उसी हिसाब से है। इस संबंध में भी शासन को अवगत कराया जाएगा। गौरतलब है कि चंबल अंचल के मुरैना, रघोपुर और भिंड जिलों से होकर 199 किमी का सिक्सलेन एक्सप्रेस-वे अटल प्रगति पथ भी प्रस्तावित है। मप्र, उप्र और राजस्थान को जोड़ने वाले भारत माला परियोजना के तहत बजट भी स्वीकृत हो गया, तीन बार सर्वे हो गया और अंतिम सर्वे

अलाइनमेंट में चंबल के किसानों ने जमीन अधिग्रहण का ऐसा विरोध किया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 27 मार्च 2023 को सर्वे को निरस्त कर दिया। 16 माह से यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में है। कागजों में न पुराना सर्वे निरस्त हुआ, न नया सर्वे हो रहा।

ग्वालियर-मुरैना-आगरा होकर दिल्ली से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 44 पर क्षमता से तीन गुना तक वाहन दौड़ रहे हैं, इस कारण हादसों का ग्राफ भी लगातार बढ़ रहा है। इसीलिए आगरा से लेकर ग्वालियर तक ग्रीनफील्ड सिक्सलेन एक्सप्रेस-वे को सरकार ने मंजूरी दी है। 4600 करोड़ से ज्यादा में बनने वाले इस एक्सप्रेस-वे से ग्वालियर से आगरा की दूरी 120 किमी से घटकर 88 किमी रह जाएगी। सड़क मार्ग से ग्वालियर से आगरा पहुंचने में ढाई से पौने तीन घंटे का जो समय लगता है, वह सफर एक घंटे में पूरा हो जाएगा और लगातार बढ़ रहे हादसों में भी कमी आएगी। यह सिक्सलेन एक्सप्रेस-वे यमुना एक्सप्रेस-वे से कनेक्ट होगा, जिससे दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक का सफर आसान हो जाएगा।

उधर, चार साल बाद होने वाले सिंहस्थ के लिए उज्जैन को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ा जा रहा है, ताकि श्रद्धालु सुगमता से यहां पहुंच सकें। इसी कड़ी में मालवा क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाले दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से इंदौर, उज्जैन को भी जोड़ा जा रहा है। देवास, उज्जैन और गरोठ के बीच नया फोरलेन रोड बनाकर इंदौर को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ा जा रहा है। गौरतलब है कि मप्र के मालवा क्षेत्र से देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस-वे दिल्ली-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस-वे गुजर रहा है। यह एक्सप्रेस-वे प्रदेश के तीन जिलों मंदसौर (102 किमी), रतलाम (90 किमी) और झाबुआ (52 किमी) से गुजरेगा। प्रदेश के इन तीन जिलों में एक्सप्रेस-वे की लंबाई कुल 245 किमी है। 245 किमी में 106 किमी रोड बनकर तैयार है जबकि बाकी नवंबर 2024 तक पूरा होगा।

● रजनीकांत पारे

**आ**धुनिक दुनिया में इससे ज्यादा बड़ी विडंबना क्या होगी कि हर 11वां इंसान अभी भी खाली पेट सोने को मजबूर है।

मतलब कि दुनिया में 73.3 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिन्हें भरपेट खाना नसीब नहीं हो रहा है। यदि 2019 की तुलना में देखें तो इन लोगों की संख्या में 15.2 करोड़ का इजाफा हुआ है। अफ्रीका में स्थिति कहीं ज्यादा खराब है, जहां हर पांचवा इंसान भुखमरी का सामना करने को मजबूर है। यह जानकारी दुनिया में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति पर जारी एक नई रिपोर्ट में सामने आई है। द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2024 नामक यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ), अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी), यूनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने संयुक्त रूप से प्रकाशित की है।

रिपोर्ट में जो आंकड़े साझा किए गए हैं वो खाद्य सुरक्षा की एक गंभीर तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इनके मुताबिक दुनिया में 233 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिन्हें नियमित तौर पर पर्याप्त भोजन हासिल करने के लिए जूझना पड़ रहा है। इनमें 86.4 करोड़ लोग वो हैं जिन्हें गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा। इसका मतलब है कि उन्हें कुछ समय बिना खाए ही गुजारा करना पड़ा है। रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि वैश्विक खाद्य असुरक्षा की स्थिति अभी भी कोविड-19 से पहले के स्तर से कहीं ज्यादा है। दरअसल पिछले चार वर्षों में यह स्तर करीब-करीब स्थिर बना हुआ है या इसमें मामूली सुधार देखा गया है। वास्तविकता में देखें तो पोषण के मामले में दुनिया 15 साल पीछे चली गई है और कुपोषण का स्तर 2008-2009 के स्तर पर पहुंच चुका है। हालांकि देखा जाए तो यह स्थिति तब है जब सतत विकास के लक्ष्यों के तहत 2030 तक किसी को खाली पेट न सोने देने की बात कही गई थी। मतलब की इन 6 वर्षों में दुनिया को एक लंबा सफर तय करना है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यदि मौजूदा रुझान जारी रहते हैं तो 2030 तक करीब 58.2 करोड़ लोगों को लंबे समय तक कुपोषण से जूझना होगा। यह स्थिति अफ्रीका के लिए कहीं ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि इनमें से करीब आधे लोग अफ्रीकी महाद्वीप के होंगे। इस बारे में खाद्य एवं कृषि संगठन के मुख्य अर्थशास्त्री मैक्सिमो टोरेरो का कहना है कि, असल बात ये है कि हम अभी भी दुनिया को भुखमरी, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण से छुटकारा दिलाने के लक्ष्य की दिशा में बाँधित रफ्तार से काफी पीछे हैं। क्षेत्रीय रुझानों पर नजर डालें तो अफ्रीका में स्थिति लगातार बदतर हुई है। वहां की 20 फीसदी से ज्यादा आबादी खाने की कमी से जूझ रही है। वहीं एशिया में स्थिति स्थिर बनी हुई है, जहां यह आंकड़ा 8.1 फीसदी

# हर 11वां इंसान भुखमरी का शिकार



## 9 वर्षों में 2 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए

देश में पिछले 9 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। इसमें मग्न में 2 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। नीति आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की रिपोर्ट जारी की है। इस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह डबल इंजन सरकार की बेहतर नीतियों का असर है, जिसके कारण गरीबों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की रिपोर्ट पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और नागरिकों की सहभागिता से बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। हमारी सरकार अत्योदय के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने आम आदमी के हित में कई योजनाएं चलाई हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया है कि इनका लाभ पात्र व्यक्तियों को मिले। विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी पात्र हितग्राहियों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवाना सुनिश्चित किया जा रहा है।

दर्ज किया गया है। हालांकि दक्षिण अमेरिका में इस दिशा में कुछ प्रगति जरूर हुई है। वहां करीब 6.2 फीसदी लोग खाने की कमी से त्रस्त हैं। यदि 2022-23 के दरमियान देखें तो पश्चिमी एशिया, कैरीबियाई देशों और अफ्रीका के अधिकांश हिस्सों में स्थिति पहले से खराब हुई है। अफ्रीका की 58 फीसदी आबादी किसी न किसी रूप में खाद्य असुरक्षा से प्रभावित है।

दुनिया में स्वस्थ आहार तक पहुंच भी एक गंभीर मुद्दा है, जो दुनिया की एक तिहाई आबादी को प्रभावित कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में करीब 280 करोड़ से ज्यादा लोग पोषण युक्त आहार का खर्च उठा पाने में असमर्थ थे। यह समस्या कमजोर देशों में कहीं ज्यादा गंभीर है, जहां 71.5 फीसदी आबादी स्वस्थ पोषण युक्त आहार का खर्च उठा पाने में असमर्थ है। हालांकि समृद्ध देशों में स्थिति पूरी तरह अलग है, जहां यह आंकड़ा 6.3 फीसदी दर्ज किया गया है। देखा जाए तो एशिया, उत्तरी अमेरिका और यूरोप में महामारी से पहले की तुलना में स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन अफ्रीका में स्थिति कहीं ज्यादा खराब हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में पोषण से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी प्रकाश डाला है। उदाहरण के लिए वैश्विक स्तर पर स्तनपान की दर में वृद्धि

हुई है, जो बढ़कर 48 फीसदी पर पहुंच गई है। लेकिन वैश्विक स्तर पर पोषण के लक्ष्यों को हासिल करना अभी भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के 15 फीसदी बच्चे अभी भी वजन में कमी की समस्या से ग्रस्त हैं। वहीं 5 वर्ष से कम आयु के 22.3 फीसदी बच्चे अपनी आयु के हिसाब से ठिगने हैं। मतलब कि इस मामले में हम अभी भी लक्ष्यों से दूर हैं। वहीं कमजोरी का शिकार बच्चों की संख्या में कोई खास सुधार नहीं हुआ है, जबकि महिलाओं में एनीमिया की समस्या पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। दुनिया में मोटापे की समस्या भी तेजी से पैर पसार रही है। ताजा आंकड़ों से पता चला है कि वयस्कों में मोटापे की जो दर्ज 2012 में 12.1 फीसदी थी, वो 2022 में बढ़कर 15.8 फीसदी पर पहुंच गई है। अनुमान दर्शाते हैं कि दुनिया में 2030 तक 120 करोड़ से ज्यादा वयस्क इस समस्या से जूझ रहे होंगे। देखा जाए तो दुनिया में लोग बढ़ते वजन और मोटापे की दोहरी मार झेल रहे हैं। यह समस्या सभी आयु वर्गों में बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दो दशकों में दुबलेपन और कम वजन का शिकार लोगों की संख्या में कमी आई है, वहीं दूसरी तरफ मोटापे से जूझ रही आबादी तेजी से बढ़ रही है।

● जितेंद्र तिवारी

**मु**ख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मप्र के हर क्षेत्र में एक समान विकास का जो मॉडल बनाया है, उसको देखते हुए तकरीबन 7 माह बाद प्रदेश सरकार के मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंपा गया है। प्रदेश आने वाले समय में तरक्की की और ऊंची छलांग लगाते हुए देश की अर्थव्यवस्था में अपना बहुमूल्य योगदान देगा। मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंपने में ऐसे कई तरह के समीकरणों को ध्यान में रखा गया है। एक तरफ जहां वरिष्ठ मंत्रियों को दो-दो जिलों का प्रभार सौंपा गया है, वहीं सिंधिया समर्थक मंत्रियों को उनकी प्राथमिकता के अनुसार जिले का प्रभार सौंपा गया है। भाजपा सूत्रों की मानें तो पहली बार जिला प्रभारी मंत्रियों की सूची केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने फाइनल की। मंत्रियों को आवंटित जिलों की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तासीर देखने से स्पष्ट हो जाता है कि मुख्यमंत्री ने प्रभारी मंत्री बनाते समय पॉलिटिकल विजन का पूरा ध्यान रखा है। इसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन ने इंदौर जिले का प्रभार अपने पास रखा है। उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल सागर और शहडोल के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। वहीं, जगदीश देवड़ा को जबलपुर और देवास जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। कांग्रेस से भाजपा में आकर मंत्री बने रामनिवास रावत को मंडला और दमोह जिले का जिम्मा दिया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के सभी बड़े नेताओं को साथ में लेकर चलने की कोशिश की है। इसी के साथ उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा है कि प्रभारी मंत्रियों की वजह से प्रदेश की आर्थिक विकास की गति और तेज हो। संगठन की दृष्टि से भी प्रभारी मंत्रियों का आवंटन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि प्रभारी मंत्री एक तरह से जिले के मुख्यमंत्री की तरह शक्तिशाली होते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग की शक्तियां प्रभारी मंत्री के पास रहती हैं। जिला योजना समिति की बैठकों में प्रभारी मंत्री अध्यक्षता करते हैं तो जिला कलेक्टर सचिव होते हैं। यानी कार्यकर्ताओं से संबंधित सभी काम प्रभारी मंत्री के पास होते हैं। जाहिर है मुख्यमंत्री ने जिला प्रभार आवंटित करते समय संगठन की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा है। मंत्रियों को दिए जिलों के प्रभार में भी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पावर अपने हाथ में ही रखा है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर जिले का प्रभार मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है। वहीं राजधानी भोपाल जिले की कमान चैतन्य काश्यप को दी है। माइनिंग के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण सिंगरौली जिले का प्रभार संपतिया उईके को दिया है।

केंद्रीय मंत्री संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के क्षेत्र में उनके ही करीबी मंत्रियों को जिलों का प्रभार दिया गया है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट को फिर से ग्वालियर का प्रभारी



## अब और तेज होगा विकास

### 8 मंत्रियों को एक जिले का प्रभार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वरिष्ठ मंत्रियों को दो जिलों का प्रभार दिया है। बाकी 8 मंत्रियों को केवल एक जिले का प्रभारी बनाया गया है। इनमें धर्मद्र सिंह लोधी को खंडवा, दिलीप जायसवाल को सीधी, गौतम टेटवाल को उज्जैन, नारायण सिंह पंवार को रायसेन, नरेंद्र शिवाजी पटेल को बैतूल, प्रतिभा बागरी को डिंडोरी, दिलीप अहिरवार को अनूपपुर और राधा सिंह को मैहर जिले का प्रभारी बनाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर का प्रभार अपने पास रखा है। मोहन सरकार ने सीनियर नेताओं को तवज्जो देते हुए दो जिलों का प्रभार दिया है। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को सतना और धार दो जिलों का प्रभार सौंपा है। इसके अलावा उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को जबलपुर, देवास और राजेंद्र शुक्ल को सागर व शहडोल का जिम्मा दिया गया। मंत्री कुंवर विजय शाह को रतलाम, झाबुआ, प्रहलाद पटेल को भिंड, रीवा, राकेश सिंह को छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, मंत्री करण सिंह वर्मा को मुरैना, सिवनी, मंत्री उदय प्रताप सिंह को बालाघाट, कटनी, मंत्री संपतिया उईके को सिंगरौली, अलीराजपुर, तुलसी सिलावट को ग्वालियर, बुरहानपुर, एदल सिंह कंसाना को दतिया, छतरपुर, निर्मला भूरिया को मंदसौर, नीमच, गोविंद सिंह राजपूत को नरसिंहपुर, गुना, विश्वास सारंग को खरगोन, हरदा, नारायण सिंह कुशवाह को शाजापुर, निवाड़ी, नागर सिंह चौहान को आगर और उमरिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर को शिवपुरी, पांडुरंग का प्रभार सौंपा गया है। चेतन कश्यप को भोपाल और राजगढ़ के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। वहीं इंदर सिंह परमार को पन्ना, बड़वानी, राकेश शुक्ला को श्योपुर, अशोकनगर, रामनिवास रावत को मंडला, दमोह, कृष्णा गौर को सीहोर, टीकमगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। वहीं धर्मद्र सिंह लोधी को खंडवा, दिलीप जायसवाल को सीधी, गौतम टेटवाल को उज्जैन, लखन पटेल को विदिशा, मऊगंज, नारायण सिंह पवार को रायसेन, नरेंद्र शिवाजी पटेल को बैतूल, प्रतिभा बागरी को डिंडोरी, दिलीप अहिरवार को अनूपपुर और राधा सिंह को मैहर का प्रभार सौंपा है।

मंत्री बनाया गया है। सिलावट को बुरहानपुर की भी जिम्मेदारी मिली है। सिंधिया के दूसरे करीबी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को गुना और नरसिंहपुर की जिम्मेदारी मिली है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को इस बार शिवपुरी और पांडुरंग का प्रभार मिला है। तोमर पिछली सरकार में गुना के प्रभारी मंत्री थे।

मंत्रियों को जिलों का प्रभार देने में विकास पर भी ध्यान दिया गया है। प्रदेश का प्रमुख फाइनेंशियल पावर सेंटर यानी आर्थिक राजधानी इंदौर जैसा सबसे महत्वपूर्ण जिला मुख्यमंत्री ने खुद अपने पास रखा है। इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि इंदौर जिले में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पत्ता चलेगा। कैलाश विजयवर्गीय जैसे अत्यंत कुशल और विकास का जबरदस्त विजन और मादा रखने वाले मंत्री को सतना और धार जिला दिया गया है। सतना जिले में प्रदेश सरकार का अत्यंत महत्वाकांक्षी चित्रकूट प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। चित्रकूट को अयोध्या की तरह ही विकसित करने की योजना बनाई गई है। जाहिर है कि इस जिले की जवाबदारी अब कैलाश विजयवर्गीय के पास रहेगी। वैसे भी सतना जिला जातीय समीकरणों के कारण भाजपा के लिए जटिल रहा है। लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनावों में सतना जिले में भाजपा का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा है। धार भी भाजपा के लिए कठिन जिला है। 2018 के बाद 2023 के विधानसभा चुनाव में भी धार जिले की आदिवासी सीटों पर भाजपा को नुकसान हुआ है। इसके अलावा भोजशाला विवाद के कारण भी धार जिला संवेदनशील है। यह जिला भी कैलाश विजयवर्गीय जैसे राजनीतिक रूप से कुशल और कड़ावर मंत्री को दिया गया है। इसी तरह विदिशा, भोपाल और सीहोर जिलों को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक तरह से गृह क्षेत्र माना जाता है। उनके वर्चस्व वाले इन तीनों जिलों के प्रभारी मंत्री उन्हीं के समर्थक हैं।

● लोकेश शर्मा

विधानसभा और लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड जीत दिलाने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं को पद और प्रतिष्ठा देकर भाजपा संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। पार्टी करीब 2 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को ताकत देने जा रही है। वहीं करीब 10 हजार निष्ठावान कार्यकर्ताओं को साहब बनाने का प्लान तैयार किया गया है।

म प्र वह राज्य बन चुका है, जहां अपनी जमीनी पैठ को लेकर भाजपा पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रही है। दरअसल, 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बंपर जीत हासिल की, उसके ठीक बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने क्लीन स्वीप करते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया। देशभर में मप्र में भाजपा अगर मजबूत है तो उसकी एक बड़ी वजह है, मप्र भाजपा के नेता और कार्यकर्ता। अब खबर आ रही है कि भाजपा इन्हें बड़ा इनाम देने जा रही है। भाजपा के कार्यकर्ता यानी कि संगठन से जुड़े हुए वे लोग जो लगातार संगठन में सक्रिय रहते हैं और पार्टी के लिए जी जान से कार्य करते हैं। चर्चा हो रही है कि लगातार चुनाव जीतती आ रही भाजपा अगर अभी भी अपने कार्यकर्ताओं के हितों की ओर ध्यान नहीं देगी, तो पार्टी में बड़े स्तर पर कोई असंतोष पनप सकता है। इसीलिए भाजपा ने यह असंतोष पनपे, उससे पहले ही एक नया रोडमैप तैयार कर लिया है। यह रोडमैप पार्टी के प्रति वफादार कार्यकर्ताओं को इनाम देने का है। इनाम से मतलब यहां नगद राशि नहीं, बल्कि अलग-अलग जो समितियां होंगी, जो निगम मंडल होंगे, उनमें कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय करने की तैयारियों में पार्टी जुट गई है।

विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाजपा को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को पार्टी अब सरकारी मशीनरी (एल्डरमैन, समितियों) का हिस्सा बनाने जा रही है। इसके लिए जिलाध्यक्षों से पार्टी के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ताओं का नाम मांगा गया है। गौरतलब है कि भाजपा कैडर बेस पार्टी और कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ माने जाते हैं। इसलिए पार्टी की कोशिश है कि कार्यकर्ताओं को सरकार में जिम्मेदारी देकर उनका मनोबल बढ़ाया जाए। मप्र में निगम और मंडलों की नियुक्तियां होती हैं। यह समितियां सिर्फ निगम और मंडलों तक नहीं, बल्कि ग्राम पंचायत स्तर तक जाती हैं। ऐसे में भाजपा की अब यह कोशिश है कि ग्राम पंचायत स्तर से लेकर निगम मंडलों तक, उसके जो कार्यकर्ता हैं उन्हें एक तरीके से चिन्हित किया जाए और उन्हें इन समितियों में जगह भी दी जाए। बीते दिनों हुई प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक के बाद भाजपा नेताओं से संकेत मिले थे कि पार्टी के समर्पित और अच्छा काम करने वाले नेताओं कार्यकर्ताओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। निगम मंडलों में नियुक्तियां हो या



## अब भाजपा कार्यकर्ताओं की बारी

### निगम-मंडलों की कुर्सी

प्रदेश में करीब छह माह से निगम-मंडल-प्राधिकरणों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की नियुक्ति की राह देख रहे नेताओं की जल्द ही लॉटरी लगने वाली है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा हाईकमान ने राजनीतिक नियुक्तियों के लिए हरी झंडी दे दी है। साथ ही कहा गया है कि निष्ठावान वरिष्ठ नेताओं को निगम-मंडल और प्राधिकरणों में पदस्थ किया जाए। गौरतलब है कि इन दिनों प्रदेशभर के भाजपा नेताओं के भोपाल से लेकर दिल्ली तक के फेरे बढ़ गए हैं। यह नेता अपने साथ अपनी उपलब्धियों के ब्यौरे के साथ ही पूर्व में मिले आश्वासनों का पुलिंदा लेकर भी चल रहे हैं। उन्हें सत्ता में भागीदारी के लिए जो नेता मददगार साबित होने वाला लगता है, उसे अपनी बायोडाटा वाली फाइल थमा दी जाती है। यह वे नेता हैं, जिन्हें विधानसभा और लोकसभा चुनाव में दावेदारी के बाद भी टिकट नहीं दिया गया था। यही वजह है कि अब यह नेता चाहते हैं कि उन्हें निगम मंडल में भागीदारी मिल जाए। भाजपा सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद से निगम मंडलों में अपनी ताजपोशी का इंतजार कर रहे नेताओं की उम्मीद जल्द पूरी हो सकती है। पार्टी हाईकमान ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है।

समितियों में जगह देने की बात हो, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो सत्तारूढ़ दल होता है, उनके कार्यकर्ताओं को उसमें प्राथमिकता दी भी जाती है। फिलहाल माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मप्र में अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करेगी।

उप्र में लोकसभा चुनावों में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा से उपजी नाराजगी का असर देखते हुए मप्र भाजपा संगठन अब अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की तैयारी में जुट गया है। पार्टी ने इसके लिए खास प्लान तैयार किया है। अब भाजपा कार्यकर्ता साहब बनेंगे। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए भाजपा इन कार्यकर्ताओं को बोर्ड, निगम, आयोग, निकाय, सहकारी समितियों और अंत्योदय समितियों में मौका देगी। भाजपा का लक्ष्य कि वह हर मंडल से कार्यकर्ता का समायोजन करे। मप्र भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। पार्टी 10 हजार से ज्यादा सक्रिय कार्यकर्ताओं को सरकार में शामिल करेगी। इसकी तैयारियों की जा रही हैं। भाजपा नेतृत्व नगरीय निकायों में एल्डरमैन, समितियों और कॉलेजों की जनभागीदारी समितियों में कार्यकर्ताओं को नियुक्त कर रही है। इस मामले को लेकर पार्टी पदाधिकारियों ने जिला प्रभारियों और जिलाध्यक्षों के साथ एक बैठक की है। इस बैठक में जिलाध्यक्षों को कहा गया है कि वे अपने-अपने जिलों में सभी नेताओं के साथ समन्वय स्थापित करें। इसके बाद उनके साथ

मिलकर समितियों में नियुक्ति के लिए कार्यकर्ताओं के नाम तय करें। ये नाम तय हो जाने के बाद उन्हें प्रदेश संगठनों को भेजा जाएगा। गौरतलब है कि जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता अक्सर पार्टी पदाधिकारियों को ये शिकायत करते हैं कि विधायक, मंत्री और सांसद बन जाने के बाद उन लोगों की नियुक्ति को भुला या टाल दिया जाता है। कार्यकर्ताओं की इस बात को पार्टी ने गंभीरता से लिया है। इसलिए अब भाजपा इन नियुक्तियों को लेकर देर नहीं करना चाहती। बता दें, राज्य के हर विभाग में समितियां होती हैं। इन समितियों में अशासकीय सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। इन्हीं समितियों में इन कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया जाएगा।

जानकारी के अनुसार, प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित वरिष्ठ नेताओं की बैठक के बाद जिलाध्यक्षों व जिला प्रभारियों के साथ एक अलग बैठक हुई। इस बैठक में जिलाध्यक्षों को कहा गया है कि वे जिले में सभी नेताओं से समन्वय करके अलग-अलग समितियों में नियुक्ति के लिए कार्यकर्ताओं के नाम तय करके प्रदेश संगठन को भेजेंगे। जिन्हें विभिन्न समितियों में पदाधिकारी बनाया जाएगा। दरअसल, भाजपा अब अपने 10 हजार से ज्यादा सक्रिय कार्यकर्ताओं को सरकार में एडजस्ट करने की तैयारी कर रही है। सभी नगरीय निकायों में एल्डरमैन से लेकर कॉलेजों की जनभागीदारी समितियों, दीनदयाल अंत्योदय समितियों सहित अन्य समितियों में पार्टी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार, नई सरकार के गठन के बाद से कार्यकर्ताओं की सत्ता में भागीदारी का इंतजार हो रहा है। पार्टी ने संकेत दिया है कि कुछ दिनों में मंत्रियों को जिलों के प्रभार बंट जाएंगे। इसके बाद जिलों की कोर कमेटियों का भी पुनर्गठन होगा। चुनाव मैदान में काम करने वाले कार्यकर्ताओं की शिकायत होती है कि सांसद, विधायक और मंत्री बन जाने के बाद अन्य नियुक्तियों को टाला जाता है। संगठन इस बार इस मामले में देरी करने के मूड में नहीं है। सरकार के विभिन्न विभागों की हर स्तर की समितियां जहां अशासकीय सदस्य नियुक्त करने



का प्रावधान है उनमें पार्टी कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए जिलाध्यक्ष से लेकर पार्टी के सीनियर नेता प्रशासन से संपर्क करेंगे ताकि हर स्तर पर नियुक्ति की प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा सके।

भाजपा सरकार के पिछले करीब दो दशक में यह पहला अवसर होगा, जब सत्ता में कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। लगभग 33 साल पहले तत्कालीन सुंदरलाल पटवा सरकार में ये समितियां बनाई गई थीं। गौरतलब है कि उग्र में लोकसभा चुनाव में आए विपरीत परिणाम और कार्यकर्ताओं में उपजे असंतोष से सीख लेते हुए मप्र में कार्यकर्ताओं की सरकार में भागीदारी सुनिश्चित करने की तैयारी की जा रही है। पार्टी की योजना है कि अगले छह महीनों में ग्राम पंचायत से लेकर राजधानी तक कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाकर उन्हें जिम्मेदारी दे दी जाए। मप्र भाजपा के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल का कहना है कि प्रदेश सरकार के विविध प्रकार के सार्वजनिक उपक्रम समितियां मंडल निगम में अशासकीय सदस्यों की नियुक्तियां की जाती हैं। यह शासन के नियम अनुसार होती हैं। वास्तव में यह प्रक्रिया जनता और सरकार के बीच पुल का कार्य करती हैं। शासन की गति तेज होती है। अंत्योदय समितियां और सहकारिता उनमें एक हैं। इनमें कौन लोग होंगे और पद्धति क्या होगी

यह तय करने का अधिकार प्रदेश सरकार को है।

गौरतलब है कि कार्यकर्ताओं के बल पर भाजपा बड़ी पार्टी बनी है। इसलिए सत्ता में कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाने के मॉडल पर काम कर रही भाजपा सरकार ने सरकारी योजनाओं की राजधानी से ग्राम पंचायत स्तर तक निगरानी के लिए दीनदयाल अंत्योदय समितियों के पुनर्गठन का रास्ता साफ कर दिया है। दीनदयाल अंत्योदय समितियों में राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री और जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री अध्यक्ष होंगे। हर स्तर पर गठित समितियों में एससी और एसटी वर्ग की महिलाओं के लिए पद आरक्षित रहेंगे। पहले चरण में गांव से राजधानी भोपाल तक दीनदयाल अंत्योदय समितियों का गठन किया जाएगा। राज्य स्तरीय समिति में यथासंभव हर वर्ग की प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इसके जरिए पांच लाख भाजपा कार्यकर्ताओं को सत्ता में भागीदार बनाया जाएगा। वर्ष 1991 में भाजपा की सरकार के दौरान ये समितियां काम करती थीं। नए मॉडल में समितियां राज्य, जिला, नगर, विकासखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर होंगी। प्रदेश में पंचायतों की बड़ी संख्या होने और जिला व राज्य स्तर पर इन समितियों के गठन से भाजपा से जुड़े कार्यकर्ता इस काम से जुड़ जाएंगे।

● श्याम सिंह सिकरवार

## सहकारी समितियों की मिलेगी कमान

50 लाख से अधिक किसान सहकारी समितियों के चुनाव बार-बार टलने के बाद भाजपा ने समितियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए फॉर्मूला तैयार कर लिया है। इस फॉर्मूले के तहत अब सहकारी समितियों में प्रशासकों की जगह भाजपा नेताओं को पदस्थ किया जाएगा। इसको लेकर गत दिनों भाजपा कार्यालय में प्रदेशभर से आए सहकारी नेताओं ने प्रदेश संगठन के साथ बैठक कर मसौदा तैयार किया है। गौरतलब है कि प्रदेश में सहकारी समितियों के चुनाव लंबे समय से नहीं हो पा रहे हैं। हाईकोर्ट के निर्देश पर इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हुई, लेकिन सदस्य सूची ही नहीं बन पाई, इसलिए चुनाव फिर टल गए हैं। खरीफ फसलों की बोवनी में किसानों के व्यस्त होने के कारण कार्य प्रभावित हुआ। उधर, हाईकोर्ट के दबाव में सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं। इसके तहत निर्वाचन की बजाय संचालक मंडलों के सदस्य नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में वर्ष 2013 में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और अपेक्स बैंक के चुनाव हुए थे। इसके बाद से प्रशासक ही पदस्थ हैं। सहकारिता चुनाव को लेकर सरकार पर अदालत का दबाव बना हुआ है।

म प्र के वनों पर बढ़ते जैविक दबाव, बढ़ती जनसंख्या तथा कृषि हेतु जमीन की बढ़ती भूख के कारण वन क्षेत्रों में अतिक्रमण एक गंभीर समस्या है। वर्तमान में संगठित एवं हिंसक अतिक्रमण के प्रयास भी हो रहे हैं। कई अशासकीय संगठनों द्वारा भी वन क्षेत्र में अतिक्रमण को प्रोत्साहित करने की घटनाएं भी प्रकाश में आई हैं। केवल

मप्र ही नहीं देश के सभी राज्यों में वन क्षेत्रों पर अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।

गौरतलब है कि पूरा मामला देश के विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने पर वन क्षेत्रों पर होते अतिक्रमण से जुड़ा है। अपने आदेश में ट्रिब्यूनल ने उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है, जिन्होंने अब तक वन अतिक्रमण के मुद्दे पर अपना जवाब नहीं दिया है कि वे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अपना जवाब प्रस्तुत करें। इसके साथ ही अदालत ने पर्यावरण मंत्रालय को अगली सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले इस जानकारी को एकत्र कर कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 11 नवंबर, 2024 को होनी है। 19 अप्रैल, 2024 को एनजीटी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक तालिका साझा की थी। इसमें उन सभी मुद्दों का जिक्र किया गया था, जिनकी जानकारी प्रस्तुत की जानी थी। इसके साथ ही अदालत ने निर्देश दिया था कि जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने जवाब दाखिल नहीं किया है वे इस तालिका में आवश्यक जानकारी पर्यावरण मंत्रालय के सामने प्रस्तुत करेंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अदालत को जानकारी दी है कि 17 राज्यों से जवाब मिल चुके हैं और अन्य राज्यों से रिपोर्ट का इंतजार है। इसके बाद पूरी जानकारी को एक चार्ट के रूप में संकलित करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 31 जुलाई को सभी राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों से दो महीने के भीतर अपने राज्यों में अवर्गीकृत वनों की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। यह मामला 28 अप्रैल को एक रिपोर्ट के आधार पर ट्रिब्यूनल द्वारा स्वतः संज्ञान में लिया था। यह राज्य विशेषज्ञ समितियों (एसईसी) द्वारा रिपोर्ट दाखिल करने में हुई देरी के कारण भारतीय वनों के गायब होने से संबंधित थी। रिपोर्ट के मुताबिक इन समितियों को देश में अवर्गीकृत जंगलों की स्थिति को लेकर अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी थी। लेकिन इस देरी की वजह से 27 वर्षों की देरी के चलते

## वन क्षेत्रों पर बढ़ रहा अतिक्रमण



## कट रहे जंगल, बढ़ रहा जंगलीपन

देश के सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले मप्र में जंगल खतरे में हैं। वनाधिकार अधिनियम के तहत मिलने वाले भू-अधिकार पत्र (पट्टे) के लिए अतिक्रमणकारी लगातार पेड़ों की कटाई कर वन भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। विरोध करने पर वनकर्मियों पर हमले, हवाई फायर, पथराव जैसी घटनाएं भी बढ़ी हैं। वर्ष 2019 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रदेश में दो साल में 68.49 प्रतिशत वर्ग किमी में जंगल बढ़ने की घोषणा की थी लेकिन इस साल तस्वीर बिल्कुल अलग है। प्रदेश में इस साल वन अधिकार पत्रों के लिए कुल 1 लाख 65 हजार 139 दावे किए गए हैं। इनमें से 20 हजार 41 दावों को जायज माना गया है। यानी 88 प्रतिशत दावे खारिज कर दिए गए। सबसे कम करीब 4 प्रतिशत दावे चंबल संभाग में सही पाए गए हैं। बड़े पैमाने पर दावों के अमान्य होने कारण जंगल की कटाई करके अवैध अतिक्रमण करना, एक से ज्यादा जिलों में जाकर दावा करना, गलत दस्तावेज देने जैसे कारण सामने आए हैं। मप्र में 94 हजार 689 वर्ग किमी में जंगल है। वन अधिकार पत्र हासिल करने के लिए ग्राम समिति अनुमोदन करती है, फिर तहसील स्तर की समिति और अंत में जिला स्तरीय समिति। ग्राम समितियों ने भी बिना दस्तावेज जांचे और भौतिक सत्यापन किए दावे मान्य किए हैं। उनकी भूमिका भी संदिग्ध है।

जंगलों का एक हिस्सा गायब हो चुका है। वहीं इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 लागू होने से अवर्गीकृत वनों पर असर पड़ेगा। गौरतलब है कि 2016 में टीएन गोदावर्मन थिरुमुलपद के ऐतिहासिक मामले के बाद इन वनों को कानूनी संरक्षण प्राप्त है। लेकिन इस नए अधिनियम के बाद वो वन क्षेत्र कानूनी संरक्षण को खो देंगे। ऐसे में इन जंगलों का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जिससे इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वहीं इस बात का भी जिक्र किया गया है कि एसईसी रिपोर्ट को आदेश को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना था। इसमें शब्दकोश के आधार पर वन को परिभाषित करना था। इसका मतलब है कि सभी प्रकार के वन, चाहे वे किसी भी स्वामित्व या अधिसूचना स्थिति के हों, उन्हें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत शामिल किया जाना था।

परिणामस्वरूप, अवर्गीकृत या माने गए वनों (डीमंड) का भी अन्य उद्देश्यों के लिए भूमि उपयोग करने से पहले केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी। मतलब की यदि किसी परियोजना के लिए इस भूमि का उपयोग जंगल को छोड़ अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है तो उसके लिए कई स्तरों की समीक्षा के बाद केंद्र से मंजूरी लेना आवश्यक होगा। जानकारी के मुताबिक, 23 राज्यों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी

हैं, हालांकि उनमें से महज 17 ने ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया है। जानकारी में यह भी कहा गया है कि लगता है कि यह रिपोर्ट जल्दबाजी में तैयार की गई हैं। इनमें अधूरी जानकारी का उपयोग किया गया है। साथ ही इनको तैयार करने के लिए आसानी से उपलब्ध रिकॉर्ड में से अधूरी और असत्यापित आंकड़ों का उपयोग हुआ है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने हरियाणा सरकार की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट (इंटेक) को चार सप्ताह का समय दिया है। मामला हरियाणा द्वारा नजफगढ़ झील के 75 एकड़ क्षेत्र को आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित करने से जुड़ा है। इंटेक का तर्क है कि हरियाणा में नजफगढ़ झील के पूरे डूब क्षेत्र को आर्द्रभूमि के रूप में घोषित किया जाना चाहिए, इसे केवल 75 एकड़ क्षेत्र तक सीमित नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि 22 दिसंबर, 2023 को एनजीटी द्वारा दिए आदेश के मुताबिक दिल्ली ने पहले ही नजफगढ़ झील को आर्द्रभूमि घोषित करने का निर्णय ले लिया है। वहीं अदालत द्वारा 16 फरवरी, 2024 और 25 अप्रैल, 2024 को दिए निर्देशों के बाद हरियाणा सरकार ने एक स्थिति रिपोर्ट दायर की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा ने 75 एकड़ क्षेत्र को आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित करने का निर्णय लिया है।

● धर्मद सिंह कथूरिया

उद्योग शून्य और पिछड़े जनपदों में गिने जाने वाले उप्र के बांदा में, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे बनने के बाद विकास की रफ्तार भी तेज हो गई है। अब यहां बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के बगल में ही बांदा विकास प्राधिकरण ने महानगरों की तर्ज पर मॉडल सिटी बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए 35 हेक्टेयर भूमि चिन्हित करके किसानों से खरीदी जा रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे बन जाने के



## एक्सप्रेस-वे के पास मॉडल सिटी

बाद अब दिल्ली तक का सफर बहुत आसान हो गया है। मात्र 7 घंटे में ही दिल्ली का सफर पूरा किया जा सकता है। बांदा से दिल्ली की दूरी कम हो जाने से अब यहां उद्योग लगने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। यहां पर पहले ही और औद्योगिक गलियारा का स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। ताकि उद्योगपतियों को यहां उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित किया जा सके। पहले चरण में शहर के निकट ग्राम पंचायत जमालपुर और महोखर में 576 हेक्टेयर जमीन औद्योगिक गलियारा के लिए चिन्हित की गई है। प्रशासन की ओर से जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

जहां एक और औद्योगिक गलियारा बनाने की तैयारी चल रही है। वही बांदा विकास प्राधिकरण ने भी शहर की विस्तारीकरण की योजना पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। दो दिन पहले ही विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में चित्रकूट धाम मंडल के आयुक्त व प्राधिकरण के अध्यक्ष बालकृष्ण त्रिपाठी की अध्यक्षता में शहर विस्तारीकरण की योजना को हरी झंडी दे दी गई। बीडीए की टीम ने सर्वे कर मवाई बुजुर्ग व बड़ोखर खुर्द में 35 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की है। यह भूमि एक्सप्रेस-वे के एप्रोच रोड किनारे बांदा बहराइच स्टेट हाईवे से रायबरेली टांडा राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच है। एक्सप्रेस-वे के एप्रोच रोड के किनारे स्कूल, अस्पताल, पार्क, ग्रीन बेल्ट, छोटे उद्यम, आवासीय कॉलोनियां विकसित करने की तैयारी है। ताकि इस क्षेत्र में मॉडल सिटी विकसित हो सके। यहां आवासीय योजना के तहत भूखंड आवंटित होंगे, साथ ही छोटे बड़े उद्योग भी स्थापित होंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर छोटे-बड़े विद्यालय, शॉपिंग मॉल आदि के लिए भी भूखंड तैयार किए जाएंगे। बीडीए इस भूमि में चौड़ी सड़कों का जाल बिछाएगा। जो एक्सप्रेस-वे को जोड़ती होगी। साथ ही पार्क, बिजली पानी, स्ट्रीट लाइट, खेलकूद के मैदान व ग्रीन बेल्ट भी बनेंगे। इस संबंध में बांदा विकास प्राधिकरण के सचिव संदीप केला का कहना है कि एक्सप्रेस-वे के किनारे टाउनशिप के लिए फार्म डिमांड आवेदन पत्र बांदा विकास प्राधिकरण से प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना की विस्तार से जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट की मदद ले सकते हैं। ईमेल पर

भी सीधे आवेदक भूखंड के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं।

झांसी के पास आकार लेने वाले बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) शहर के मास्टर प्लान का जिम्मा अंतरराष्ट्रीय कंपनी सुर्बाना जुराग को सौंपा गया है। वहीं अमेरिकी कंपनी सीबीआरई कंसल्टेंट के तौर पर बीडा को विकसित करने में सहयोग करेगी। सुर्बाना जुराग कंपनी ने सिंगापुर का मास्टर प्लान तैयार किया है, जबकि अमेरिकी कंपनी

सीबीआरई ने हाईटेक स्पेस सिटी, मलेशिया और महाराष्ट्र स्थित शेन्झा-बिडकिन इंडस्ट्रियल पार्क पर काम किया है। बीडा शहर न केवल बुंदेलखंड का कायाकल्प करेगा बल्कि कानपुर तक औद्योगिक विकास में अहम भूमिका निभाएगा। 47 साल बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस पहल पर बुंदेलखंड सहित पूरे प्रदेश को नोएडा से बड़ी औद्योगिक टाउनशिप मिलेगी। नोएडा की तर्ज पर झांसी के 33 गांवों की 35300 एकड़ जमीन को अर्जित कर आधुनिक और निवेश सिटी के रूप में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा बीडा शहर का निर्माण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत शहर का मास्टर प्लान बनाने के लिए सिंगापुर की जुर्बाना जुराग ने न केवल सिंगापुर का मास्टर प्लान तैयार किया है, बल्कि चीन के सुझा इंडस्ट्रियल एरिया किंगाली, जी-4 सिटी शहरों को भी आकार दिया है। काम पूरा होने के बाद बीडा नोएडा से भी बड़ा शहर होगा।

● सिद्धार्थ पांडे

**अपील**

- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
- सभी किसान भाई मुख्यमंत्री हवामाल तुलवटी योजना का लाभ प्राप्त करें।

**78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...**

सचिव • भार साधक अधिकारी

**कृषि उपज मंडी समिति, जिला-खंडवा**

**अपील**

- किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
- नीलामी के समय किसान भाई अपने ढेर पर उपस्थित रहें।

**78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...**

सचिव • भार साधक अधिकारी

**कृषि उपज मंडी समिति, जिला-बुरहानपुर**

**अपील**

- किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
- नीलामी के समय किसान भाई अपने ढेर पर उपस्थित रहें।

**78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...**

सचिव • भार साधक अधिकारी

**कृषि उपज मंडी समिति, हरसूद, जिला-खंडवा**



# आजादी के सही मायने की अब भी तलाश!

विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत की आजादी की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई। हर तरफ उल्लास, जोश, जुनून और खुशी का माहौल था, लेकिन एक दिन के उल्लास पर बेरोजगारी, महंगाई और अपराधों की बीमारी सालभर भारी पड़ती है। विडंबना यह है कि आज भारत विकास की नई-नई ऊंचाईयां छू रहा है। शहर उन्नत और हाईटेक बन रहे हैं। लेकिन आज भी देश जाति, धर्म, भाषा और भेदभाव की वेड़ियों को तोड़ नहीं पाया है।

## ● राजेंद्र आगाल

15 अगस्त 2024 को भारत ने अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। हर तरफ एकदिनी हर्षोल्लास नजर आया। हर कोई आजादी का दम भर रहा था। लेकिन देश में जिस तरह के हालात हैं, उसको देखकर आज भी लोगों के मन में यही सवाल उठ

रहे हैं कि क्या वाकई हम पूरी तरह आजाद हैं। विकास के बड़े-बड़े दावों के बाद भी आपदा और विपदा का सामना करने के संसाधनों की कमी बनी हुई है। हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दम भर रहे हैं, लेकिन आलम यह है कि बहुसंख्यक आबादी गरीबी की चपेट में है। क्या ये वाकई आजादी ही है जहां हम

अपने अधिकारों की मांग करते हुए ट्रेन, बस, इमारतों को जलाते हुए अपने देश के बारे में न सोचकर केवल और केवल इतना भर सोचते हैं कि मुझे बस, मेरे हक की लड़ाई में जीत मिलनी चाहिए, बल्कि हक से ज्यादा ही मिलनी चाहिए और वो भी सबसे पहले। अगर सही मायने में देखा जाए तो अभी भी हमें आजादी की तलाश है।



## आबादी का बढ़ता भार

जब हम आजाद हुए थे तब देश की आबादी 34 करोड़ के आसपास थी। 1951 में देश की पहली जनगणना हुई। उस वक्त हमारी आबादी 36 करोड़ से थोड़ी ही ज्यादा थी। आखिरी बार 2011 में जनगणना हुई थी, तब आबादी बढ़कर 121 करोड़ के पार पहुंच गई। वहीं वर्तमान में हम 140 करोड़ पार हो गए हैं। भारत आज प्रगति की राह पर तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन आबादी का भार भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में विकास की तमाम कोशिशों के बावजूद कई मोर्चों पर हम फंसे हुए हैं। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर इस बार की थीम विकसित भारत थी, मगर मौजूदा भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है प्रति व्यक्ति आय। यह वो सूचकांक है, जिसे देखकर किसी भी देश के नागरिकों की समृद्धि का अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। भारत आर्थिक तरक्की की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। इसके बावजूद हम प्रति व्यक्ति आय के मामले में अमेरिका के सामने कहीं नहीं टिकते। यह बात विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2024: मध्यम आय जाल से भी साबित होती है। विश्व बैंक ने रिपोर्ट में चिंता जताई है कि भारत समेत दुनिया के 100 से ज्यादा देश हाई इनकम वाले देश बनने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये सब आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। भारत का हाल तो यह है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका की एक-चौथाई आय तक पहुंचने में 75 साल लग सकते हैं। अंग्रेजों से आजाद हुए भारत को 77 साल हो चुके हैं। आगामी 75 साल बाद भी हम प्रति व्यक्ति आय में अमेरिका की बराबरी नहीं कर पाएंगे। मतलब यह कि आजाद भारत 150 साल का हो जाएगा तब भी हमारी जेब में अमेरिका के नागरिकों के जितने पैसे में नहीं डाल पाएगा। विश्व बैंक की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की एक-चौथाई प्रति व्यक्ति आय तक पहुंचने में भारत को लगभग 75 वर्ष लगने का अनुमान है। वहीं, चीन इस उपलब्धि को 10 साल में ही हासिल कर सकता है जबकि इंडोनेशिया को लगभग 70 वर्ष लग सकते हैं।

## आत्म-चिंतन का समय

जब हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो यह समय केवल उत्सव का नहीं है, बल्कि आत्म-चिंतन का भी है। स्वतंत्रता का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि इसका व्यापक अर्थ मानसिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता से है। जब हम अपने देश के तिरंगे को लहराते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं और परेड देखते हैं, तो हमें खुद से पूछना चाहिए- क्या हम वास्तव



## चुनौतियां अब भी शेष

1947 में, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब इसकी जीडीपी या कुल आय 2.7 लाख करोड़ रुपए और जनसंख्या 34 करोड़ थी, वहीं आज देश की जीडीपी लगभग 235 लाख करोड़ रुपए और जनसंख्या 1.4 अरब से अधिक है। भारत की साक्षरता दर 1947 में लगभग 12 प्रतिशत से बढ़कर आज 75 प्रतिशत हो गई है। आजादी के समय खाद्यान्न की कमी का सामना करने वाला भारत अब आत्मनिर्भर भारत बन दुनियाभर के देशों में खाद्यान्न निर्यात कर रहा है। हरित क्रांति के परिणामस्वरूप रिकॉर्ड अनाज उत्पादन हुआ। भारत अब दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता राष्ट्र बन चुका है। चीनी का यह दूसरा और कपास का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक। 1970 में, श्वेत क्रांति (ऑपरेशन फ्लड) ने देश को दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश में बदल दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि देश ने इन 77 वर्षों में एक लंबा रास्ता तय किया है और जो एक मील का पत्थर है पर हम अभी भी एक विकासशील देश हैं, देश को अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, और ये भी सही है कि आने वाले समय में देश के सामने कई चुनौतियां भी होंगी। रेलवे वर्तमान में सबसे बड़ा नियोजक है फिर भी ट्रेन में आरक्षित सीट पाने के लिए लंबी प्रतीक्षा सूची है। देश के सामने रोजगार सृजन का मुद्दा भी एक महत्वपूर्ण चुनौती बना रहेगा। भारत ने स्वतंत्रता के बाद एक अरब अधिक उपभोक्ता जोड़े पर क्रय शक्ति कुछ लोगों तक सीमित है। आर्थिक असमानता भी देश के सामने बड़ा मुद्दा है। आज हम कृषि के मामले में आत्मनिर्भर हैं, लेकिन किसान इस पेशे से बाहर जा रहे हैं, राष्ट्रीय कर्ज बढ़कर 620 बिलियन हो गया है। विदेशी सत्ता की बेड़ियां टूटीं, देश में बहुत कुछ बदला पर विदेशी ताकतें हमारे संस्कार को नहीं बदल सकीं। आज भी हम वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से आगे बढ़ रहे हैं।

में स्वतंत्र हैं? स्वतंत्रता को अक्सर एक राजनीतिक अवधारणा के रूप में समझा जाता है, एक राष्ट्र की अपनी शासन प्रणाली को बाहरी नियंत्रण के बिना संचालित करने की क्षमता। लेकिन सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ इससे कहीं अधिक है। यह मन और आत्मा की मुक्ति है, जो हमें सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक बंधनों से मुक्त करती है। राष्ट्रों के बीच के संघर्ष को लेकर हमें हमेशा सिखाया गया है कि यह जरूरी है। इतिहास गवाह है कि पिछले 4,500 वर्षों में 10,000 से अधिक युद्ध हुए हैं। ये युद्ध केवल राष्ट्रों के बीच की लड़ाई नहीं थे, बल्कि मानवता को पीछे धकेलने वाले संघर्ष थे। हर राष्ट्र के अस्तित्व की नींव ही दूसरे राष्ट्र से संघर्ष में निहित मानी जाती है। लेकिन हमें यह विचार करना चाहिए कि क्या वास्तव में राष्ट्रों का अस्तित्व संघर्ष पर निर्भर है?

पाकिस्तान का उदाहरण लें, जिसकी पहचान अक्सर भारत के साथ उसकी दुश्मनी से जुड़ी होती है। यह धारणा अब भी जीवित है कि पाकिस्तान के अस्तित्व का आधार ही भारत के प्रति उसकी शत्रुता है। लेकिन यह केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। हर राष्ट्र अपने अस्तित्व के लिए किसी दुश्मन की आवश्यकता महसूस करता है। यह एक कड़वी सच्चाई है कि हमारे राजनीतिक अस्तित्व की नींव उतनी मजबूत और नैतिक नहीं हो सकती, जितना हम सोचते हैं। सच्ची प्रगति का मार्ग विभाजन के बजाय एकता की तलाश में है। स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए एक मौका है कि हम अपने भीतर झांकें और अपनी स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को समझें। सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ है कि हम अपने मन और विचारों को सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय सीमाओं से मुक्त कर सकें। ध्यान का अर्थ है इस क्षण में जीना, और सच्ची स्वतंत्रता की ओर पहला कदम यही है कि हम अपने भीतर जागरूकता लाएं। बाहरी दुनिया में बदलाव करने के बजाय खुद को बदलने का



## भारत में प्रति व्यक्ति आय अमेरिका से कई गुना कम

फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय 13.14 हजार डॉलर यानी करीब 2.28 लाख रुपए है। वहीं, अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय 85.37 हजार डॉलर यानी करीब 71.30 लाख रुपए है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों की सूची में अमेरिका 28.78 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ टॉप पर है। भारत 3.94 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। हालांकि, टॉप-10 जीडीपी वाले देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय भारत की है। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय उसकी राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से विभाजित करके निर्धारित की जाती है। मतलब भारत में रहने वाले लोगों की औसत आय ज्ञात करने के लिए भारत की जीडीपी को कुल आबादी से भाग कर देते हैं। प्रति व्यक्ति आय देश के नागरिकों की समृद्धि को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण सूचक है। प्रति व्यक्ति आय का इस्तेमाल लोगों के जीवन स्तर और क्वालिटी ऑफ लाइफ का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है।

प्रयास करें। यह स्वतंत्रता दिवस हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक स्थिति नहीं है, यह हमारे मन की स्थिति है।

## बेईमानी-भ्रष्टाचार व्यवस्था का हिस्सा

आजादी के 77 साल में ईमानदारी और कर्मठता के लिए मिलने वाले ईनाम पाने के लिए लगाई जाने वाली बेईमानी और भ्रष्टाचार की दौड़ भी पूरी तरह से हमारी व्यवस्था का हिस्सा बन गई है। रिश्तों में घुली मतलब की बयार आपसी संबंधों को आज कमजोर बना रही है। ऐसा भी नहीं है कि हमने इतने सालों में कुछ भी अच्छा नहीं किया। हम कई क्षेत्रों में विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं, हम अंतरिक्ष की यात्रा कर आए हैं। और ये सब हम देशवासियों की दिन-रात की मेहनत, देश के प्रति कुछ कर गुजरने के जज्बे और कुशल नेतृत्व का ही कमाल है। परंतु हम इस बात को भी नजरअंदाज तो नहीं कर सकते कि पल-पल गरीब-अमीर के बीच खाई और चौड़ी होती जा रही है। हम लाख कोशिशों के बाद भी इस सत्य से मुंह नहीं मोड़ सकते कि जात-बिरादरी-धर्म-मतलबों, मजहबों में बटे हुए समाज में रहना दिन-दिन दूधर होता जा रहा है। हम इसे भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं कि भाषा, जाति, नस्ल और ऐसे ही अन्य मुद्दों पर धर्मनिरपेक्षता के नाम पर लड़ते रहें। किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यकता होती

है कंधे से कंधा मिलाकर चलने की। संकीर्ण जातीय, सांप्रदायिक, लैंगिक, भाषायी मतभेदों और निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर आपस में मिलकर रहने की वैचारिक-राजनीतिक इच्छाशक्ति की। आपसी सद्भाव और प्यार की, देश के प्रति सच्चे लगाव की। सिर्फ कोरी जुबान से नहीं, अपितु मन की गहराइयों से इसकी माटी और भूमि को मां मानने और उसी मां के प्रति होने वाले लगाव, प्यार और चिंता के भाव की। देश को भी प्रगति और समृद्धि के पथ पर ले जाने के सपनों और संकल्पों की और उन सपनों और संकल्पों को पूरा करने के लिए हर तरह से समर्पित होने की। 77 साल बाद आज भी आजादी के मायने ढूँढने के प्रयास को कदापि निराशावादी होने का प्रमाण न मानकर आशावाद ही माना जाए कि आज के इस जाति, धर्म, भाषा और ऐसे ही अन्य मतभेदों में घिरे भारत में किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त लोग एक ऐसे भारत का सपना देख रहे हैं, जहां सभी आपसी सहज प्रेम और सद्भाव से रहें, जहां महिलाएं सुरक्षित हों, जहां किसी दफ्तर में काम कराने के लिए जाते हुए जेब में रखे हुए नोट या सिफारिशी पत्र को टटोलने की जरूरत न पड़े। जहां बच्चे कमाने की मजबूरी में किसी ढाबे या किसी निर्माण स्थल पर न जाकर पढ़ाई के लिए स्कूलों में जाएं। जहां ज्ञान और मेहनत पर सिफारिश या अन्य कोई भी साधन भारी न पड़े। जहां न्याय न

केवल सहज और सुलभ हो, बल्कि सबके लिए बराबर हो। देश के लोग एक ऐसी सुबह के इंतजार में हैं, जहां इन उम्मीदों को पूरा करने के लिए भारत के लिए सामूहिक संकल्प लिए जाएं और ईमानदारी, सत्यनिष्ठा से सामूहिक प्रयास किए जाएं।

## आर्थिक स्थिति

भारत को अपनी स्वतंत्रता के बाद कई मुद्दों का सामना करना पड़ा, जिसमें अशिक्षा, भ्रष्टाचार, गरीबी, लैंगिक भेदभाव, अस्पृश्यता, क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकता शामिल हैं। कई मुद्दों ने भारत के आर्थिक विकास में बड़ी बाधाओं के रूप में काम किया है। जब भारत ने 1947 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, तब इसका सकल घरेलू उत्पाद मात्र 2.7 लाख करोड़ था, जो विश्व सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत था। 1965 में, हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की। हरित क्रांति के दौरान, उच्च उपज वाले गेहूं और चावल के प्रकारों के साथ लगाए गए फसल क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। 1978-1979 से, हरित क्रांति ने 131 मिलियन टन का रिकॉर्ड अनाज उत्पादन किया। भारत तब दुनिया के शीर्ष कृषि उत्पादकों में से एक के रूप में पहचाना गया था। कारखानों और पनबिजली संयंत्रों जैसी जुड़ी हुई सुविधाओं के निर्माण के साथ, कृषि श्रमिकों के अलावा औद्योगिक श्रमिकों के लिए भी बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा हुईं।

आज भारत 147 लाख करोड़ जीडीपी के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो वैश्विक जीडीपी का 8 प्रतिशत है। हाल के वर्षों में, भारत में स्टार्टअप की संख्या में 15,400 प्रतिशत की भारी वृद्धि देखी गई है, जो 2016 में 471 से बढ़कर जून 2022 तक 72,993 हो गई है। स्टार्टअप में इस अभूतपूर्व वृद्धि ने देश में लाखों नए रोजगार भी पैदा किए हैं।

आज का भारत आजादी के समय के भारत से अलग है। आजादी के 77 सालों में भारतीय बुनियादी ढांचे में काफी सुधार हुआ है। भारतीय सड़क नेटवर्क की कुल लंबाई 1951 में 0.399 मिलियन किलोमीटर से बढ़कर 2015 तक 4.70 मिलियन किलोमीटर हो गई है, जो इसे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क बनाती है। आजादी के 77 सालों के बाद, भारत एशिया का तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक देश बन गया है। 1947 में भारत की जनसंख्या 340 मिलियन थी और साक्षरता दर सिर्फ 12 प्रतिशत थी, आज इसकी जनसंख्या लगभग 1.4 बिलियन है और साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत है। जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए, तो वे अपने पीछे एक टूटा-फूटा, जरूरतमंद, अविकसित और आर्थिक रूप से अस्थिर देश छोड़ गए। आजादी

के बाद भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना में वैज्ञानिक अनुसंधान को प्राथमिकता दी। इसने आईआईटी और आईआईसीएस जैसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थानों का मार्ग प्रशस्त किया। आजादी के सिर्फ तीन साल बाद, 1950 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना हुई। इन संस्थानों ने विदेशी संस्थानों की सहायता से भारत में अनुसंधान को बढ़ावा दिया। 1975 में अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च करने से लेकर मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला देश बनने तक, भारत ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की बदौलत अंतरिक्ष अनुसंधान तकनीक के क्षेत्र में आत्मविश्वास से भरे कदम उठाए हैं। हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत अमेरिका और चीन जैसे देशों के बराबर खड़ा है।

### शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति

1947 में भारत की जनसंख्या 340 मिलियन थी और साक्षरता दर सिर्फ 12 प्रतिशत थी, आज इसकी जनसंख्या लगभग 1.4 बिलियन है और साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत है। यद्यपि भारत ने साक्षरता दर के मामले में उल्लेखनीय प्रगति की है, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता अभी भी एक बड़ी चिंता का विषय है। शीर्ष 100 यूएस वल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एक भी भारतीय विश्वविद्यालय या संस्थान नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ी युवा आबादी वाला भारत चमत्कार कर सकता है, अगर इसके युवाओं को उचित कौशल और शिक्षा मिले। स्वास्थ्य क्षेत्र भी चिंताजनक है। डॉक्टर-रोगी अनुपात प्रति 1000 लोगों पर केवल 0.7 डॉक्टर है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन का औसत 2.5 डॉक्टर प्रति 1000 लोग है। एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि भारत में 65 प्रतिशत चिकित्सा व्यय मरीजों को अपनी जेब से चुकाना पड़ता है और इसका कारण यह है कि सार्वजनिक अस्पतालों में खराब सुविधाओं के कारण उनके पास निजी स्वास्थ्य सेवाओं का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है।



### अपराध अब आम बात

देश में आजादी के बाद से जैसे-जैसे विकास का क्रम बढ़ता गया, वैसे-वैसे अपराध के ग्राफ भी बढ़ते गए। नतीजा यह हो गया है कि आज देश में अपराध आम बात हो गई है। केंद्र सरकार की एजेंसी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 1953 से अपराधों का लेखा-जोखा रख रही है। 1953 में एनसीआरबी की पहली रिपोर्ट आई थी। उसके मुताबिक, 1952 में देश में 6.25 लाख अपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। उस वक्त 10 हजार से ज्यादा मामले तो मर्डर के ही थे। एनसआरबी की आखिरी रिपोर्ट 2021 के आंकड़ों पर आई है। इसकी मानें तो 2021 में देशभर में 60 लाख से ज्यादा केस दर्ज किए गए थे, जिनमें 29 हजार से ज्यादा मर्डर के केस थे। बलात्कार के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। 1971 से एनसीआरबी बलात्कार के मामलों का डेटा रख रहा है। 1971 में देश में 2,487 केस बलात्कार के दर्ज किए गए थे, जबकि 2021 में साढ़े 31 हजार से ज्यादा केस दर्ज किए गए। उधर, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का डेटा 1951 से रख रहा है। उस वक्त देश में सिर्फ 3 लाख के आसपास गाड़ियां रजिस्टर्ड थीं। लेकिन अभी देश में रजिस्टर्ड गाड़ियों की संख्या करीब 35 करोड़ हो चुकी है। इसी तरह 1951 के वक्त देश में 3.99 लाख किमी की सड़क ही थी, लेकिन अब देश में सड़कों का जाल 63.31 लाख किमी से भी ज्यादा हो गया है।

### राजनीतिक स्थिति

ब्रिटिश शासन के अंत के बाद 1947 में जवाहरलाल नेहरू को भारत का पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने भारत के लिए एक समाजवादी-आर्थिक प्रणाली को बढ़ावा दिया, जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं और खनन, इस्पात, विमानन और अन्य भारी उद्योगों जैसे अर्थव्यवस्था के बड़े क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण शामिल था। गांव के आम इलाकों को ले लिया गया, और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक कार्यों और औद्योगिकरण अभियान ने महत्वपूर्ण बांधों, सड़कों, सिंचाई नहरों, थर्मल और पनबिजली संयंत्रों और कई अन्य चीजों के निर्माण को जन्म दिया। 1970 के दशक की शुरुआत में भारत की आबादी 500 मिलियन को पार कर गई, लेकिन हरित क्रांति ने कृषि उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि की, जिसने देश की लंबे समय से चली आ रही खाद्य समस्या को समाप्त करने में मदद की।

1991 से 1996 तक भारत की अर्थव्यवस्था दिवंगत प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और तत्कालीन वित्तमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा लागू की गई नीतियों के परिणामस्वरूप तेजी से बढ़ी। गरीबी लगभग 22 प्रतिशत तक कम हो गई थी, जबकि बेरोजगारी लगातार कम हो रही है। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 7 प्रतिशत से अधिक हो गई। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक लगातार तीन कार्यकालों तक पद पर रहीं, उसके बाद उन्होंने अपना चौथा कार्यकाल (1980-84) पूरा किया। भारत ने 2007 में प्रतिभा पाटिल को अपनी पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना।

इक्कीसवीं सदी में भारत की अर्थव्यवस्था काफी तेजी से बढ़ी है। नरेंद्र मोदी (भाजपा) के



प्रधानमंत्री कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जैसे धारा 370 को हटाना, रक्षा प्रणालियों को मजबूत करना, स्टार्टअप के लिए अनुकूल माहौल बनाना और भी बहुत कुछ। बुनियादी ढांचे और विनिर्माण को बढ़ाने के लिए मोदी प्रशासन ने कई कार्यक्रम और अभियान शुरू किए, जिनमें मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत परियोजना शामिल हैं।

### कानून व्यवस्था

स्वतंत्रता से पहले, प्रिवी काउंसिल भारत में सर्वोच्च अपीलीय प्राधिकरण था। स्वतंत्रता के बाद पहली कार्रवाई के रूप में इस परिषद को समाप्त कर दिया गया था। प्रिवी काउंसिल अधिकार क्षेत्र उन्मूलन अधिनियम को भारतीय संविधान सभा द्वारा 1949 में पारित किया गया था ताकि भारत से अपील पर प्रिवी काउंसिल के अधिकार को समाप्त किया जा सके और लंबित अपीलों के लिए प्रावधान किए जा सकें। नए संप्रभु देश के लिए संविधान का मसौदा तैयार करना बीआर अंबेडकर की तीक्ष्ण कानूनी बुद्धि का ही कमाल था। राष्ट्र में सभी कार्यकारी, विधायी और न्यायिक मामलों में, भारत का संविधान सर्वोच्च कानून के रूप में कार्य करता है। भारतीय कानूनी प्रणाली दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के एक प्रमुख घटक और सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोर्चे के रूप में विकसित हुई है। 1950 में पहली बार अपनाए जाने के बाद से अब तक भारतीय संविधान में एक सैकड़ से अधिक संशोधन हुए हैं। भारतीय संविधान 395 अनुच्छेदों के साथ 22 भागों में विभाजित है। बाद में, विभिन्न परिवर्तनों के माध्यम से, आगे के अनुच्छेद जोड़े गए और संशोधन किए गए। अब तक भारत के विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग द्वारा बनाए गए ऑनलाइन संग्रह के अनुसार, लगभग 839



केंद्रीय कानून हैं। भारतीय विधिक प्रणाली का भविष्य आशाजनक और दूरदर्शी है, और इक्कीसवीं सदी में, युवा, पहली पीढ़ी के वकील सर्वश्रेष्ठ विधि विद्यालयों से स्नातक होने के बाद इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं।

### रक्षा क्षेत्र की स्थिति

वार्षिक जीएफपी समीक्षा के लिए विचार किए गए देशों में से 142 में से भारतीय सेना चौथे स्थान पर है। 1962 में चीनी सेना से पराजित होने से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रणालियों में से एक बनने तक, भारत ने निश्चित रूप से अपनी पिछली गलतियों से सीखा है। भारतीय रक्षा प्रणाली अपनी वर्तमान प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सक्षम होने के कारणों में से एक रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) है, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। अपनी स्थापना के बाद से, इसने कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम और महत्वपूर्ण तकनीकें बनाई हैं, जिनमें मिसाइल सिस्टम, छोटे और बड़े हथियार, तोपखाने प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, टैंक

और बख्तरबंद वाहन शामिल हैं। भारत ने 1950 के दशक के अंत में परमाणु ऊर्जा पर काम करना शुरू किया और 1970 के दशक तक स्वदेशी परमाणु ऊर्जा स्टेशन बन गए। भारत ने परमाणु हथियार विकसित करना और विखंडनीय सामग्री का उत्पादन भी शुरू कर दिया था, जिसके कारण 1971 में पोग्रण में कथित रूप से हानिरहित परमाणु विस्फोट संभव हो सका। एपीजे अब्दुल कलाम के निर्देशन में और आयुध कारखानों के सहयोग से एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (आईजीएमडीपी) की स्थापना 1983 में की गई थी। 1989 में, लंबी दूरी की अग्नि को स्वतंत्र रूप से डिजाइन और परीक्षण किया गया था। बाद में, भारत और रूस ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डिजाइन और उत्पादन करने के लिए सहयोग किया। भारत वर्तमान में रक्षा उत्पादन में कई अन्य देशों का नेतृत्व करता है। भारत लगभग एक दर्जन देशों में से एक है जिसने अपने लड़ाकू जेट, हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी, मिसाइल और विमान वाहक का निर्माण और उत्पादन किया है।

## आज महंगाई ने हर व्यक्ति की कमर तोड़ी

एक वक्त था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसका कारण ये था कि हमारे देश में हर घर में सोना हुआ करता था। आज भी दुनियाभर में सबसे ज्यादा सोना भारतीय घरों में ही है। आज 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 70 हजार पहुंच गई है। लेकिन जब हम आजाद हुए थे, तब 10 ग्राम सोने की कीमत 90 रुपए भी नहीं थी। यानी, अगर आज के हिसाब से तुलना करें तो आजादी के वक्त हम जितने में 10 ग्राम सोना खरीद सकते थे, आज उतने में एक लीटर पेट्रोल भी नहीं आता। सोने के बाद अब पेट्रोल की कीमतों की बात करें, तो आज देश में पेट्रोल की कीमतें 100 का आंकड़ा पार कर चुकी हैं। लेकिन आजादी के वक्त एक लीटर पेट्रोल की कीमत महज 27 पैसे थी। साल 2000 तक एक लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़कर 29 रुपए के आसपास पहुंच गई थी। भारत कृषि प्रधान देश है। आजादी के वक्त देश की ज्यादातर आबादी खेती पर ही निर्भर थी। ऐसा अनुमान है कि उस वक्त 80 प्रतिशत से ज्यादा आबादी की आजीविका खेती से ही चलती थी। इतना ही नहीं, उस समय देश की जीडीपी में कृषि का योगदान भी करीब आधा हुआ करता था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 1950-51 में देश की जीडीपी में कृषि का योगदान 52 प्रतिशत के आसपास था, जो 2022-23 तक घटकर 20 प्रतिशत से भी कम हो गया है। हालांकि, इस दौरान कृषि उत्पादन में जमकर बढ़ोतरी हुई है। खेती से जुड़े कामगारों की संख्या भी बढ़ी है। खेती की बात हो तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस (एमएसपी) की बात भी करनी ही होगी। हमारे देश में एमएसपी 1966-67 से लागू की गई। उस वक्त सिर्फ गेहूं को ही एमएसपी पर खरीदा जाता था। उस समय एक क्विंटल (100 किलो) गेहूं पर सरकार 54 रुपए एमएसपी देती थी। वहीं आज एक क्विंटल गेहूं पर 2,125 रुपए एमएसपी मिलती है। सरकारी आंकड़ों की मानें तो 31 मार्च 1948 तक देश में 1.40 लाख के आसपास प्राइमरी और 12,693 मिडिल और हाईस्कूल थे। लेकिन आज देश में करीब 15 लाख स्कूल हैं। इसी तरह उस वक्त महज 414 कॉलेज हुआ करते थे और आज इनकी संख्या 49 हजार से ऊपर चली गई है। उस वक्त बजट भी मात्र 74 करोड़ रुपए हुआ करता था और 2023-24 में केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय को एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए हैं।

**मो** पाल के कोलार इलाके में गत दिनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बाइक बीच सड़क पर बैठे मवेशी से टकरा गई। हादसे

में युवक के सिर में गंभीर चोट आई। मवेशी का सींग लगने से उनकी जांघ में गहरा कट लगा था। राहगीरों ने उन्हें पास के निजी अस्पताल पहुंचाया। जहां इलाज के दौरान रात करीब डेढ़ बजे उनकी मौत हो गई। ऐसे में मप्र की सड़कों पर रोजाना हो रहे हैं। प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों, राजमार्गों, जिला मार्गों पर लाखों गायों का कब्जा है। जबकि गायों के लिए इस बजट में तीन गुना राशि का प्रावधान किया गया है, फिर भी हालात जस के तस है। मप्र में गाय पर सियासत काफी लंबे वक्त से होती रही है। इस बार मप्र सरकार ने गोवंश के संरक्षण के लिए बचत को तीन गुना तक बढ़ा दिया है। बावजूद इसके पूरे प्रदेश तो छोड़िए राजधानी भोपाल में ही गोवंश की हालत ठीक नहीं है। गौशालाओं में चारा-पानी के बिना गायें बेमौत मर रही हैं। लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं है।

वर्तमान में प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 8853 किलोमीटर, राजमार्ग 11 हजार 389 किलोमीटर, जिला मार्ग 23 हजार 401 किलोमीटर सहित प्रदेश में कुल सड़कों की लंबाई 70 हजार 956 किलोमीटर है। साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क और मुख्यमंत्री सड़क योजना में लगभग 80 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण कराया गया है। इन सड़कों

## सड़कों पर बैठी मौत!

पर तकरीबन 6 लाख गायें अपना डेरा जमाए रहती हैं। सड़कों पर बैठी रोजाना इन गायों से वाहनों की टक्कर से 8-10 लोगों की मौत हो रही है। कई ऐसे भी जिनकी जान तो बच गई, लेकिन हादसे के बाद वे अपाहिज जिंदगी जीने को मजबूर हैं। जान सिर्फ इंसानों की ही नहीं मवेशियों की भी जा रही है। प्रदेश में गायों के संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार ने साल 2024-25 के बजट में 252 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

● बृजेश साहू

**अपील**

78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...

- सभी किसान भाई मुख्यमंत्री हनुमाल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।

सचिव • भार साधक अधिकारी

**कृषि उपज मंडी समिति, शिवपुरी**

**अपील**

78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...

- नीलानी के समय किसान भाई अपने ढेर पर उपस्थित रहें।
- किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।

सचिव • भार साधक अधिकारी

**कृषि उपज मंडी समिति, श्योपुर**

**अपील**

78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...

- सभी किसान भाई मुख्यमंत्री हनुमाल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।

सचिव • भार साधक अधिकारी

**कृषि उपज मंडी समिति, मुरैना**

**अपील**

78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...

- सभी किसान भाई मुख्यमंत्री हनुमाल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।

सचिव • भार साधक अधिकारी

**कृषि उपज मंडी समिति, गुना**

**अपील**

78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...

- नीलानी के समय किसान भाई अपने ढेर पर उपस्थित रहें।
- किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।

सचिव • भार साधक अधिकारी

**कृषि उपज मंडी समिति, अशोकनगर**

**अपील**

78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...

- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
- सभी किसान भाई मुख्यमंत्री हनुमाल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।

सचिव • भार साधक अधिकारी

**कृषि उपज मंडी समिति, डबरा, जिला-ग्वालियर**

6

कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों की चुनावी तैयारी शुरू हो गई है। अगले चार महीने में चार राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ज्यादा संभावना है कि इस बार तीन राज्यों के चुनाव एक साथ हों। पहले महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव अलग-अलग होते थे। लेकिन इस बार जानकारों का कहना है कि अक्टूबर में तीनों राज्यों का चुनाव एक साथ हो सकता है। उससे पहले सितंबर में जम्मू-कश्मीर विधानसभा का चुनाव होने की संभावना है। सो, कांग्रेस और उसके सहयोगी चुनावी गारंटि की तैयारी कर रहे हैं।



## कांग्रेस की स्पेशल-14 टीम

**लो** कसभा चुनाव के बाद अब कांग्रेस चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा चुनाव में मिली जीत के मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव को हर हाल में जीतने का टारगेट दे दिया है। इसके साथ ही लक्ष्य को हासिल करने के लिए कांग्रेस ने चार राज्यों में चुनाव के लिए स्पेशल-14 टीम का गठन कर दिया है। इनके ऊपर चार राज्यों में कांग्रेस के उम्मीदवारों का चयन करने का जिम्मा होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू-कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी गठित कर दी है। कांग्रेस की यह कमेटी पार्टी उम्मीदवारों के चयन और उनके टिकट का फैसला करेगी। कांग्रेस ने हरियाणा और महाराष्ट्र के गठित स्क्रीनिंग कमेटी में एक चेयरमैन और तीन-तीन मेंबर बनाए गए हैं जबकि झारखंड और जम्मू-कश्मीर के लिए एक चेयरमैन और दो-दो सदस्य नियुक्त किए हैं।

हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी अजय माकन को सौंपी है। उनके साथ मणिकम टैगोर, जिग्नेश मेवानी और श्रीनिवास बीवी को सदस्य बनाया है। महाराष्ट्र विधानसभा के लिए कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी की कमान मधुसूदन मिस्त्री को सौंपी है। उनके साथ सप्तगिरि शंकर

उल्का, मंसूर अली खान और श्रीवेल्ला प्रसाद को सदस्य बनाया गया है।

झारखंड विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के सेलेक्शन करने के लिए कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी गिरीश चोडनकर को सौंपी है। कांग्रेस ने पूनम पासवान और प्रकाश जोशी को कमेटी का सदस्य बनाया है। वहीं, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को सौंपी गई है। इस कमेटी में एंटों एंटोनियो और सचिन राव होंगे। इसके अलावा चारों राज्यों में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी में प्रदेश अध्यक्ष, सीएलपी नेता, कांग्रेस के राज्य प्रभारी को भी शामिल रहने की बात कही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने महाराष्ट्र और हरियाणा में पिछली बार के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया था। हरियाणा में कांग्रेस को 10 में से 5 लोकसभा सीटें मिलीं, तो महाराष्ट्र में कांग्रेस ने 13 लोकसभा सीटें जीती हैं, वहीं झारखंड में कांग्रेस की सीटें एक से बढ़कर दो हो गई हैं। लोकसभा चुनावों के संचालक महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस सबसे बड़ी दल बनकर उभरी है। लोकसभा चुनाव में इन तीनों ही राज्यों में भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा है। भाजपा को हरियाणा में 5, महाराष्ट्र में 14, झारखंड में 4 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त को अब विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रखना चाहती है। इसके चलते ही सोनिया गांधी ने संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के

## विधानसभा चुनावों में गारंटी पर रहेगा जोर

जानकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस ने गारंटी दी थी और राहुल गांधी व दूसरे विपक्षी नेताओं ने लोगों के खाते में खटाखट पैसे जाने की बात कही थी उसको इस बार राज्यों के चुनाव में विस्तार दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अपनी गारंटियों की सूची बना रही है। इसके बारे में शरद पवार, उद्व टाकरे और हेमंत सोरेन से भी बात की जाएगी। इस बात की संभावना कम है कि कोई साझा घोषणापत्र जारी होगा। सभी पार्टियां अपना-अपना घोषणापत्र जारी करेंगी, जिसमें राज्यों के हिसाब से कुछ गारंटियों की घोषणा होगी। लेकिन हर साल गरीब महिलाओं को एक लाख रुपए देने की योजना की घोषणा हर जगह होगी। इसका मतलब है कि लोकसभा के प्रचार की तरह इस बार राज्यों के चुनाव में भी हर महीने साढ़े आठ हजार रुपए खटाखट लोगों के खाते में जाने की बात होगी। इसी तरह 21 से 25 साल के डिग्री या डिप्लोमाधारी युवाओं को एप्रेंटिसशिप के नाम पर हर साल एक लाख रुपए देने की योजना की भी घोषणा होगी। इसके अलावा मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर के साथ-साथ मुफ्त में 200 यूनिट तक बिजली देने की गारंटी भी दी जाएगी। महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों खेती-किसानी वाले राज्य हैं। इसलिए दोनों राज्यों में किसानों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं होंगी।

लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को जुट जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ ही महीनों में चार राज्यों में चुनाव होने हैं। हमें लोकसभा चुनाव में बनी स्थिति को बरकरार रखना चाहिए। हमें आत्मसंतुष्ट और अति आत्मविश्वासी नहीं बनना चाहिए। माहौल हमारे पक्ष में है, लेकिन हमें लक्ष्य को ध्यान में रखने की भावना के साथ एकजुट होकर काम करना होगा। लोकसभा

चुनाव के बाद कांग्रेस अब 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में उलटफेर की तैयारी कर रही है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने इसके संकेत दिए। सोनिया ने नेताओं और कार्यकर्ताओं से इन राज्यों में जीत के लिए कमर कसने की अपील की। अपने संबोधन में सोनिया ने कहा कि देश की हवा हमारे पक्ष में है और अगर इन 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव में

हम जीत दर्ज कर लेते हैं तो इसका व्यापक राजनीतिक संदेश जाएगा। 10 साल से केंद्र की सत्ता से बाहर कांग्रेस के लिए 2024 का चुनाव संजीवनी साबित हुआ है। लोकसभा की 99 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस की नजर अब विधानसभा के चुनावों पर है, जिसके जरिए पार्टी सत्ता में खुद का विस्तार करना चाहती है।

● विपिन कंधारी



**78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...**

सचिव • भार साधक अधिकारी

**कृषि उपज मंडी समिति, सावेर, जिला-इंदौर**

**अपील**

- नीलामी के समय किसान माई अपने ढेर पर उपस्थित रहें।
- किसान माई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।



**78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...**

सचिव • भार साधक अधिकारी

**कृषि उपज मंडी समिति, जिला-धार**

**अपील**

- सभी किसान माई मुख्यमंत्री हनुमाल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।



**78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...**

सचिव • भार साधक अधिकारी

**कृषि उपज मंडी समिति, धामनोद, जिला-धार**

**अपील**

- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
- सभी किसान माई मुख्यमंत्री हनुमाल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।



**78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...**

सचिव • भार साधक अधिकारी

**कृषि उपज मंडी समिति, बदनावर, जिला-धार**

**अपील**

- किसान माई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
- नीलामी के समय किसान माई अपने ढेर पर उपस्थित रहें।



**78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...**

सचिव • भार साधक अधिकारी

**कृषि उपज मंडी समिति, कुशी, जिला-धार**

**अपील**

- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
- सभी किसान माई मुख्यमंत्री हनुमाल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।



**78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...**

सचिव • भार साधक अधिकारी

**कृषि उपज मंडी समिति, मनावर, जिला-धार**

**अपील**

- किसान माई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
- नीलामी के समय किसान माई अपने ढेर पर उपस्थित रहें।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब से लेकर उप्र और महाराष्ट्र जैसे राज्य में दलित आरक्षण का बंटवारा होने का फैसला राज्य सरकारें ले पाएंगी तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय को मिलने वाले आरक्षण को वर्गीकरण करके बांट सकती है। इसके साथ ही ओबीसी आरक्षण के बंटवारे का भी रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया है।

## कोटा के अंदर कोटा



सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने एससी और एसटी के लोगों के बीच समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को एससी-एसटी के आरक्षण को कोटा के भीतर कोटा बनाने की मंजूरी दे दी है। अब देश की राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सब कैटेगरी का आधार उचित होना चाहिए।

देश के अलग-अलग राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ ओबीसी वर्ग में सब कैटेगरी और उनके आरक्षण के मुद्दे पर लंबे समय से बहस होती आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मिथल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने एससी-एसटी आरक्षण को श्रेणी में बांटने का अधिकार राज्य सरकार को दे दिया है। अब संवैधानिक फैसला राज्य के हक में आया है। इसके बाद राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में दलित और आदिवासी समुदाय को मिलने वाले आरक्षण को बांटने का अधिकार मिल गया है। इसके साथ ही

चार जजों ने एससी-एसटी में भी क्रीमी लेयर को लेकर टिप्पणी की है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब से लेकर उप्र और महाराष्ट्र जैसे राज्य में दलित आरक्षण का बंटवारा होने का फैसला राज्य सरकारें ले पाएंगी तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय को मिलने वाले आरक्षण को वर्गीकरण करके बांट सकती है। इसके साथ ही ओबीसी आरक्षण के बंटवारे का भी रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया है। बिहार से लेकर राजस्थान, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में ओबीसी आरक्षण को कोटा के भीतर कोटा बनाने की मांग लंबे समय से उठती रही है। सर्वोच्च अदालत के फैसले का सियासी प्रभाव पड़ना लाजमी है। केंद्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति को 15 और अनुसूचित जनजाति को 7 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है। तमाम रिपोर्ट्स में कहा गया है कि आरक्षण का लाभ लगातार वही ले रहे हैं, जो ऊपर उठ चुके हैं और जो नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व हासिल कर चुके हैं। ऐसे में दलित और आदिवासी समुदाय की तमाम जातियों को अभी भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने निचले स्तर तक आरक्षण का लाभ पहुंचाने के मकसद से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के भीतर कोटा बनाने का फैसला राज्य सरकारों को दिया है।

दलित चिंतक और जेएनयू में राजनीतिक अध्ययन केंद्र के एसोसिएट प्रोफेसर हरीश

वानखेड़े कहते हैं कि देश के हर एक राज्य में दलित समुदाय के बीच एक डोमिनेटिंग कास्ट होती है। बिहार में पासवान तो उप्र में जाटव और महाराष्ट्र में महार दलित समुदाय के बीच ऐसी जातियां हैं, जिनके खिलाफ दलितों की दूसरी जातियों को गोलबंद कर राजनीतिक इस्तेमाल किया जाता है। नीतीश कुमार बिहार में 2007 में दलितों के बीच वर्गीकरण कर महादलित की राजनीति खड़ी कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश और पंजाब में भी दलितों को मिलने वाले आरक्षण को बांटने का फैसला हुआ था, लेकिन मामला अदालत में जाने से कानूनी पेंच में फंस गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से दलित आरक्षण को बांटने का इन तमाम राज्यों में रास्ता साफ हो गया है। उप्र में लंबे समय तक अनुसूचित जाति को मिलने वाले आरक्षण को दो वर्गों में बांटने की बात की जा रही थी। उप्र में अनुसूचित जाति के लिए 20 फीसदी आरक्षण मिलता है। उप्र में सियासी तौर पर जाटव और गैर-जाटव के बीच दलित बंटता हुआ है। कहा जाता है कि उप्र में अनुसूचित जाति को मिलने वाले आरक्षण का लाभ जाटव समुदाय को सबसे ज्यादा हुआ है और उसके बाद धोबी, पासी और अन्य जातियों को मिली है, लेकिन कोरी, कोल, वाल्मीकि जैसी अनुसूचित जातियों को आरक्षण वैसा नहीं मिला जैसे जाटव समुदाय को मिला है। जाटव समुदाय बसपा का कोर वोटबैंक माना जाता है।



ऐसे में भाजपा और सपा गैर-जाटव वोटों को साधने के लिए दलित आरक्षण के वर्गीकरण का दांव चल सकती है।

उप्र में दलित आरक्षण को दो हिस्सों में बांटने का फैसला होता है तो उसका सियासी प्रभाव भी पड़ेगा। उप्र में दलित जाटव और गैर-जाटव के बीच बंटता हुआ है, जिसमें 12 फीसदी जाटवों की संख्या है और 10 फीसदी गैर-जाटव दलित हैं।

उप्र में दलितों की कुल 66 उपजातियां हैं, जिनमें 55 ऐसी उपजातियां हैं, जिनका संख्या बल ज्यादा नहीं है। इसमें मुसहर, बसोर, सपेरा और रंगरेज जैसी जातियां शामिल हैं। दलित की कुल आबादी में 56 फीसदी जाटव के अलावा दलितों की अन्य जो उपजातियां हैं, उनकी संख्या 46 फीसदी के करीब है। पासी 16 फीसदी, धोबी, कोरी और वाल्मीकि 15 फीसदी और गोंड,

धानुक और खटीक करीब 5 फीसदी हैं। गौर-जाटव दलित में वाल्मीकि, खटीक, पासी, धोबी, कोरी सहित तमाम जातियों के विपक्षी राजनीतिक दल अपने-अपने पाले में लामबंद करने में जुटे हैं। इस तरह अनुसूचित जाति के आरक्षण को देखना है कि बांटने का दांव सरकार चलती है या नहीं।

● इन्द्र कुमार

**78वें स्वतंत्रता दिवस**  
की शुभकामनाओं सहित...

**अपील**

- सभी किसान भाई मुख्यमंत्री हनुमाल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।

सचिव • भार साधक अधिकारी

**कृषि उपज मंडी समिति, राजगढ़, जिला-धार**

**78वें स्वतंत्रता दिवस**  
की शुभकामनाओं सहित...

**अपील**

- नीलामी के समय किसान भाई अपने ढेर पर उपस्थित रहें।
- किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।

सचिव • भार साधक अधिकारी

**कृषि उपज मंडी समिति, पेटलावद, जिला-झाबुआ**

**78वें स्वतंत्रता दिवस**  
की शुभकामनाओं सहित...

**अपील**

- नीलामी के समय किसान भाई अपने ढेर पर उपस्थित रहें।
- किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।

सचिव • भार साधक अधिकारी

**कृषि उपज मंडी समिति, थांदला, जिला-झाबुआ**

**78वें स्वतंत्रता दिवस**  
की शुभकामनाओं सहित...

**अपील**

- सभी किसान भाई मुख्यमंत्री हनुमाल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।

सचिव • भार साधक अधिकारी

**कृषि उपज मंडी समिति, सेंधवा, जिला-बड़वानी**

**78वें स्वतंत्रता दिवस**  
की शुभकामनाओं सहित...

**अपील**

- किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
- नीलामी के समय किसान भाई अपने ढेर पर उपस्थित रहें।

सचिव • भार साधक अधिकारी

**कृषि उपज मंडी समिति, जिला-खरगौन**

**78वें स्वतंत्रता दिवस**  
की शुभकामनाओं सहित...

**अपील**

- सभी किसान भाई मुख्यमंत्री हनुमाल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।

सचिव • भार साधक अधिकारी

**कृषि उपज मंडी समिति, अंजड़, जिला-बड़वानी**

**अ** ब सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस में नए मुकाबले की तैयारी है। दोनों पार्टियों ने इस साल नवंबर-दिसंबर में तय नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए कसर

कसनी शुरू कर दी है। भाजपा सरकारी योजनाओं, त्योहारों और पारंपरिक खेलों के आयोजन के जरिए लोगों का मन छूने में जुट गई है। कांग्रेस मानसून सत्र में विधानसभा का घेराव और पार्टी में बड़ा फेरबदल कर चुनाव में अपनी खोई प्रतिष्ठा को पाने के लिए पसीना बहाने की तैयारी में है। हाल ही में राजधानी रायपुर में मूसलाधार बारिश के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मितानिन बहनों के साथ पंगत में बैठे दिखे। पंगत में मुख्यमंत्री ने बस्तर के दरभा से आई मितानिन दीदियों जयमनी नाग और कवर्धा की बैगा जनजाति की दसनी बाई के साथ भोजन किया। भोजन से पहले मुख्यमंत्री ने मितानिन बहनों को सौगात दी और हर माह उनकी प्रोत्साहन राशि को सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर करने की शुरुआत की। इसके साथ ही राज्यभर में 90 करोड़ 8 लाख 84 हजार 20 रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे मितानिन बहनों के बैंक खाते में डाली गई।

भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2023 में महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना शुरू करने की घोषणा की थी। इस चुनावी घोषणा ने जादू का काम किया और प्रदेश में भाजपा ने अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की। 90 विधानसभा सीटों वाली विधानसभा में भाजपा 54 सीटों पर विजयी हुई। कांग्रेस महज 34 सीटों पर सिमट गई और एक सीट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के खाते में गई। भाजपा सरकार बनने के बाद और लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ भी मिलना शुरू हो गया। जाहिर है, योजना के क्रियान्वयन का असर लोकसभा चुनाव के परिणाम में दिखाई दिया। भाजपा ने प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों में से 10 सीटों पर जबरदस्त जीत हासिल की। अब प्रदेश में होने जा रहे नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के पहले प्रदेश भाजपा हरेली त्योहार के माध्यम से लोगों को जोड़ने में जुट रही है। 15 जुलाई से सितंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में

## निकाय चुनावों का मुकाबला

मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद, विधायक और पार्टी के सभी पदाधिकारी सक्रिय रूप से भाग लेने जा रहे हैं। त्योहार में भाजपा के नेता गेड़ी चढ़ने के अलावा गांव, शहरी और सभी ग्रामीण अंचलों में पारंपरिक खेल और अन्य गतिविधियों का आयोजन करेंगे।

हरेली त्योहार के अलावा तीज, गुरु पूर्णिमा जैसे त्योहारों का आयोजन पंचायत, ब्लॉक, ग्रामीण और शहरी अंचलों में किया जाएगा। प्रदेश में इसके पहले हरेली त्योहार का आयोजन कांग्रेस के शासनकाल में मुख्यमंत्री निवास में किया जाता था। तब भूपेश बघेल गेड़ी चढ़ते थे। उस वक्त भाजपा के नेता इसे दिखावा बताते थे। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव से पहले राज्य सरकार सस्ते गैस सिलेंडर पर बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। चुनाव से पहले सरकार गरीब वर्ग की महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा भी पूरा करने जा रही है, इसके लिए नवा रायपुर के मंत्रालय में बैठकें भी हो चुकी हैं। भाजपा के लिए यह योजना चुनाव में गेमचेंजर साबित हो सकती है। विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी की गारंटी (घोषणापत्र) में भाजपा ने सस्ता गैस सिलेंडर देने का वादा किया था।

भाजपा की इस रणनीति पर कांग्रेस का कहना है कि भाजपा हमेशा ही मतदाताओं को लालच देने की कोशिश करती है। फिर भी, किसी भी कीमत पर पार्टी इस बार अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाएगी। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला कहते हैं कि भाजपा चुनावों को देखकर वादा पूरा करने की बात करती है और अब नगरीय निकाय चुनाव से पहले भाजपा फिर से वही करने जा रही है। वे कहते हैं कि भाजपा केवल मतदाताओं को लालच देने की कोशिश करती है मगर इस बार यह फॉर्मूला नहीं चलने वाला है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के माध्यम से कांग्रेस पार्टी अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा हासिल करने की फिराक में नजर आ रही है। पार्टी अपने संगठन में बड़ा बदलाव करने जा रही है।

● रायपुर से टीपी सिंह



**कार्यालय, कृषि उपज मण्डी समिति, इन्दौर, जिला इन्दौर**  
**लक्ष्मीबाई नगर, इन्दौर, दूरभाष क्रमांक 0731-2411223, 2412902**

**Fax No.:-0731-2412040 & E-mail ID :- apmcindore@gmail.com**



-: कृषकों से अपील :-

1. किसान भाई अपनी विक्रित कृषि उपज का भुगतान उसी दिन प्राप्त करें, यदि भुगतान प्राप्त नहीं होता है, तो उसकी लिखित सूचना अगले दिन तक मण्डी कार्यालय में अवश्य देवें अन्यथा यह मान लिया जावेगा कि संबंधित कृषक को भुगतान प्राप्त हो गया है तथा इसके बाद की जाने वाली शिकायत को आपसी लेन-देन माना जावेगा।
2. किसान भाई शासन के नियमानुसार राशि रु. 2 लाख रुपये तक का नगद भुगतान प्राप्त करें तथा शेष राशि RTGS/NEFT से प्राप्त कर सकते हैं। तथा चेक के माध्यम से भुगतान प्राप्त न करें।
3. धोखाधड़ी से बचने हेतु किसान भाई अपनी कृषि उपज को मण्डी प्रांगण में अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी को ही खुली नीलाम अथवा सौदा पत्रक एप के माध्यम से ही विक्रय करें तथा मण्डी प्रांगण के बाहर किसी भी स्थिति में सीधे विक्रय न करें।
4. किसान भाई मण्डी प्रांगण में कृषक भोजन, कृषक विपणन पुरस्कार, विश्राम गृह तथा शासन की अन्य सुविधाओं का लाभ उठावें।
5. किसान भाई अपने एंड्राइड मोबाईल में गूगल प्लेस्टोर से ई-मण्डी एप इंस्टाल करें।
6. कृषक भाई इस एप में कृषक पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण करें। इस हेतु अपना न्यूनतम आवश्यक विवरण स्वयं भरें।
7. किसान लॉगिन में जाकर मण्डी इन्दौर का चयन कर अपनी फसल विवरण दर्ज कर प्रवेश पर्ची स्वयं अपने मोबाईल में ही प्राप्त करें।

सचिव  
मण्डी, इन्दौर

अपर कलेक्टर/भारसाधक अधिकारी  
मण्डी इन्दौर

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन भाजपा राज्य में चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। हालांकि पार्टी को चिंता राज्य में कार्यकर्ताओं के एक तबके की नाराजगी की सता रही है। साथ ही चुनाव से पहले पार्टी अपने लोगों को जोड़े रखने, और जोश भरने के लिए राज्यभर में शिवाजी महाराज के नाम पर एक यात्रा निकालने पर भी विचार कर रही है। दरअसल पहले शिवसेना से एकनाथ शिंदे और फिर अजित पवार से भाजपा ने गठबंधन किया और राज्य की सत्ता में भागीदारी दी। अब तैयारी है आगामी विधानसभा चुनावों में भी शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के साथ जाने की। ऐसे में भाजपा कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि अजित पवार के साथ चुनाव में जाने से पार्टी का भ्रष्टाचार का मुद्दा हाशिए पर चला जाएगा। भाजपा के कई नेताओं को ऐसा लगता है कि अजित पवार से गठबंधन करने के कारण भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा की लड़ाई कमजोर पड़ी है। इन नेताओं को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के प्रदेश कार्यकारिणी में दिए उस बयान से मजबूती मिली जिसमें उन्होंने शरद पवार को भ्रष्टाचार का सरगना बताया था। तो वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं की एक चिंता ये भी है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार की पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहती हैं ऐसे में भाजपा कार्यकर्ताओं का हक भी मारा जाएगा।

दूसरी ओर, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) का एक बड़ा धड़ा भी अजित पवार से गठबंधन जारी रखने के पक्ष में नहीं है। शिवसेना का कहना है कि अभी तक राज्य में उसका सीधा मुकाबला एनसीपी से ही होता आया है, जिसकी अगुवाई तब अजित पवार करते थे, ऐसे में अब शिवसेना कार्यकर्ता अजित पवार के लिए काम करने में खुद को असहज पा रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं की चिंता का एक और सबब है। उनका मानना है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री तो बन गए पर सरकार में तमाम पॉलिटिकल पद खाली पड़े हैं जिन्हें भरा ही नहीं गया। इसमें निगम, बोर्ड और ट्रस्ट जैसे सरकार के ढेरों राजनीतिक पद शामिल हैं। यही वजह है कि भाजपा कार्यकर्ताओं के एक बड़े तबके का मत है कि विधानसभा चुनाव में अकेले जाया जाए। भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने महाराष्ट्र भाजपा के इन कार्यकर्ताओं की



## साथ-साथ चुनाव लड़ने पर संशय

### कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिश

भाजपा आलाकमान ने अपने नेताओं को संदेश दिया है कि कार्यकर्ताओं से बात करें, उनको जमीनी हकीकत बताएं। महाराष्ट्र की एनडीए सरकार जल्द ही खाली पड़े राजनीतिक पदों को भरेगी जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को एडजस्ट कर नाराजगी दूर करने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को ये भी आश्वासन दिया जाएगा कि भले पार्टी गठबंधन में है पर स्थानीय निकाय, नगर निगम और नगरपालिका के चुनाव पार्टी अकेले ही लड़ेगी, जिसमें कार्यकर्ताओं के हितों का ध्यान रखा जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने, एकजुट करने और जोश भरने के लिए पूरे राज्य में शिवाजी महाराज के नाम पर एक यात्रा निकालने पर भी विचार कर रही है।

ये इच्छा दिल्ली में भाजपा आलाकमान तक भी पहुंचाई। लेकिन भाजपा आलाकमान का आंकलन है कि दोनों दलों के साथ ही चुनावों में जाने का फायदा होगा। इस आंकलन के पीछे भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का तर्क है कि अगर भाजपा अकेले चुनाव में गई तो संभावना है कि अजित पवार की पार्टी शरद पवार के दल से और शिंदे (शिवसेना) के ज्यादातर नेता उद्धव ठाकरे गुट में जा सकते हैं।

जिसका सीधा चुनावी नुकसान भाजपा को होगा। साथ ही पार्टी आलाकमान का ये भी मानना है कि अजित पवार की एनसीपी के लगभग डेढ़ दर्जन से ज्यादा विधायक अपने-अपने क्षेत्रों के अपने दम पर क्षत्रप हैं और वे जीत के लिए किसी भी दल के मोहताज नहीं हैं। ऐसे में वो गठबंधन में रहें या अलग लड़ें उनकी जीत तय है।

महाराष्ट्र में महायुति की पार्टियों भाजपा, एनसीपी (अजित पवार) और शिवसेना (शिंदे गुट) के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे पर रजामंदी हो गई है। महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री और एनसीपी के नेता अजित पवार ने कहा कि महायुति में सीटों के बंटवारे पर फैसला लगभग तय है। अजित पवार ने यह भी कहा है कि हम सम्मानजनक सीट के लिए लड़ेंगे। अजित पवार ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान इस बारे में बयान दिया है। सीट बंटवारे में महायुति में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, ये भी देखना अहम होने वाला है। इस बीच अजित पवार के बयान पर महायुति के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। इस पर अजित पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, तीन दिन पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों उपमुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी। हमने एक समन्वय समिति बनाई है। सीट आवंटन को लेकर भी जल्द ही चर्चा होगी। चर्चा समाप्त होने के बाद हम उस संबंध में विवरण देंगे। जहां तक मेरी जानकारी है सीट बंटवारे को लेकर कोई मतभेद नहीं है। हम निर्वाचित होने की क्षमता को देखकर ये सभी बातें तय करेंगे। सुनील तटकरे ने कहा कि उस बिंदु पर स्वतंत्र निर्णय का सवाल ही नहीं उठता है।

● बिन्दु माथुर

78वें स्वतंत्रता दिवस  
की शुभकामनाओं सहित...



सचिव ● भार साधक अधिकारी  
कृषि उपज मंडी समिति, उदयपुरा, जिला-रायसेन

78वें स्वतंत्रता दिवस  
की शुभकामनाओं सहित...



सचिव ● भार साधक अधिकारी  
कृषि उपज मंडी समिति, खिरकिया, जिला-हरदा

78वें स्वतंत्रता दिवस  
की शुभकामनाओं सहित...



सचिव ● भार साधक अधिकारी  
कृषि उपज मंडी समिति, बनखेड़ी, जिला-नर्मदापुरम

**का**ंग्रेस की सरकार में अशोक गहलोत के आंख-कान माने जाने वाले नेता अब सचिन पायलट की तरफदारी करते नजर आ रहे हैं। इनमें कुछ नेता मुखर होकर सचिन पायलट की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं तो कुछ अंदरूनी तौर पर सियासी बिसात बिछाने में जुटे हैं। गहलोत गुट के इन नेताओं की एक्टिविटी से सवाल उठ रहा है कि क्या राजस्थान की सियासत का यह कोई नया संकेत है या तारीफ करने वाले नेता खुद का सियासी समीकरण साध रहे हैं? कांग्रेस 2018 से 2023 तक राजस्थान की सत्ता में थी। इसी दौरान साल 2020 में सचिन पायलट और अशोक गहलोत का झगड़ा खुलकर सामने आ गया था। इसके बाद से दोनों के बीच तनातनी बनी रही। 2023 में पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ा और कांग्रेस राजस्थान की सत्ता से बाहर हो गई।

राजस्थान के बसेड़ी से विधायक रहे खिलाड़ी लाल बैरवा 2022 तक गहलोत गुट के नेता माने जाते थे, लेकिन विधानसभा के चुनाव नजदीक आते-आते उनका गहलोत से मोहभंग हो गया। 2023 के विधानसभा चुनाव में बसेड़ी सीट से कांग्रेस ने संजय जाटव को टिकट दे दिया। इससे नाराज खिलाड़ी लाल कांग्रेस से ही निकल गए। वे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में गए, लेकिन वहां भी उनकी दाल नहीं गली। लोकसभा चुनाव में बैरवा करौली-धौलपुर से लड़ना चाहते थे, भाजपा ने इंडु देवी जाटव को उम्मीदवार बना दिया। हालांकि, भाजपा यह सीट कांग्रेस के भजनलाल जाटव से हार गई।

अब खिलाड़ी लाल भाजपा से भी बाहर निकल गए हैं। भाजपा से इस्तीफा देते वक्त उन्होंने सचिन पायलट की जमकर तारीफ की है। खिलाड़ी लाल जिस इलाके में राजनीति करते हैं, वहां सचिन पायलट का सियासी दबदबा मजबूत है। पायलट के करीबी भजनलाल जाटव अभी करौली-धौलपुर से सांसद हैं। उनके प्रचार में पायलट ने करौली में डेरा डाल दिया था। कांग्रेस नेता लोकेश शर्मा अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते उनके विशिष्ट कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी (ओएसडी) थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। शर्मा गहलोत के काफी मुखर हो गए हैं। हाल ही में उन्होंने राजस्थान में फोन रिकॉर्डिंग को लेकर गहलोत पर निशाना साधा था। कहा जा रहा



## गहलोत समर्थकों को पायलट से उम्मीद

है कि शर्मा कुछ महीनों से पायलट के क्लोज सर्किल में आने की कोशिश में जुटे हैं। लोकसभा चुनाव के बीच लोकेश शर्मा ने पायलट की तारीफ भी की थी। उन्होंने कहा था कि गहलोत ने फोन टेप इसलिए कराए थे, जिससे सचिन मुख्यमंत्री न बन सकें।

लोकेश जमीन के जरिए अब राजनीति में एंट्री की कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीकानेर सीट पर दावेदारी की थी, लेकिन टिकट नहीं मिला। लोकेश अब भरतपुर की किसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें पायलट का सहारा सबसे मुफ़ीद लग रहा है। सवाई-माधोपुर से पूर्व विधायक दानिश अबरार अशोक गहलोत के सलाहकार रह चुके हैं। कहा जाता है कि 2020 में जब पायलट के साथ 20 विधायकों ने बगावत की थी, उस वक्त पूरे मामले की जानकारी दानिश ने ही गहलोत को दी थी। गहलोत ने इसके बाद विधायकों को रिजॉर्ट ले जाकर अपनी कुर्सी बचा ली थी। इस घटना की वजह से पायलट और अबरार में दूरी आ गई। 2023 के विधानसभा चुनाव में अबरार ने कई बार

कोशिश की, लेकिन सचिन पायलट उनके लिए प्रचार करने नहीं आए। सवाई माधोपुर सीट गुर्जर, मीणा और मुस्लिम बाहुल्य है। यहां दो समुदाय जिसके पक्ष में वोट करते हैं वो आसानी से चुनाव जीत जाता है। पायलट के न आने की वजह से यहां गुर्जर वोट किरोड़ी लाल मीणा की तरफ मूव कर गया। हाल ही में सवाई माधोपुर में एक कार्यक्रम के दौरान अबरार पायलट के साथ मंच पर नजर आए। यहां उन्होंने पुरानी गलती को भूलकर आगे बढ़ने की बात कही। अबरार ने लोगों से माफ़ी भी मांगी।

ममता भूपेश अशोक गहलोत की सरकार में मंत्री थीं। जब 2020 में कांग्रेस के भीतर बवाल मचा तो ममता ने अशोक गहलोत के पक्ष में स्टैंड लिया, लेकिन 2023 के चुनाव के बाद से उनका भी रुख बदला-बदला सा है। ममता ने सीधे पायलट की तारीफ तो अभी तक नहीं की है, लेकिन उनके करीबी मुरारिलाल मीणा के जरिए पायलट के क्लोज सर्किल में एंट्री की जद्दोजहद में जुटी हुई हैं। ममता को कई बार मुरारी के साथ मंच पर देखा गया है। दरअसल, ममता भूपेश दौसा की सिकराय सीट से चुनाव लड़ती हैं। यह इलाका सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है। 2023 के चुनाव में ममता इस सीट पर 9 हजार मतों से हार गईं। यह सीट भी गुर्जर बाहुल्य है। कहा जा रहा है कि ममता के पक्ष में अगर पायलट मोर्चा संभालते तो यहां का परिणाम कुछ और होता।

● जयपुर से आर.के. बिन्नानी

78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...  
  
 सचिव ● भारत साधक अधिकारी  
 कृषि उपज मंडी समिति, बरेली, जिला-रायसेन

78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...  
  
 सचिव ● भारत साधक अधिकारी  
 कृषि उपज मंडी समिति, रायसेन

78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...  
  
 सचिव ● भारत साधक अधिकारी  
 कृषि उपज मंडी समिति, औबेदुल्लागंज, जिला-रायसेन

**लो** कसभा चुनाव के नतीजों के बाद उग्र में भाजपा कार्यसमिति की बैठक में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के सरकार से बड़ा संगठन बताने वाले बयान को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी सियासी अदावत को जोड़ दिया गया था।

केशव मौर्य अपनी इस बात पर पूरी तरह से कायम हैं और सोशल मीडिया के जरिए लगातार इसी मुद्दे को उठा रहे हैं, जिसके बाद उग्र भाजपा में अंतर्विरोध की चर्चा जोर पकड़ी। ऐसे में सरकार से बड़ा संगठन वाला बयान तब सच साबित होता दिखा, जब नजूल भूमि विधेयक विधानसभा से पास होने के बाद विधान परिषद से जाकर अधर में लटक गया। नजूल भूमि के बिल को भाजपा विधायकों के विरोध के परवाह न करते हुए योगी सरकार ने विधानसभा से पास करा लिया, लेकिन विधान परिषद में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विरोध करके बिल को प्रवर समिति को भेजने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद नजूल भूमि विधान परिषद में जाकर लटक गया है। ऐसे में सवाल उठने लगा कि नजूल संपत्ति विधेयक ने क्या साबित कर दिया है, सरकार से बड़ा संगठन है।

उग्र में भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में तगड़ा झटका लगा है। भाजपा सूबे की 62 सीटों से घटकर 33 सीट पर आ गई है। इस तरह उग्र में भाजपा की जितनी सीटें कम हुई हैं, उतनी ही सीटों से बहुमत से दूर रह गई है। उग्र में मिली हार के बाद से भाजपा में सियासी संग्राम छिड़ा है। इसी बीच केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में पार्टी कार्यसमिति की बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी की मौजूदगी में कहा था कि सरकार से बड़ा संगठन है। इसके बाद से केशव मौर्य फ्रंटफुट पर दिखाई दे रहे हैं और अपने बयान पर अडिग हैं। इस कड़ी में उन्होंने फिर कहा कि संगठन सदा बड़ा रहेगा। केशव के साथ सुर में सुर मिलाते हुए भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी नजर आ रहे हैं। योगी सरकार उग्र की नजूल की जमीन को विकास

# सरकार से बड़ा संगठन



## विधानसभा में बिल पास ही क्यों करवाया ?

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के विरोध जताने के बाद योगी सरकार के नजूल बिल के लटकने से सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। उग्र में भाजपा सरकार आने के बाद यह पहला मौका है, जब विधानसभा से पास होने के बाद किसी बिल को उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने विधेयक का विरोध करते हुए विधान परिषद में लटकवा दिया हो। ऐसे में यह सवाल उठता है कि अगर इस विधेयक को प्रवर समिति ही भेजना था तो सरकार ने इसे विधानसभा से पास ही क्यों करवाया गया? ऐसे में कहा जा रहा है कि सरकार से बड़ा संगठन की बात विधान परिषद में सही साबित हुई।

योजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने की मंशा से उग्र नजूल संपत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबंधन और उपयोग) विधेयक, 2024 लेकर आई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गत दिनों कैबिनेट की बैठक में नजूल भूमि विधेयक बिल को मंजूरी दी। इसके बाद विधेयक को विधानसभा में योगी सरकार के संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक आर्थिक रूप से कमजोर

वर्गों को राहत देने के लिए लाया गया है। साथ ही कहा कि सार्वजनिक महत्व की विभिन्न प्रकार की विकास गतिविधियों के कारण भूमि की निरंतर और तत्काल जरूरत है, जिसे संबंधित हितधारकों को विकास गतिविधियों में उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जा सके।

विधानसभा में बिल पेश होते ही सपा विधायकों के साथ भाजपा के विधायकों ने भी विरोध शुरू कर दिया। भाजपा विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह और हर्षवर्धन वाजपेयी के साथ ही कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह और कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने विरोध जताया था। इस विधेयक को लेकर सिद्धार्थनाथ सिंह और हर्षवर्धन वाजपेयी ने आपत्ति दर्ज करवाई थी। विधेयक में

नजूल की भूमि की लीज रिन्यू करने के बारे स्पष्ट न होने का सवाल सिद्धार्थनाथ सिंह ने उठाया था। योगी सरकार ने विपक्ष के साथ भाजपा के विधायकों का विरोध नजरअंदाज करते हुए बिल को पास करा लिया। नजूल भूमि विधेयक विधानसभा से पास होने के बाद गत दिनों विधान परिषद में पेश किया गया था। केशव प्रसाद मौर्य जैसे ही विधान परिषद सदन में बिल टेबल करने का प्रस्ताव कर ही रहे थे, तभी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी भूपेंद्र चौधरी खड़े हुए और विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की बात कहने लगे। ऐसे में सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने भूपेंद्र चौधरी को रोका और कहा कि पहले विधेयक टेबल तो हो जाने दीजिए। इसके बाद भूपेंद्र चौधरी बैठ गए और जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य ने विधेयक पेश किए, उसके बाद फिर से भूपेंद्र चौधरी फिर खड़े हुए और विधेयक प्रवर समिति में भेजने की कहा कही। उन्होंने कहा कि प्रवर समिति दो महीने में रिपोर्ट देगी और समिति के सदस्यों के नाम बाद में तय कर दिए जाएंगे। विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने भाजपा एमएलसी भूपेंद्र चौधरी के अनुरोध और प्रस्ताव को मंजूर करते हुए बिल को प्रवर समिति को भेज दिया।

● लखनऊ से मधु आलोक निगम

78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...  
  
 सचिव ● भार साधक अधिकारी  
 कृषि उपज मंडी समिति, नरसिंहगढ़, जिला-राजगढ़

78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...  
  
 सचिव ● भार साधक अधिकारी  
 कृषि उपज मंडी समिति, खिलचीपुर, जिला-राजगढ़

78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...  
  
 सचिव ● भार साधक अधिकारी  
 कृषि उपज मंडी समिति, बेगमगंज, जिला-रायसेन

**लो** कसभा चुनाव के बाद भाजपा ने सम्राट चौधरी को बिहार प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया है। सम्राट चौधरी के हटाए जाने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख कारण हैं, वो उनका नीतीश कुमार से बेहतर तालमेल का न होना है। बिहार की सियासत में सम्राट चौधरी को नीतीश का विरोधी नेता माना जाता है। राजनीतिक जानकारों के गुणा-गणित से इतर बिहार भाजपा के पहले भी कई ऐसे नेता रहे हैं, जिन्हें नीतीश कुमार की वजह से हाईकमान ने शंट कर दिया। इनमें कुछ नेता बाद के दिनों में सियासत में असरदार हुए तो कुछ नेपथ्य में चले गए।

2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी तो उसमें भाजपा कोटे से चंद्रमोहन राय को शामिल किया गया। राय को स्वास्थ्य मंत्रालय की कमान सौंपी गई। शुरुआत में राय के लिए सबकुछ ठीक था, लेकिन 2007 के आसपास वे नीतीश के निशाने पर आ गए। 2008 में नीतीश कुमार ने जब कैबिनेट का फेरबदल किया तो उससे राय को ड्राप कर दिया गया। राय की रुखसती से बिहार भाजपा के भीतर बवाल मचा दिया। दिल्ली तक यह विवाद पहुंचा, लेकिन हाईकमान ने मामले को शांत करा दिया। राय इसके बाद राजनीति के नेपथ्य में ही रह गए। उन्हें न तो बिहार कैबिनेट और न ही देश की राजनीति में कुछ बड़ा पद मिला। साल 2015 में राय को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया। 2010 के विधानसभा चुनाव से पहले सीपी ठाकुर को भाजपा की कमान मिली। उस वक्त भाजपा-जेडीयू के साथ गठबंधन में थी। सीट बंटवारे के दौरान सीपी ठाकुर और नीतीश कुमार के बीच तलखी आ गई, जिसके बाद नीतीश ने सीधे भाजपा हाईकमान से संपर्क किया। हाईकमान ने समझौते के तहत नीतीश को पटना की दीघा सीट दे दी। इससे नाराज होकर चुनाव के बीच ही सीपी ठाकुर ने इस्तीफा दे दिया। कहा जाता है कि ठाकुर ने यह इस्तीफा प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत दिया था, लेकिन नीतीश टस से मस नहीं हुए। 2010 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को जबर्दस्त जीत मिली। नीतीश कुमार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। कयास लगाए जा रहे थे कि ठाकुर को सरकार में कोई बड़ा पद मिलेगा, लेकिन नीतीश कुमार ने सुशील मोदी के साथ ही काम करने की इच्छा

# नीतीश के कारण डिमोशन



## नीतीश के बिना नैया पार नहीं लगेगी

जानकार कहते हैं कि नीतीश को नेता मानने की सबसे बड़ी वजह ये है कि भाजपा ये मानकर चल रही थी कि वो लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन न वे बिहार में अच्छा कर सकी और न ही केंद्र में अपने दम पर बहुमत हासिल कर सकी। भाजपा के कई बड़े नेता और मंत्री भी अपनी सीट खो बैठे। इसके बाद अब इन्हें ये समझ आ रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के बिना इनकी नैया पार होने वाली नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार अब इनके लिए मजबूरी बन गए हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद जो सामाजिक समीकरण निकलकर सामने आए हैं, उसमें भाजपा के उस दंभ की हवा निकल गई है, जिसमें वे अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे। लोकसभा में अगर भाजपा अकेले चुनाव लड़ती तो बिहार में उसके परिणाम और बुरे हो सकते थे। चुनाव में जदयू का स्ट्राइक रेट भी भाजपा से अच्छा रहा है।

जताई। हाईकमान ने उनकी बात मान ली और सीपी ठाकुर संगठन में ही रह गए।

एक वक्त भाजपा के कद्दावर नेता रहे गोपाल नारायण सिंह को भी भाजपा ने सम्राट की तरह ही शंट कर दिया था। दरअसल, साल 2005 में विधानसभा के चुनाव होने थे। भाजपा की तरफ से गोपाल नारायण सिंह अध्यक्ष थे। पार्टी के भीतर और बाहर उन्हें ही चेहरा बताया जा रहा था, लेकिन चुनाव से 3 महीने पहले ही उन्हें पद से हटा दिया। सिंह के बदले सुशील मोदी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। 2005 में भाजपा और जेडीयू की सरकार बनी और सुशील मोदी उपमुख्यमंत्री बनाए गए। गोपाल नारायण सिंह तब तक शॉटिंग जोन में रहे, जब तक भाजपा और जेडीयू की सरकार थी। साल 2016 में भाजपा ने गोपाल नारायण सिंह को राज्यसभा भेजा। राज्यसभा सांसद बनने के बाद सिंह नीतीश पर काफी मुखर रहे। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद

भाजपा नेताओं के सुर अचानक बदल गए हैं। जनवरी से पहले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने तक पगड़ी बांधे रहने की सौगंध खाने वाले (जनवरी में गठबंधन के बाद उन्होंने इसके कारण भी बताया) उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नतीजे के बाद कहा- हम नीतीश के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ेंगे। हम 1996 से नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं।

● विनोद बक्सरी

78वें  
**स्वतंत्रता दिवस**  
की शुभकामनाओं सहित...



सचिव ● भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, नर्मदापुरम, जिला-नर्मदापुरम

78वें  
**स्वतंत्रता दिवस**  
की शुभकामनाओं सहित...



सचिव ● भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, पचौर, जिला-राजगढ़

78वें  
**स्वतंत्रता दिवस**  
की शुभकामनाओं सहित...



सचिव ● भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, कुरावर, जिला-राजगढ़

78वें  
**स्वतंत्रता दिवस**  
की शुभकामनाओं सहित...



सचिव ● भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, ब्यावरा, जिला-राजगढ़

# नया गठजोड़, नई सरकार

नेपाल में दो वर्ष के भीतर एक बार फिर सरकार बदल गई। केपी शर्मा ओली की अगुवाई वाले सीपीएन-यूएमएल के समर्थन से पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड 25 दिसंबर, 2022 को प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन अल्पमत में होने के कारण उनकी सरकार कभी स्थिर नहीं रह पाई। 19 महीने में उन्हें पांच बार विश्वास मत का सामना करना पड़ा। हालांकि वे चार बार विश्वास मत हासिल करने में सफल रहे, लेकिन पांचवीं बार ओली के गठबंधन से बाहर होने और समर्थन वापस लेने पर वे बहुमत साबित नहीं कर सके। अब केपी शर्मा ओली नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेपाल में हुई राजनीतिक उठापटक का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वहां 16 वर्ष में 13वीं बार सरकार गिरी है। अब बदले राजनीतिक समीकरण में ओली की सीपीएन-यूएमएल और शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस साथ आई हैं। दोनों के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत दोनों बारी-बारी तीन साल तक सरकार चलाएंगे। ओली को 30 दिन के भीतर बहुमत साबित करना होगा।

275 सीटों वाली नेपाली संसद में प्रचंड की माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पास मात्र 32 सांसद हैं, जबकि सीपीएन-यूएमएल के पास 78 और नेपाली कांग्रेस के पास 89 सांसद हैं। यानी नेपाली कांग्रेस और सीपीएन-यूएमएल गठबंधन के पास 167 सांसद हैं। इनके अलावा जनता समाजवादी पार्टी के पास 5, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के पास 14 और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के पास 4 सांसद हैं। नेपाली संसद की 165 सीटों पर प्रत्यक्ष मतदान हुआ था, जबकि 110 सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से हुआ। ओली को बहुमत साबित करने के लिए 138 सांसदों की जरूरत है, जबकि गठबंधन के पास 167 सांसद हैं।

संविधान संशोधन के मुद्दे पर जब कम्युनिस्ट पार्टियां एक साथ आई थीं, तो देश में राजनीतिक स्थिरता की उम्मीद जगी थी। चुनाव में वामपंथी दलों को लगभग दो तिहाई बहुमत भी मिला। इसलिए सभी को यह लग रहा था कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। लेकिन सत्ता का सुख भोग रही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और गठबंधन में शामिल रहने के बावजूद सत्ता से दूर रहने वाले गुट के बीच अविश्वास बढ़ता



## फिर संविधान संशोधन!

दरअसल, राजनीतिक कलाबाजी के अलावा कुछ और भी मुद्दे हैं, जिनके कारण संविधान में आमूल-चूल परिवर्तन की मांग उठ रही है। संविधान की प्रस्तावना में संघीयता, समानुपातिक, समावेशी जैसे शब्दों का उल्लेख है, लेकिन वास्तव में इनकी आवश्यकता है? क्या जनप्रतिनिधि इसके मर्म और भाव को समझ पा रहे हैं? नेपाल का अर्थतंत्र 7 प्रदेशों का बोझ सहन कर सकता है या नहीं? संविधान की प्रस्तावना में बदलाव के लिए दो तिहाई बहुमत चाहिए। ताजा समीकरण राजनीतिक परिस्थिति के चलते भले ही बन गया हो, लेकिन इसके पीछे वास्तविक उद्देश्य संविधान संशोधन भी है। ओली की सत्ता में वापसी से राजनीतिक स्थिरता को लेकर लोगों में एक उम्मीद तो जगी ही है, दो बड़े दलों के साथ आने से संविधान संशोधन का मुद्दा भी चर्चा के केंद्र में आ गया है। हालांकि प्रधानमंत्री बनने के बाद ओली ने अपने लेख में देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने और आम लोगों का जीवन स्तर उठाने की बात कही है। भले ही लेख में ओली ने संविधान संशोधन का जिक्र नहीं किया है, पर दोनों दलों के नेता इस मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। ओली-देउबा छोटे दलों पर अंकुश लगाने पर भी विचार कर रहे हैं।

गया। दोनों गुटों में हर मुद्दे पर मतभेद इतने बढ़ गए कि गठबंधन दल के नेता अपनी ही सरकार और पार्टी के प्रधानमंत्री के विरुद्ध सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे। पार्टी की बैठकों में सरकार की नीतियों की आलोचना होने लगी, प्रधानमंत्री के विरुद्ध पार्टी के नेता समाचार-पत्रों में लेख लिखने लगे और मीडिया में खबरें लीक करने लगे। इसी बीच, पार्टी की एकता को चुनौती देने वाली याचिका पर अदालत का फैसला आया, जिससे वामपंथी दल फिर से अलग होने को मजबूर हो गए। इसके बाद राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हुआ।

खैर, 2022 में फिर चुनाव हुए तो किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। उस समय लग रहा था कि कांग्रेस और माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी की गठबंधन सरकार बन जाएगी और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेरबहादुर देउबा प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन प्रचंड अड़े रहे, जबकि उनकी पार्टी के पास मात्र 32 सांसद थे। ओली भी प्रचंड को सत्ता से दूर रखना चाहते थे। लेकिन आखिरी दो घंटों में ओली पलट गए और प्रचंड को समर्थन दे दिया। इससे देउबा को सत्ता से दूर रहना पड़ा। इस तरह, ओली-प्रचंड की गठबंधन सरकार बनी। फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद एक महीने में ही प्रचंड ने ओली को दरकिनार कर देउबा के साथ गठबंधन कर लिया।

● ऋतेन्द्र माथुर

78वें  
**स्वतंत्रता दिवस**  
की शुभकामनाओं सहित...

सचिव ● भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, बैरसिया, जिला-मोपाल

78वें  
**स्वतंत्रता दिवस**  
की शुभकामनाओं सहित...

सचिव ● भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, सिरोंज, जिला-विदिशा

78वें  
**स्वतंत्रता दिवस**  
की शुभकामनाओं सहित...

सचिव ● भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, नसरुल्लागंज, जिला-सीहोर

हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या किए जाने के बाद इजराइल और हमास के बीच जंग और तेज होने की आशंका है। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम कराने की कोशिशों को भी इस घटना से गहरा झटका लगा है। फिलिस्तीनी समूह हमास के सदस्यों द्वारा 7 अक्टूबर, 2023 को इजराइल पर किए गए हमले से शुरू हुई भीषण

जंग में अब तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और गाजा पट्टी के कई शहर तहस-नहस हो चुके हैं। हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हानिया की मौत के साथ 7 अक्टूबर के हमले के बाद जीवित हमास के वरिष्ठ नेताओं की संख्या एक हाथ की उंगलियों से भी कम रह गई है। हानिया और मारवान ईसा की मौत के बाद इजराइल ने 1 अगस्त को मोहम्मद देएफ की मौत की घोषणा की। इसके बाद अब याह्या सनवार, खालिद मेशाल और महमूद जहर हमास के सबसे प्रमुख जीवित नेता बचे हैं, जो इजराइल के टारगेट पर लंबे समय से हैं और कई बार पहले भी उनको मारने का प्रयास मोसाद या दूसरी एजेंसियों के द्वारा किया गया है।

पिछले महीनों में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि वह किसी भी तरह से हमास के पूरे नेतृत्व को नष्ट कर देंगे। हमास की लीडरशिप में शामिल अधिकांश नेताओं के बारे में बहुत कम जानकारी है, और उनमें से कई ने अपना अधिकांश जीवन इजराइल के डर से छिपकर बिताया है। गाजा पट्टी में याह्या सनवार और अन्य हमास नेता शायद खान यूनिस् में भूमिगत सुरंगों में छिपे हुए हैं। हमास के सूत्रों के मुताबिक, उसके ठिकाने के बारे में केवल दो या तीन लोगों को ही पता है, लेकिन वह अभी भी गाजा के अंदर और बाहर इस समूह के नेताओं के संपर्क में है। केंद्रीय खुफिया एजेंसी (सीआईए) के आंकलन के अनुसार, गाजा में हमास के नेता के रूप में सनवार पर हाल के हफ्तों में युद्धविराम पर सहमत होने और इजराइल के साथ युद्ध खत्म करने के लिए अपने सैन्य कमांडरों से अधिक दबाव रहा है।

याह्या सनवार का जन्म 1962 में गाजा पट्टी में हुआ था। वह हमास सुरक्षा सेवा के संस्थापक हैं, जिन्हें मज्द के नाम से जाना जाता है, जो आंतरिक सुरक्षा मामलों का प्रबंधन करती है और संदिग्ध लोगों, इजराइली खुफिया और सुरक्षा सेवाओं के अधिकारियों की जांच और उनके बारे में पता लगाती है। सनवार को इजराइल ने तीन बार गिरफ्तार किया है। 1988 में गिरफ्तारी के बाद उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में एक इजराइली सैनिक के बदले में

127 फिलिस्तीनी और अरब-इजराइल कैदियों के साथ रिहा कर दिया गया, जिसे हमास ने पांच साल से अधिक समय तक बंदी बनाकर रखा था। याह्या सनवार हमास के एक प्रमुख नेता के रूप में अपने पद पर लौट आए और 2017 में गाजा पट्टी में समूह के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख बन गए। सितंबर 2015 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने उसका नाम

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की काली सूची में डाल दिया।

खालिद मेशाल का जन्म 1956 में वेस्ट बैंक में हुआ था और वह हमास समूह के संस्थापकों में से एक है। एक समय इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सीधे आदेश पर मोसाद खुफिया एजेंसी ने 1997 में उनकी हत्या का प्रयास किया था, उस वक्त खालिद मेशाल जॉर्डन में रह रहा था। मोसाद एजेंट नकली कनाडाई पासपोर्ट के साथ जॉर्डन में दाखिल हुए और सड़क पर चल रहे मेशाल को जहरीला पदार्थ इंजेक्ट किया। जॉर्डन के अधिकारियों ने इस हत्या के प्रयास का पता लगाया और मोसाद के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। जॉर्डन के दिवंगत राजा हुसैन ने इजराइल के प्रधानमंत्री से मेशाल में इंजेक्ट किए गए जहर के एंटीडोट की मांग की। पहले तो नेतन्याहू ने जॉर्डन के राजा के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, लेकिन उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के दबाव में वह एंटीडोट देने के लिए सहमत हो गए।

मेशाल (अब कतर में रहते हैं) ने पहली बार 2012 में गाजा पट्टी का दौरा किया था और फिलिस्तीनी अधिकारियों व लोगों की भीड़ ने उसका स्वागत किया था। 2017 में, हमास ने समूह के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख के रूप में मेशाल के उत्तराधिकारी के रूप में इस्माइल हानिया को चुना। इसके बाद मेशाल को विदेश में समूह के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। महमूद जहर का जन्म 1945 में गाजा में हुआ, उनके पिता फिलिस्तीनी और मां मिस्त्र की थी। वह हमास के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक हैं और इस आंदोलन के राजनीतिक नेतृत्व के सदस्य हैं। जहर गाजा स्कूल गए और काहिरा में अपनी विश्वविद्यालय की

पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने गाजा और खान यूनिस् में एक डॉक्टर के रूप में काम किया, जब तक कि इजराइली अधिकारियों ने उनकी राजनीतिक स्थिति के कारण उन्हें निकाल दिया। महमूद जहर को 1988 में और हमास की स्थापना के कुछ महीनों बाद इजराइली जेलों में कैद कर दिया गया था।

● कुमार विनोद

## क्या खत्म होगा हमास

78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...

अपील

- नीलामी के समय किसान भाई अपने ढेर पर उपस्थित रहें।
- किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।

सचिव • भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, टिमरनी, जिला-हरदा

78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...

अपील

- सभी किसान भाई मुख्यमंत्री हकमाल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।

सचिव • भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, बानापुरा, जिला-नर्मदापुरम

78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...

अपील

- अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
- नीलामी के समय किसान भाई अपने ढेर पर उपस्थित रहें।
- सही तौल एवं समय पर भुगतान पाएं।

सचिव • भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, इटारसी, जिला-नर्मदापुरम

78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...

अपील

- नीलामी के समय किसान भाई अपने ढेर पर उपस्थित रहें।
- अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।

सचिव • भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, पिपरिया, जिला-नर्मदापुरम



## समय पर ब्रेस्ट फीडिंग कराना जरूरी



दुनियाभर में हर साल 1 से 7 अगस्त तक वर्ल्ड ब्रेस्टफीडिंग वीक 120 से अधिक देशों में मनाया जाता है। इसके जरिए लोगों को ब्रेस्टफीडिंग के बारे में जागरूक किया जाता है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि मां का दूध बच्चे को सभी जरूरी पोषक तत्वों को प्रदान करता है। इससे बच्चे में मालनूट्रिशन की आशंका कम हो जाती है। ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे को अस्थमा, मोटापा और टाइप 1 डायबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा कम रहता है। बच्चे को मां का दूध मिलने से कान के इन्फेक्शन और पेट की बीमारियों से भी बचाव होता है।

बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराने से कैंसर और टाइप-2 जैसी बीमारियों का रिस्क भी कम होता है। मैक्स हॉस्पिटल गुरुग्राम में आब्सेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी विभाग में सीनियर डायरेक्टर और यूनिट हेड डॉ. सुमन लाल बताती हैं कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराने से पोस्टपार्टम रिकवरी में भी मदद करता है। इससे महिला ब्रेस्ट कैंसर के खतरे से भी बच सकती है। बच्चे के लिए भी मां का दूध काफी जरूरी होता है। अगर सही समय तक यह न मिले तो

बच्चे को कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं।

डॉ. सुमन लाल के मुताबिक, सफल ब्रेस्टफीडिंग के लिए स्किन से स्किन का संपर्क जरूरी है। अगर बच्चा हाथ चूस रहा है या काफी मूवमेंट कर रहा है तो यह संकेत है कि उसको भूख लग रही है। बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए आरामदायक स्थिति सुनिश्चित करना जरूरी है ताकि बच्चे को सही से दूध पिलाया जा सके और मां और बच्चे दोनों को असुविधा कम हो। ब्रेस्ट फीडिंग के बाद बच्चे को डकार आना जरूरी है। यह संकेत है कि उसका पेट भर गया है।

अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, जन्म के बाद से 6 महीने तक केवल स्तनपान कराना चाहिए। उसके बाद पूरक आहार के साथ दो साल या उससे अधिक समय तक स्तनपान कराएं। इस दौरान ध्यान रखें कि बच्चे को केवल मां का दूध ही पिलाएं किसी तरह का बाजार से आने वाला दूध या गाय, भैंस का दूध बिलकुल न दें। इससे बच्चे की सेहत बिगड़ सकती है।

● ज्योत्सना

### 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...



सचिव • भार साधक अधिकारी

अपील

- किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
- सही तौल एवं समय पर मुगदान पाएं।
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
- सभी किसान भाई मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।

कृषि उपज मंडी समिति, भोपाल

### 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...



सचिव • भार साधक अधिकारी

अपील

- सभी किसान भाई मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।

कृषि उपज मंडी समिति, बैतूल

### 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...



सचिव • भार साधक अधिकारी

अपील

- नीलामी के समय किसान भाई अपने ढेर पर उपस्थित रहें।
- किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
- सही तौल एवं समय पर मुगदान पाएं।

कृषि उपज मंडी समिति, गंजबासौदा, जिला-विदिशा

### 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...



सचिव • भार साधक अधिकारी

अपील

- सभी किसान भाई मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।

कृषि उपज मंडी समिति, विदिशा

### 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...



सचिव • भार साधक अधिकारी

अपील

- किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
- सही तौल एवं समय पर मुगदान पाएं।

कृषि उपज मंडी समिति, हरदा

वन्दे देव उमापतिम् सुरगुरुं वन्दे जगत् कारणं,  
वन्दे पन्नग भूषणं मृगधरम् वन्दे पशूनाम्पतिम्!  
वन्दे सूर्य शशांकं वह्निनयनम् वन्दे मुकुन्दप्रियम्,  
वन्दे भक्त जनाश्रयम् च वरदम् वन्दे शिवम् शंकरं!!

महादेव की इस स्तुति में प्रकृति संरक्षण का जो दिव्य संदेश निहित है, वह अपने आप में अनूठा है। शिव की आराधना हमें प्रकृति को पूजना और सहेजना सिखाती है। भौतिक सुखों से दूर आत्मिक सुख और जन कल्याण की सोच के साथ शिव जिस धैर्य और दृढ़ता के साथ प्रकृति की गोद में रमते हैं, वैसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता।

शिव और शक्ति के सम्भाव समन्वय से ही सृष्टि का संतुलन कायम रह सकता है। इसी कारण हमारे सनातन हिन्दू धर्म दर्शन में महादेव शिव को लोकमंगल के महानतम देवता और श्रावण माह को शिव तत्व के जागरण का सर्वाधिक फलदायी साधनाकाल माना जाता है। शास्त्रीय मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के दिन से जगतपालक श्रीहरि विष्णु के चातुर्मास कालीन योगनिद्रा में चले जाने के फलस्वरूप सृष्टि संचालन का कार्यभार देवाधिदेव महादेव संभालते हैं। शास्त्र कहते हैं कि शिव, प्रकृति और सावन का संबंध बहुत गहरा है। परम पुरुष (शिव) और मां प्रकृति (भवानी) का मंगलमय पुनर्मिलन ही इस परम पवित्र साधनाकाल की आध्यात्मिक आर्द्रता है। मात्र एक लोटा जल व विल्व पत्र से सहज प्रसन्न हो जाने वाले औषधदानी भोलेनाथ की अतीव कृपा इस ऋतु में धरतीवासियों पर बरसती है।

शिव महापुराण के अनुसार समुद्र मंथन की महान पौराणिक घटना इसी श्रावण मास में घटित हुई थी। देवों और असुरों के मध्य हुए इस सागर मंथन में सबसे पहले निकले कालकूट विष की प्रचंड विषाक्तता से सृष्टि की रक्षा के लिए महादेव ने उस हलाहल को अपने कंठ में धारण कर लिया था। जब उस विषपान से महादेव के शरीर का ताप बहुत बढ़ गया और जहर की तीव्रता के कारण वे अर्द्धमूर्च्छित हो गए तब देवराज इंद्र ने मूसलाधार वर्षा कर तथा अन्य सभी देव-दानवों ने जलाभिषेक कर शिव के शरीर को शीतलता प्रदान की। तभी से श्रावण मास में शिव को जलाभिषेक की परंपरा का शुभारंभ माना जाता है।

श्रावण मास में प्रकृति अपने समूचे श्रृंगार के साथ महाकाल का महारुद्राभिषेक करती नजर आती है। वन-उपवन में हरियाली, फूल-फल से लदी पेड़-पौधों की डालियां, कोयल की कूक, नदी-तालाब और झरनों का कल-कल निनाद; प्रकृति का यह हरा-भरा मनमोहक सौंदर्य महादेव को खूब लुभाता है। श्रावण मास में शिव के जलाभिषेक को निकलने वाली कांवड़ यात्राओं का हर-हर महादेव और बम-बम भोले का जयघोष चहुंओर एक अनूठी आध्यात्मिक ऊर्जा का सृजन करता प्रतीत होता है।

पूरी श्रद्धा से अपने कंधों पर कांवड़ों को धारण करने वाले शिवभक्तों की टोली जब केसरिया वस्त्र धारण कर हर-हर, बम-बम की जयकार करती हुई महादेव को जलाभिषेक के लिए निर्धारित गंतव्यों पर निकलती है तो भक्ति का यह स्वतः स्फूर्त जनसमूह राष्ट्र की सामाजिक समरसता का ऐसा अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है जिसमें गरीब-अमीर, अगड़े-पिछड़े, छोटे-बड़े सब एकरस हो उठते हैं। ज्ञात हो कि शिव महापुराण में भगवान शिव को बिल्व पत्र चढ़ाने का भी विशेष महत्व बताया गया है। तीन पत्तों वाला अर्खंडित बिल्व पत्र शिव पूजन का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इसका तत्वदर्शन यह है कि बिल्व पत्र के ये तीन पत्ते धर्म, अर्थ व काम इन तीन पुरुषार्थों के प्रतीक हैं। शिव भक्त जब इन तीनों पुरुषार्थों को निस्वार्थ भाव से साध लेता है तो भगवान शिव की कृपा से चौथा पुरुषार्थ मोक्ष उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाता है।

श्रावण मास के आध्यात्मिक महात्म्य की अत्यंत सारगर्भित व्याख्या करते हुए युगगुरु पंडित श्रीराम शर्मा लिखते हैं, सावन का महीना प्रकृति के निकट जाने और शिव की शिक्षाओं को हृदयंगम कर प्रकृति के समस्त घटकों को

संरक्षित करने है। यही सच्ची शिव आराधना है, सच्चा रुद्राभिषेक है। जीव व जगत के कल्याणकर्ता शिव प्रकृति व जीवों का संरक्षण कर मानव को संदेश देते हैं कि प्रकृति को उजाड़ो मत, जीवों को सुरक्षित व संरक्षित करने के लिए सर्वत्र मदद करो। इसलिए शिव पशुपतिनाथ बनकर पूजे जाते हैं। श्रावण में शिवोपासना का मर्म है अपने अंदर के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का सत्प्रयत्न। मानव का मन ही उसके मोक्ष और बंधन का मूल कारण है। इसे श्रावण में ज्ञानयोग की साधना से ही साधा जा सकता है। इसके लिए गुरुपूर्णिमा से श्रावणी पूर्णिमा तक शास्त्रों के सत्संग, प्रवचन व धर्मोपदेश सुनने व चिंतन-मनन का विधान हमारे मनीषियों ने बनाया है। इसे सिर्फ शिवकृपा से ही नियंत्रित किया जा सकता है।

शास्त्रज्ञ कहते हैं कि एकमात्र शिवतत्व ही स्वयंभू है। महादेव शिव अपने संपूर्ण स्वरूप से जिस तरह समूची प्रकृति को रूपायित करते हैं, वह अपने आप में विलक्षण है। देवाधिदेव शिव प्रकृति के महानतम देवता हैं। सृष्टि और समष्टि के कल्याण के लिए अपने अर्द्धनारीश्वर रूप में वे प्रत्येक जीव को सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो लोकमंगलकारी शिक्षण देते हैं, वह वर्तमान के पर्यावरणीय असंतुलन को साधने में अत्यन्त कारगर है। देवाधिदेव का प्रकृति से जुड़े रहना और साधारण जीवन आज के आमजन के लिए प्रेरणादायी है। शिव के सभी रूप भक्तों के लिए कल्याणकारी हैं। वे सभी रूपों में पूजनीय हैं और जीवन का संदेश देते हैं।

● ओम

## महादेव से सीखें प्रकृति संरक्षण के दिव्य सूत्र

## 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...

**अपील**

- ◆ किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
- ◆ मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय अपनी कृषि उपज आवश्यक रूप से दर्ज कराएं।
- ◆ सही तौल एवं समय पर भुगतान पाएं।
- ◆ नीलामी के समय किसान भाई अपने ढेर पर उपस्थित रहें।
- ◆ मुख्यमंत्री हममाल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।
- ◆ मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।

सविव

भार साधक अधिकारी

**कृषि उपज मंडी समिति, उज्जैन**

**कि** तना अच्छा लगता है जब किसी गली में बच्चों की आवाज सुनाई देती है कान में जैसे किसी ने मिसरी सी खोल दी है। जैसे ढेर सारी कोयल एक साथ बोल रही हो। इसी सोच खोए हुए रमेश को टोकते हुए रामनाथ काका ने कहा।

अरे रमेश देखना गली में वानर सेना आ गई है। कहीं हमारे घर की खिड़की का शीशा न तोड़ दे। उन लोगों का कोई भरोसा थोड़ी ही रहता है। शैतान... शैतान हैं जाने कहां से आ जाते हैं उनके माता-पिता नहीं रोकते होंगे। इतने अच्छे लगते हैं तो अपने घरों के शीशे तुड़वाए। तब पता चले उनको कि किन शैतानों को जन्म दिया है। रामनाथ

## बचपन



नहीं आता है अगर चला जाए तो।

चाचा ने चिढ़ते हुए कहा।

रमेश बोला- अरे चाचा उनका बचपन है वो शरारत नहीं करेंगे तो क्या हम करेंगे। कभी कभार उनकी गेंदों से शीशा टूट जाता है। तो उस पर इतना आसमान सिर पर उठाना ठीक नहीं है। बच्चे हैं, बच्चे हैं।

रामनाथ चाचा- तू तो उनका वकील हो जा। इसी बहाने चार पैसे घर लाया करेगा। उनका केश लड़ना। और मोटी फीस लेना।

अरे फीस क्यों लूंगा उन मासूम फरिश्तों से। बचपन का सम्मान करो चाचा। ये फिर लौटकर

- अभिषेक जैन

**सां** झ हो चली थी, अंधेरों की काली छाया धीरे-धीरे अपना पांव पसार रही थी, पंछियां अपने घोंसलों को लौट रही थीं। मंदिरों में घंटियां बजने लगीं, गायों का झुंड अपने बसेरों में पहुंचने को ललालित हो रम्भाते दौड़ लगा रही थीं। गांवों के लट्टू टिमटिमाते नजर आ रहे थे। इधर बिरजू भी सोच रहा था कि कब उसका काम खत्म हो और वह फौरन अपने घर पहुंचे। दरअसल में वह एक मजदूर था। जो एक



## प्रतीक्षा

निश्चित राशि के एवज में एक जमींदार के यहां मजदूरी करता था। उसका मालिक उसे कब? क्या? कौन सा काम? भिड़ा देता कोई निश्चित नहीं रहता।

आज वह अपने मालिक की आज्ञा का पालन करते हुए दोपहर से काम किए जा रहा है। आज कुछ ज्यादा ही काम था और छुट्टी होने

में देरी हो गई। उसके मालिक ने कहा- बिरजू आज कुछ देरी हो गई है रात हो चली है तुम हमारे साथ हमारे घर में ही खाना खा के जाना!

तभी कांपती आवाज में बिरजू कहता है- नहीं-नहीं मालिक मुझे जाना होगा!

तब उसका मालिक कहता है- इतनी हड़बड़ी और जल्दी क्यों है बिरजू? तब बिरजू कहता है- मालिक! मेरे घर में किसी की पथराई आंखें, किसी की ममता, किसी का भरोसा, किसी का स्नेह मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको भला मैं कैसे भूला सकता हूं। और फिर क्या था उसने अपना परोसा खाना पोटली बनाया और वह झट से निकल पड़ता है। मालिक को समझ में आ गया था, और गंभीर हो उसे देखने लगा।

- अशोक पटेल 'आशु'



# 78वें स्वतंत्रता दिवस

की शुभकामनाओं सहित...

**अपील**

- ♦ किसान माई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
- ♦ मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
- ♦ नीलामी के समय किसान माई अपने ढेर पर उपस्थित रहें।

- ♦ मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय अपनी कृषि उपज आवश्यक रूप से दर्ज कराएं।
- ♦ सही तौल एवं समय पर भुगतान पाएं।
- ♦ मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।

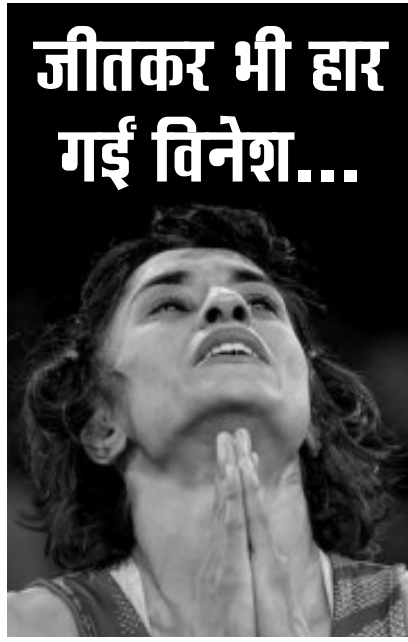
सचिव
•
भार साधक अधिकारी

## कृषि उपज मंडी समिति, देवास

पेरिस ओलंपिक में महिलाओं के 50 किलो भार वर्ग के फ्रीस्टाइल दंगल में विनेश फोगाट ने धुआंधार शुरुआत की थी। अपने पहले ही मैच में डिफेंडिंग चैंपियन को धूल चटाई तो क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में जबरदस्त प्रदर्शन कर फाइनल का सफर तय करने वाली भारत की पहली महिला रेसलर भी बन गई थी। लेकिन अब गोल्ड मेडल मुकाबले से जिस तरह उन्हें ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है वो उनके लिए जीतकर भी मिली हार की तरह है।

भारतीय रेसलर विनेश फोगाट का वजन तय मानकों से महज 100 ग्राम अधिक हो जाने के कारण उन्हें फाइनल मैच खेलने से अयोग्य करार दे दिया गया। यह जानकर सभी हैरान हैं कि ओलंपिक खेलों के लिए बेहद कड़ी ट्रेनिंग से गुजरने वाली विनेश फोगाट और उनकी टीम से यह गड़बड़ी कैसे हो गई? विनेश का वजन अब तक बिल्कुल ही रेंज में चल रहा था, फिर यह अचानक बढ़ कैसे गया? क्या फोगाट और उनकी टीम को इसकी जानकारी हो गई थी। क्या इसे ठीक करने की कोशिश की गई थी या फिर यह कोई साजिश है? ऐसे कई सवाल मीडिया और सोशल मीडिया में तैर रहे हैं।

खबरों के अनुसार फोगाट और उनकी टीम को इस खतरे की जानकारी एक दिन पहले ही हो गई थी। वजन को नियंत्रित करने के लिए टीम ने कड़ी एक्सरसाइज करने के साथ-साथ कई अन्य प्रयास भी किए थे, लेकिन अंततः वे इसमें सफल नहीं हो पाए और फोगाट को इसका नुकसान



उठाना पड़ा। बताया जा रहा है कि प्री क्वार्टर फाइनल में उतरने से पहले विनेश का जो वजन मापा गया था, तब वो 49.9 किलो की थीं, जो कि 50 किलो भारवर्ग में उतरने के लिए ठीक था। लेकिन तीन राउंड, प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल खेलने के बाद उनका वजन 52.7 किलो हो गया जो कि 2.8 किलो ज्यादा था। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार विनेश का 2.8 किलो वजन महज 12 घंटे के अंदर बढ़ा कैसे?

पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अपने बयान में कहा कि पहलवान आमतौर पर अपने प्राकृतिक वेट कैटेगरी से कम वेट कैटेगरी में हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं। यह उन्हें एक एडवांटेज देता है कि जो पहलवान उनके सामने आएंगे, वह उनसे कम ताकतवर होंगे। यह जो वजन घटाने की प्रक्रिया है वजन मापने वाले कार्यक्रम से पहले, उसमें काफी खतरा होता है और काफी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। इसके अलावा एथलीट को काफी पसीना बहाना होता है। यह एक यंत्र के द्वारा किया जाता है और व्यायाम का इस्तेमाल होता है। साथ ही इसमें स्टीम का भी इस्तेमाल किया जाता है। यह भले ही उन्हें हल्के वेट कैटेगरी में ले जाता है, लेकिन इससे एथलीट में कमजोरी और ऊर्जा में कमी आती है। इससे आपको उस कैटेगरी में खेलने में मुश्किल आती है।

ऊर्जा को बनाए रखने के लिए हम एथलीट्स को पानी और उन्हें कुछ ऊर्जावान खाना देते हैं। यह एक तरह से काउंटर बैलेंस करता है। अगर आप वजन घटा सकते हैं तो आप, अच्छे खिलाड़ी के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। कई पहलवान ऐसा करते हैं। एक स्ट्रेटजी होती है जिसके तहत आप अपनी ऊर्जा को वापस पा सकते हैं, लेकिन पानी और खाना के अमाउंट को भी देखना होता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए पहलवान के साथ मौजूद टीम जिम्मेदार होती है।

● आशीष नेमा

78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...

अपील

- नीलामी के समय किसान भाई आपसे डेर पर उपस्थित रहें।
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
- किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।

सचिव • भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, नीमच

78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...

अपील

- मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय अपनी कृषि उपज आवश्यक रूप से दर्ज कराएं।
- मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।
- सही तौल एवं समय पर भुगतान पाएं।

सचिव • भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, मंदसौर

78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...

अपील

- मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय अपनी कृषि उपज आवश्यक रूप से दर्ज कराएं।
- सही तौल एवं समय पर भुगतान पाएं।

सचिव • भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, महिदपुर, जिला-उज्जैन

78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...

अपील

- मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय अपनी कृषि उपज आवश्यक रूप से दर्ज कराएं।
- मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।
- सही तौल एवं समय पर भुगतान पाएं।

सचिव • भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, बड़नगर, जिला-उज्जैन



# 250 फिल्मों में काम कर चुका एक्टर... अब बेटा भी है स्टार

तारीफ सुनकर बोले- अच्छा लगता है जब कोई...

जैकी श्रॉफ ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं। अपने अब तक के करियर में वह हर तरह के रोल निभा चुके हैं। उनके बेटे टाइगर श्रॉफ भी एक्टिंग की दुनिया का बड़ा नाम है। एक्टर का कहना है कि उन्हें अच्छा लगता है, जब उन्हें उनके बेटे के नाम से पुकारा जाता है।

युवा एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ की वजह से मिल रही पहचान को लेकर बॉलीवुड के फेमस और वरिष्ठ अभिनेता जैकी श्रॉफ ने कहा कि उन्हें अच्छा लगता है जब लोग उन्हें टाइगर का पिता कहते हैं। 67 वर्षीय एक्टर हाल ही में रणवीर अल्लाहबादिया के पॉडकास्ट में दिखाई दिए थे। जिन्हें बीयर बाइसेप्स के नाम से भी जाना जाता है। जैकी ने बताया कि टाइगर स्वास्थ्य, फुटबॉल और अच्छाई के बारे में बात करता है, जिससे बच्चे अच्छी चीजे सीखते हैं और अपनाते हैं।

## जैकी श्रॉफ ने की बेटे की जमकर तारीफ



अपनी बात रखते हुए रणवीर ने जब जैकी से पूछा कि जब भी मैं टाइगर से मिला हूँ तो मुझे एक बात समझ में आई है कि हमें अभी भी टाइगर श्रॉफ का सर्वश्रेष्ठ रूप देखना बाकी है। इसके जवाब में जैकी ने कहा, टाइगर अभी तो बच्चा है यार। वह अभी भी बड़ा हो रहा है, मेरे लिए अभी भी बहुत समय है। 42 साल हो गए हैं, मैं उसकी 10 साल की ग्रोथ देख सकता हूँ, मैं उसकी 20 साल की ग्रोथ देख सकता हूँ, उसे बस वही करना है, जो वह कर रहा है, उसे करते रहना चाहिए। वह इस उम्र में दुनिया का सबसे कम उम्र का एक्शन स्टार है।

## 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...



- अपील**
- किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
  - सही तौल एवं समय पर गुणतान पाएं।
  - नीलामी के समय किसान भाई अपने ढेर पर उपस्थित रहें।

सचिव • भार साधक अधिकारी  
कृषि उपज मंडी समिति खातेगांव, जिला-देवास

## 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...



सचिव • भार साधक अधिकारी  
कृषि उपज मंडी समिति, सैलाना, जिला-रतलाम

## 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...



- अपील**
- नीलामी के समय किसान भाई अपने ढेर पर उपस्थित रहें।
  - किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।

सचिव • भार साधक अधिकारी  
कृषि उपज मंडी समिति, दलौद, जिला-मंडसौर

## 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...



सचिव • भार साधक अधिकारी  
कृषि उपज मंडी समिति, पिपल्या, जिला-मंडसौर

## 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...



- अपील**
- नीलामी के समय किसान भाई अपने ढेर पर उपस्थित रहें।
  - किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
  - मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।

सचिव • भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, रतलाम

## 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...



- अपील**
- सही तौल एवं समय पर गुणतान पाएं।
  - मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय अपनी कृषि उपज आवश्यक रूप से दर्ज कराएं।

सचिव • भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, जावरा, जिला-रतलाम

आखिर को लैला की मां ने मंजूर कर लिया, कहा- अब लैला को मजनु के हाथ ही सौंप दूंगी!

सुनने वाले इस समाचार से खुश हो गए। लोगों ने लैला की मां को बधाइयां दीं। मजनु बिचारा कितनी मुद्दत से लैला के पीछे तड़प रहा था। आशिकी के कारण इस दुनिया और उस दुनिया दोनों जगह बदनाम हो गया था। मिट्टी भारी हो गई थी और प्राणों में केवल आह भर ही बच रही थी। चलो, लैला की मां का फैसला बड़ा अच्छा हुआ। आशिक-माशुक की जोड़ी मिल जाएगी। दोनों का भला होगा।

और उधर लैला की मां शादी का बजट बना रही थी- सत्तर गज कीम-खाब, एक सौ सत्तर गज तंजेब, सत्रह बोरे गेहूं, बीस बोरे चावल, पंद्रह कनस्तर घी!!...

बजट तो बन गया, पास-पड़ोस वालों ने उसे पास भी कर दिया, लेकिन सौदा कैसे मिले? लैला की मां ने बाजार में पहुंचकर देखा कि किराने वालों के यहां खरीददारों का मेला लगा हुआ है, किरासन तेलवाले अपनी-अपनी दुकानें बंद करके सो रहे हैं, बाजार की दुकानों में लाठियां चल रही हैं। यह जर्मन की लड़ाई क्या हुई कि आफत हो गई। लैला की मां घबरा गई। भीड़ के इस धक्के में हड्डी-पसली किसी का भी पता नहीं मिलेगा। या खुदा, अब क्या करूं?

सहसा अंधेरे में बिजली की चमक की तरह वहां मजनु दिखलाई दे गया। शादी की खुशी में वह अपने दोस्त के साथ सैर करने को निकला था। लैला की मां उसके पास पहुंचकर गिड़गिड़ाने लगी- शादी क्या हुई, मुसीबत हो गई; कोई भी जिन्स नहीं मिलती, बेटा! देखो, मदद करो; तुम्हारी ही शादी की चीजें हैं। शुक्रगुजार होऊंगी।

मजनु हक्का-बक्का। आंखें फाड़कर उसने पूछा- तुम चाहती हो कि इस भीड़ में घुसकर मैं गेहूं खरीद लाऊं?

हां बेटा, जियादा नहीं, फकत सत्रह बोरे! सत्रह बोरे! सुनते ही मजनु की आंखों के आगे सत्रह हजार सितारे नाचने लगे। आसमान को घूंसा मार आना आसान है, लेकिन सत्रह बोरे गेहूं खरीद सकना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। पसीने-पसीने होकर मजनु ने जवाब दिया- यह तो नामुमकिन है अम्माजान! तीन सेर का सवाल हो तो कहो; मैं लंगोट कसकर और लैला का नाम लेकर भीड़ में घुस जाता हूं और तीन सेर गेहूं खरीद लाता हूं।

लैला की मां ने कहा- लेकिन शादी की बात है, सत्रह बोरे से कम में काम नहीं चल सकता। मजनु ने आह भरकर जवाब दिया- अब शादी



हो या न हो, सत्रह बोरे गेहूं तो तुम्हें किसी हालत में नहीं मिल सकते।

मजनु के जवाब से लैला की मां की हिम्मत टूट गई। आंखों में आंसू भरकर बोली- तो क्या तुम चाहते हो कि गेहूं के चलते मैं तुम्हारे साथ लैला की शादी मंसूख कर दूं?

मजनु ने कहा- चाहता तो मैं नहीं, लेकिन लाचारी है!

तो यह शादी नहीं होगी?

शादी तो हो सकती है, लेकिन शादी में गेहूं नहीं होंगे।

मैं कहती हूं, गेहूं के बिना शादी नहीं हो सकती।

तो शादी मुश्किल है!

यानी तुम कुछ कर न सकोगे?

इस मामले में मैं कर ही क्या सकता हूं?

अब लैला की मां आंसू बहाती बाजार में खड़ी थी।

शहर के नामी गुंडे उस्मान की नजर उस ओर गई। लैला की मां के पास पहुंचकर वह उसके रोने का कारण पूछने लगा।

लैला की मां रोती गई, फफकती गई और कारण बताती गई। सब कुछ सुन लेने के बाद उस्मान ने कहा- इन सारी चीजों का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम जो-जो कहो, मैं सारी चीजें खरीद दूँ; लेकिन दुनिया में एक मजनु ही तो लड़का नहीं। मैं भी लैला के लिए कब से तरस रहा हूँ; लेकिन हाँ, उस मजनु की तरह चिल्ला-चिल्लाकर मुझसे आह नहीं भरी जाती। तो देखो, अगर लैला की शादी मेरे साथ कर सको...

और भीड़ को चीरकर उस्मान दुकानदार के पास पहुंच गया- क्यों सेट, लगाऊं दो रद्दे या देते हो सत्रह बोरे गेहूं?

दुकानदार ने घबरा कर कहा- सत्रह बोरे!

हां-हां, सत्रह से लेकर सत्रह सौ बोरे तक गेहूं तुम्हें देना पड़ेगा, समझ रखो, वर्ना तुम हो और मैं हूँ!

दुकानदार उस्मान के कान में जाकर फुसफुसाने लगा- भाई, तुम्हें जो-जो चीजें चाहिए, उनकी लिस्ट देते जाओ। सारी जिन्स जहां तुम कहो, पहुंचवा दूंगा। दाम के लिए भी कोई बात नहीं। हाँ!

और गेहूं, गल्ला, कपड़े, किरासन सब ठेले पर लद-लदकर लैला की मां के दरवाजे पर पहुंचने लगे।

अब आज के समाचार-पत्र में पढ़ रहा हूँ कि लैला की शादी उसी उस्मान से होने वाली है। मजनु बेचारा निराश होकर मिलिट्री में भर्ती हो गया।

● राधाकृष्ण

अपील

सभी किसान भाई मुख्यमंत्री हममाल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।

78वें स्वतंत्रता दिवस

की शुभकामनाओं सहित...

सचिव • भारत साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, आगरा, जिला-शाजापुर

अपील

मंडी प्रांजण में प्रवेश करते समय अपनी कृषि उपज आदर्यक रूप से दर्ज कराए।

मुख्यमंत्री हममाल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।

सही तौल एवं समय पर मुगतान पाए।

78वें स्वतंत्रता दिवस

की शुभकामनाओं सहित...

सचिव • भारत साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, शुजालपुर, जिला-शाजापुर

अपील

सभी किसान भाई मुख्यमंत्री हममाल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।

78वें स्वतंत्रता दिवस

की शुभकामनाओं सहित...

सचिव • भारत साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, तराना, जिला-उज्जैन

**mycem**  
cement

HEIDELBERGCEMENT

**mycem power**

Trusted German Quality  
Over 150 Years



Send 'Hi'  7236955555

INDIA

INDEPENDENCE

DAY



For Any Medical &  
Pathology Equipments  
Contact Us

## D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA<sub>1c</sub>, HbA<sub>2</sub> and HbF

### Flexible

to solve more testing needs

### Comprehensive

B-thalassemia and  
diabetes testing

### Easy

for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; it's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA<sub>1c</sub> or HbA<sub>1c</sub>/FIA<sub>c</sub> testing using primary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps. With the D-10™ System, it's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

# SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

📍 C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023  
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 ✉ Email : shbple@rediffmail.com  
☎ Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687